



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2014/ज्येष्ठ 5, 1936

No. 277]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2014/JYAISTHA 5, 1936

महानिदेशक रक्षोपाय

(सीमा-शुल्क एवं उत्पादकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2014

विषय : एकल, सम्मिश्रण एवं अमिश्रित सहित सी 8, सी 10, सी 12- सी 14, सी 16, और सी 18 की लंबाई के कार्बन शृंखला युक्त (जिनमें शाखायुक्त आईजोमर्स शामिल नहीं हैं) जिसमें सी 12 – सी 14, सी 12 – सी 16, सी 12 – सी 18, सी 16-18 और सी 14 – सी 16 (सामान्यतः सी 12 – सी 14 के रूप में प्रवर्गीकृत) कार्बन शृंखला लंबाई के संयोजन के ब्लेंड शामिल हैं "अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों", जिन्हें एतद्वारा "पीयूसी" (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है, का भारत में आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच-प्रारंभिक जांच परिणाम

सा.का.नि. 357 (अ).—सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसका सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997, को ध्यान में रखते हुए

(क) प्रक्रिया

1. सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतदपश्चात् "रक्षोपाय नियमावली" कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत मैसर्स वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई, एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई ने एकल, सम्मिश्रण एवं अमिश्रित सहित सी 8, सी 10, सी 12, सी 14, सी 16, और सी 18 की लंबाई के कार्बन शृंखला युक्त (जिनमें शाखायुक्त आईजोमर्स शामिल नहीं हैं) जिसमें सी 12 – सी 14, सी 12 – सी 16, सी 12 – सी 18, सी 16-18 और सी 14 – सी 16 कार्बन शृंखला लंबाई के संयोजन के ब्लेंड शामिल हैं (सामान्यतः सी 12 – सी 14 के रूप में प्रवर्गीकृत) अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों", जिन्हें एतद्वारा "पीयूसी" (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है, का भारत में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की मांग करते हुए एक आवेदन-पत्र याचिका में यथाप्रदर्शित यह आरोप लगाते हुए मेरे समक्ष दायर किया है कि इस "पीयूसी" के संबंधित आयात घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित कर रहे हैं और/या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, और जिसमें उन्होंने भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के संबंधित आयातों द्वारा कारित बाजार विकृति या बाजार विकृति की चुनौती से घरेलू उत्पादक की रक्षा करने की मांग की है।

2. इस बात से संतुष्ट होते हुए कि नियम 5 की अपेक्षाएं पूरी होती हैं, इस "पीयूसी" के आयातों के विरुद्ध दिनांक 13 फरवरी, 2014 के जांच शुरुआत नोटिस, जिसे उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के तहत एक रक्षोपाय जांच प्रारंभ की गई थी।
3. दिनांक 13 फरवरी, 2014 के इस जांच शुरुआत नोटिस की एक प्रति तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति संबद्ध कार्य देखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को नई दिल्ली में स्थित राजदूतावासों और अधोलिखित सूचीबद्धगत हितवद्ध पक्षकारों को प्रेषित की गई :

3.1 निर्यातक

- (1) **एमरी ओलियोकैमिकल्स**, लेवल 5, बिल्डिंग-ई, पिरेम्बा स्क्वेयर, सौजना रिसार्ट, सेक्सन यू2 40150 शाह आलम सेलान्गोर मलेशिया
- (2) **विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड**, 56 नील रोड, सिंगापुर 08883
- (3) **पी एंड जी कैमिकल्स** प्राकटर एंड गैम्बल इंटरनेशनल आपरेशन्स एसए सिंगापुर ब्रांच, 238ए थामसन रोड #20-01/10 नोवेना स्क्वेयर टावर ए, सिंगापुर 307684
- (4) **सासोल लिमिटेड**, सासोल जर्मनी जी एम बी एच एंक्लैम्सप्लैट्स 120537 हैम्बर्ग
- (5) **के एल के ओलियो** लेवल 8, मेंनारा के एल के, नम्बर 1, जालान पीजेयू 7/6 मुटियारा दामनसारा, 47810 पेटालिंग जाया, सेलानगर दारूल अहसान, मलेशिया
- (6) **मुसिम मास** पीटी मुसिम मास जे1 केएल याससुदर्शो केएम7, 9 तोन्जुंगमुलिया मेडान 20241, उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया
- (7) **इकोग्रिन ओलियोकैमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड**, 99, बुकित तिमह रोड #03-01 अल्फा सेंटर, सिंगापुर 229835
- (8) **एफपीजी ओलियोकैमिकल्स एसडीएन-बीएचडी**, एफपीजी ओलियो कैमिकल्स, एसडीएन बीएचडी (184896-यू) लाट 3831, कौन्टान पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, तान्जुंग गेलांग, पीओ बॉक्स 26, पेजाबट पास बैलाक, 26080 कैन्टन, पेहांग दारुलमाक्मर, मलेशिया
- (9) **काओ कारपोरेशन**, पिलिपिनास काओ, इंक, एक काओ ग्रुप कंपनी, 7वां तल, टावर वन एवं एक्सचेंज प्लाजा आयाला ट्राइंगल आयाला एवेन्यू, 1226 मकती सिटी, फिलीपीन्स
- (10) **थाई ओलियोकैमिकल्स कंपनी लिमिटेड**, 123 सनटावर्स बिल्डिंग ए, 14वां विभावाड़ी रंगसिट रोड, चामफोन, चाटुचाक बैंकाक 10900 थाईलैंड
- (11) **टेक गुआन**, टेक गुआन (चीन) लिमिटेड, संख्या 1, टेक गुआन रोड, रूगाओ पोर्ट इकानामिक डेवलपमेंट जोन रूगाओ, जियांगसु प्राविन्स, चीन 226532
- (12) **आक्सिटेनो** एवेनिडा ब्रिगैडिआइरो लुइस एंटानिओ, 1343 बेला विस्टा -सीईपी 01317-910, साओ पाउलो - एसपी - ब्राजील
- (13) **बीएएसएफ/कागनिस**, हेन्केलस्ट्रास्सी 6740551, डसेलडार्फ नार्डरहिन - वेस्टफालेन जर्मनी

3.2 प्रमुख आयातक/भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रयोक्ता

- (1) **गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स लिमिटेड**, सी 49/2, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, पावनी नवी मुंबई, महाराष्ट्र 400703
- (2) **विश्वट कैमिकल्स लिमिटेड**, "विश्वट" 7 सतसंग काम्प्लेक्स अपर गोविंद नगर, एलएस राहेजा मार्ग, मालाड (पूर्व) मुंबई-400097
- (3) **रोडिया स्पेशियलिटी कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड**, फीनिक्स हाउस "ए/बी" विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग लोअर परेल (पश्चिम) मुंबई, 400013
- (4) **इंडियन ग्लायकोल लिमिटेड**, 2 बी सेक्टर 126, नौएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201304
- (5) **स्टर्लिंग आक्जिलरीज प्राइवेट लिमिटेड**, 30/31, मारोल कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, एमवी रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400059
- (6) **मातंगी इंडस्ट्रीज**, प्लाट संख्या 28, फेज 1 निल्सिन इंडस्ट्रीज के पीछे, जीआईडीसी, वात्वा, अहमदाबाद 382445, गुजरात
- (7) **वीनस इथाक्सीलेट्स प्राइवेट लिमिटेड**, प्लाट संख्या 109-111 बिचोलिम इंडस्ट्रियल एस्टेट, बिचोलिम, गोआ-403529

- (8) गुजरात कैमिकल्स, 111, जलनिधि काम्प्लेक्स, बहुमाली भवन के पीछे, नानपुरा सूरत-1
- (9) आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 71 उद्योग क्षेत्र, द्वितीय तल, मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड, मुलुंड (पश्चिम) मुंबई - 400080
- (10) कुशा कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 101, वरूण अपार्टमेंट दत्तात्रेय रोड, सांताक्रूज (पश्चिम) मुंबई -400054
- (11) कृष्णा एंटीआक्सीडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, 1 लोपाज मैनार, मुंबई-400013

3.3 घरेलू उत्पादक

- (1) वी वी एफ (इंडिया) लिमिटेड, (घरेलू उद्योग) 109, सायन (पूर्व), मुंबई-400022
- (2) गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिरोशनगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली, मुंबई-400079

3.4 राजदूतावास का नाम और पता

- (1) फिलिपीन्स का राजदूतावास, माननीय (श्री) बेनितो बी. बालेरिआनो राजदूत 50-एन, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली -110021
- (2) बेल्जियम का राजदूतावास, टी सी जी फाइनेंशियल सेंटर, 7वां तल, सी 53, जी ब्लाक, बांद्राकुर्ला काम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400051/50 एन, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (3) यूएसए का राजदूतावास, यूएस का राजदूतावास, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (4) यूके का राजदूतावास, नीति मार्ग, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (5) यूएई का राजदूतावास, 12 चंद्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 (भारत)
- (6) स्विटजरलैंड का राजदूतावास, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (7) पोलैंड का राजदूतावास, 50 एम, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (8) सिंगापुर का राजदूतावास ई-6, चंद्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (9) नीदरलैंड का राजदूतावास, "फोर्क्स बिल्डिंग" प्रथम तल, चरणजीत राय मार्ग, मुंबई-400001/6/50 एच, शांतिपथ, कौमी क्रुमाह मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (10) इटली का राजदूतावास, 50 ई, चंद्रगुप्त मार्ग, नई दिल्ली-110021
- (11) फिनलैंड का राजदूतावास, ई-3, न्यायमार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (12) फ्रांस का राजदूतावास, 2/50 ई, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (13) फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का राजदूतावास, पोस्ट बाक्स नम्बर 613, नई दिल्ली-110001
- (14) चीन का राजदूतावास, 50डी, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (15) इंडोनेशिया का राजदूतावास, 9 अल्टामाउंट रोड, कुम्बाला हिल, मुंबई -400026/ 50 ए, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021
- (16) थाईलैंड का राजदूतावास, डी-1/3, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
- (17) मलेशिया का राजदूतावास, 50 एम, सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

4. उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य देशों के सभी ज्ञात निर्यातकों, भारत के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावलियां इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे इस जांच शुरुआत नोटिस के 30 दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत करा दें।

5. हितबद्ध पक्षकार के रूप में विचार किए जाने के लिए निम्नलिखित से अनुरोध प्राप्त हुआ तथा उसे स्वीकार कर लिया गया ।

5.1 जांच शुरुआत नोटिस जारी होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि के अंदर नवीन हितबद्ध पक्षकार

1. श्री मोहम्मद राशी अब्दुल रज्जाक (निदेशक) ट्रेड पैकिटसेस सेक्सन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय, लेवल-140, ब्लॉक 8, सरकारी कार्यालय काम्प्लेक्स, जालान डुटा 50622 कुआलालम्पुर, मलेशिया ई-मेल : alltps@miti.gov.my
2. मैसर्स मेजरहब ओलियो कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 10वां सिद्धिविनायक अपार्टमेंट्स, चौथा तल, सोसायटी रोड, जोगेश्वरी पूर्व मुंबई-400060, ई-मेल : majorhubindia@vsnl.net
3. मैसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड (एचयूएल) यूनीलीवर हाउस, बी डी सावंत मार्ग, चकाला, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400099

4. मैसर्स चान पेक वान, सचिवालय, कैमिकल इंडस्ट्रीज काउंसिल आफ मलेशिया, मलेशिया ओलियोकैमिकल मैन्यूफैक्चरर्स ग्रुप (एम ओ एम जी) विस्मा एफएमएम, संख्या 13, पेरिसियासन डैगांग, पीजेयू 9, बंदर श्री दमामसारा 52200 कुआलालम्पुर मलेशिया, ई-मेल : pek_wan@FMM.ORG.MY
5. मैसर्स पैन ओलियो इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, 309,10,11 आदित्य बनारसी हैरिटेज, माइन्ड स्पेस, आफ लिंक रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई-400064, ई-मेल : panoleo@panoleo.com
6. श्री मनोज झा, मैसर्स यूनिडस, ई-मेल : manoj@unidusononline.com
7. भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधिमंडल, ब्लाक 50ई, न्यायमार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, ई-मेल : rusintrade@mail.ru
8. मैसर्स पीटी इकोग्रीन ओलियो कैमिकल्स, इंडोनेशिया, पीओ बॉक्स 1010, नागोया प्लाजा, बाताम, आईलैंड, 29432, इंडोनेशिया, ई-मेल : info.batam@ecogreenoleo.com
9. व्यापार एवं आर्थिक प्रभाग, भारत में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल 65, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली -110003 – ई –मेल : chaitanya.kaushal@eeas.europa.eu
10. मैसर्स काविनकेयर प्राइवेट लिमिटेड, 12, सेन्टोफा रोड, तेयनाम्पेट, चेन्नई-600018
11. विदेश व्यापार महानिदेशालय, जालान, एम 1, रिदवान रायस संख्या 5, जकार्ता 10110
12. मैसर्स रत्नसागर हर्वल्स प्राइवेट लिमिटेड
13. मैसर्स इमामी लिमिटेड, 687, आनंदपुर ई एम बाईपास, कोलकाता – 700107-ई-मेल : sapan.barik@emamigroup.com
14. मैसर्स थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड, 555/1, एनर्जी काम्प्लेक्स, बिल्डिंग ए, 15वां तल, विभावाडी रंगसिट रोड, चाटुचाक, बैंकाक, 10900, थाईलैंड
- 5.2 मैसर्स पीटी मुसिम मास, इंडोनेशिया ने समयवृद्धि का अनुरोध किया जिससे कि वह अपना उत्तर प्रस्तुत कर सके।
- 5.3 विहित अवधि के अंदर जांच पूरी करने के लिए समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने हेतु अनुरोध पर रक्षोपाय नियमावली, 1997 के नियम 6(4) के अनुसार समय विस्तार करने की अनुमति दे दी गई।
- 5.4 आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का घरेलू उत्पादक के संयंत्र का स्थल दौरा करके सत्यापन किया गया। इस सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।
- 5.5 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त किए गए सभी विचारों को समुचित निर्धारण करते समय ध्यान में रखा गया। प्राप्त या अधिप्राप्त सूचना का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया।

(ख) घरेलू उत्पादक (आवेदक) के विचार

6. **घरेलू उद्योग :** मैसर्स वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई, एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई ने दावा किया कि उनका उत्पादन इस "पीयूसी" का देश में होने वाले कुल उत्पादन का 63 प्रतिशत बनता है और यह देश में इस विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का बड़ा भाग बनता है और इस प्रकार वर्तमान याचिका दायर करने का उनका पूरा आधार है। आवेदक के अलावा इस संबद्ध वस्तु का उत्पादन मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई द्वारा भी किया जा रहा है, जो इस आवेदनपत्र का समर्थन करते हैं।
7. **अंतर्गस्त उत्पाद :** वसीय अल्कोहल्स अलिफैटिक अल्कोहल होते हैं तथा यह अनुविद्ध एवं अननुविद्ध रूपों में प्राप्त होते हैं। अल्कोहलों को समूहबद्ध किया जा सकता है और इनकी सबसे सामान्य लंबाई सी 12, सी 14 और उनका सम्मिश्रण होता है। इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन प्राकृतिक वसा एवं तेलों, अधिकांशतः नारियल और पाम गिरी का तेल, का संपरिवर्तन करके मिथायल ईस्टर या वैक्स ईस्टर का रिडक्शन करके किया जाता है। यह प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया के रूप में, वेजिटेबल आयल्स जैसे अपरिष्कृत पाम गिरी का तेल, का उच्च ताप एवं दाब पर विखंडन करके, प्रारंभ की जाती है। वेजिटेबल आयल्स/फैट्स (अखाद्य) मूलतः फैटी एसिड्स का ट्रिग्लायसेराइड होते हैं, जिसे हाइड्रोलायसिस प्रतिक्रिया करके वसीय अम्लों एवं ग्लायसेरोल में परिवर्तित किया जाता है जिसे सामान्य भाषा में वसा विखण्डन कहा जाता है। तब इन अपरिष्कृत वसीय अम्लों का उच्च ताप एवं निर्वात में सादा/ विखंडित आसवन किया जाता है, फिर इसका प्रलवणन (ईस्टरीफिकेशन) किया जाता है जो वसीय अम्ल और वसीय अल्कोहल के बीच, इनर्ट वातावरण में, वैक्स ईस्टर बनाने के लिए प्रतिक्रिया का एक परिणाम होता है। फिर विशुद्ध मोम प्रलवण का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है जो फिक्सड वेड कापर कैटालिस्ट की मौजूदगी में घटित होता है और उससे अपरिष्कृत फैटी अल्कोहल बनता है। फिर इसका आसवन एवं परिशुद्धीकरण किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद की बिक्री फ्लेक्स, चूसिका (पैस्टिल्स) और द्रव रूप में की जाती है।

8. आवेदक ने 4 वर्षों की अवधि के लिए आयात एवं क्षति संबंधी आंकड़े दायर किए हैं। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 (दिसम्बर 2013) तक के तिमाहीवार आंकड़े प्रदान कराए हैं जिनके आधार पर जांच शुरुआत का नोटिस जारी किया गया। तथापि, घरेलू उद्योग ने दिनांक 21.04.2014 और दिनांक 15.05.2014 के पत्र के तहत अतिरिक्त सूचना भी प्रस्तुत की जिसमें जनवरी 14 से अप्रैल 14 तक की अवधि के लिए आयातों एवं अन्य आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित सूचना का उल्लेख था। उसने इसमें अपनी शोचनीय स्थिति का वर्णन किया था और इस विचाराधीन उत्पाद पर तत्काल अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध किया था, और यह कहा गया था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो बढ़ते आयातों के कारण उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि उसमें सुधार होना मुश्किल हो जाएगा।

9. याचिकाकर्ता ने अपने रक्षोपाय आवेदन में अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध किया था। इस विचाराधीन उत्पाद के संबंधित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में प्रपाती पतन और बाजार विकृति की चुनौती के मद्देनजर अंतरिम उपाय करना आवश्यक हो गया है। घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद में कटौती करने के लिए मजबूर किया गया है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में आयातों के उद्रेक द्वारा कारित बिक्री में गिरावट को देखते हुए अत्यधिक अभिनव अवधि में प्रपाती रूप से कमी आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में भारी वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को इस विचाराधीन उत्पाद के प्रचालनों के कारण वित्तीय घाटा हो रहा है।

10. गंभीर परिस्थितियों के आलोक में, आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि रक्षोपाय साधन के अनुप्रयोग में थोड़ा सा भी विलंब करने से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के रूप में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें जिससे कि घरेलू उद्योग को होने वाली अपूरणीय क्षति से बचाया जा सके। अनंतिम रक्षोपाय शुल्क उदग्रहण करने के लिए विपरीत परिस्थितियों की मौजूदगी के संबंध में अपने तर्क के समर्थन में घरेलू उद्योग ने अप्रैल, 2014 तक के आंकड़े अर्थात् (वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक की अवधि के लिए) वार्षिक रूप से और वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही एवं वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही (अप्रैल 14 के आंकड़े वार्षिकीकृत) के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ताकि वह बढ़ते आयातों के कारण उनकी पहले से ही बदतर हुई आघातन को न्यायोचित ठहराया जा सके।

क. विधिक प्रावधान

क1. गाट 1994 के अंतर्गत रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 6 प्रावधान करता है कि "गंभीर परिस्थितियों में जहां विलंब करने से ऐसी क्षति हो सकती है, जिसमें सुधार करना दुष्कर हो जाए तो कोई सदस्य, इस प्रारंभिक निर्धारण के अनुसरण में कि इस बात के स्पष्ट साक्ष्य हैं कि आयातों में वृद्धि ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की है या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है, अनंतिम रक्षोपाय साधन का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अनंतिम शुल्क के लिए आधारभूत अपेक्षा निम्नलिखित है :

संबंधित आयातों का साक्ष्य, इन आयातों से गंभीर क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न हो रही हो और ऐसी गंभीर परिस्थितियां मौजूद हो गई हो, जहां विलंब करने से ऐसी क्षति होगी जिसमें सुधार करना दुष्कर हो जाए।

ख. संबंधित आयात

ख1. वसीय अल्कोहलों का आयात उच्च स्तर पर हुआ है और यह लगातार बढ़ता रहा है। आयात का विवरण निम्नलिखित है :

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
आयात (एमटी)	19843	34142	51055	57616	
प्रवृत्ति	100	172	257	290	

ख2. घरेलू उत्पाद के संबंध में आयात : घरेलू उत्पाद के संबंध में भी आयातों में भारी वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता के घरेलू उत्पादन (अर्थात् निर्यात को घटाकर उत्पादन) के संबंध में आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2010-11 में 60 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 214 प्रतिशत हो गई। संपूर्ण अवधि के दौरान, घरेलू उत्पादन के संबंध में आयातों में सतत वृद्धि हुई है।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात	60%	118%	226%	247%
प्रवृत्ति	100	195	375	412

ख2.1 उत्पादन (निर्यात हित) के संबंध में आयात :

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात	29%	69%	75%	62%
प्रवृत्ति	100	237	260	213

ख 2.2 कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में भी आयातों में वृद्धि हुई है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात	अखिल भारतीय उत्पादन	निर्यात को घटाकर अखिल भारतीय उत्पादन	कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात का प्रतिशत	कुल भारतीय घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात प्रतिशत
2010-11	19843	118582	43338	17	46
2011-12	34142	96344	57145	35	60
2012-13	51055	112613	31046	45	164
2013-14	57616	142350	35951	40	160

ग. घरेलू उद्योग को कारित गंभीर क्षति

ग1. घरेलू बाजार में आयातों का हिस्सा

मांग या खपत में आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 44 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2013-14 में 72 प्रतिशत हो गया। आयातों का बाजार हिस्सा निम्नवत था।

ग2. वर्ष 2010-11 में घरेलू उत्पादन और आयातों के बीच बाजार का समान वितरण था और भारतीय उद्योग का बाजार पर 50 प्रतिशत से अधिक आधिपत्य था। वर्ष 2011-12 में आयातों की बाढ़ सी आ गई और आयातों ने 61 प्रतिशत से अधिक बाजार पर अपनी पकड़ बना ली। जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है आयातों में वर्ष 2011-12 से निरंतर वृद्धि हो रही है और इस समय उनकी बाजार में हिस्सेदारी 72 प्रतिशत से अधिक बाजार पर है।

वित्तीय वर्ष	कुल आयात	घरेलू उद्योग की बिक्री	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	कुल मांग	बाजार हिस्सा	
					घरेलू उद्योग	आयात
2010-11	19843	17080	8242	45165	38%	44%
2011-12	34142	15285	6677	56104	27%	61%
2012-13	51055	12891	7573	71519	18%	71%
2013-14	57616	14776	8088	80480	18%	72%

ग3. दूसरी ओर, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में निरंतर गिरावट आई, जो वर्ष 2010-11 में 38 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2013-14 में 18 प्रतिशत रह गया।

ग4. बिक्री के स्तर में परिवर्तन

याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियों की प्रवृत्ति में निम्नवत है :

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	17080	15285	12891	14776
प्रवृत्ति	100	89	75	86

ग5. घरेलू उत्पादन

ग5.1 याचिकाकर्ता का घरेलू उत्पाद (निर्यात को घटाकर उत्पादन) निम्नवत है :

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उत्पादन	33319	28974	22560	23303
प्रवृत्ति	100	87	68	70

ग5.2 उत्पादन (निर्यात सहित उत्पादन) :

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन (निर्यात सहित)	68605	49585	67837	93297
प्रवृत्ति	100	72	99	136

ग5.3 उभरती हुई बाजारों में बढ़ती मांग को आयातों द्वारा पूरा किया गया है। मांग में इस वृद्धि से घरेलू उद्योग को कोई लाभ नहीं हुआ है।

ग6. उत्पादकता

क्षति के लिए इस कारक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। कर्मचारियों में वृद्धि को विखंडन संयंत्र, वसीय अम्ल प्रभाजन संयंत्र, ग्लिसरीन संयंत्र और ग्राही विद्युत संयंत्र के प्रतिष्ठापन के साथ संबद्ध की जा सकती है, जिसका लाभ उपचित होना अब शुरू हो गया है। इसे विकसित उत्पादकता स्तर से देखा जा सकता है जो 186 से बढ़कर 205 हो गया है।

ग7. ग्राही उपयोग

क्षमता उपयोग में भी भारी गिरावट आई है

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
क्षमता उपयोग प्रतिशत	28	24	19	19
प्रवृत्ति	100	87	68	68

ग8. लाभ एवं हानि

घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्ष 2011-12 और 2012-13 में पूर्णतया अपक्षरण हो गई। लाभप्रदायकता निम्नलिखित तालिका में दर्शायी जा रही है :

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
लाभ/हानि	745	-1982	-20829	-14151
प्रवृत्ति	100	-266	-2796	-1900

*वाईटीडी फरवरी, 2014

वर्ष 2011-12 से घरेलू उद्योग की स्थिति में तेजी से गिरावट आई है और बाजार के आकार में वृद्धि के बावजूद, यह अपनी लागत को पुनप्राप्ति करने में असमर्थ रहा। समान वस्तु का उत्पादन पूर्णतया अर्थक्षम नहीं रहा क्योंकि घरेलू उद्योग को निरंतर घाटा होता रहा।

ग9. रोजगार

इस यूनिट में रोजगार जो वर्ष 2010-11 में 100 था, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़कर 124 (अनुक्रमित) हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः स्प्लिटिंग संयंत्र, फैटी एसिड फ्रैक्शनल प्लांट, ग्लिसरीन प्लांट में विस्तार करने और ग्राही विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के कारण हुई है जिसके लाभ अभी उपचित होना प्रारंभ हो गए हैं। इसे विकसित उत्पादकता स्तर से देखा जा सकता है।

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
रोजगार अनुक्रमित	100	109	119	124
उत्पादकता (एमटी/रोजगार)	100	66	83	110

घ. क्षति की चुनौती आसन्न है

घ1. सभी संगत पैरामीटर घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, यदि शुल्क का अधिरोपण अविलंब नहीं किया जाता है तो अपूरणीय क्षति कारित की जाती रहेगी। गंभीर क्षति कारित की गई है, जैसाकि उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है। गंभीर क्षति की चुनौती आसन्न है, क्योंकि याचिकाकर्ता की स्थिति में भारी समग्र परिक्षण हुआ है।

घ2. वसीय अल्कोहलों का वर्ष 2011-12 से भारी मात्रा में आयात जारी रहा। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आ रही है और उसे भारी घाटा हो रहा है। याचिकाकर्ता की अतिजीविता भी खतरे में है क्योंकि और अधिक गंभीर क्षति की चुनौती आसन्न है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई गंभीर क्षति तथा आयातों के बीच कारणात्मक संबंध

ड.1 आयातों तथा घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति के बीच स्पष्ट संबंध है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में आयात उच्चतम सीमा पर थे। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार में हिस्सेदारी, लाभप्रदायकता, निवेश पर अर्जन, घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान जब आयात अपनी उच्च सीमा पर थे तब, याचिकाकर्ता की स्थिति में बहुत अधिक गिरावट आई।

ड.2. कतिपय स्रोतों से वसीय अल्कोहलों के आयातों पर शुल्क को दिनांक 01.01.2014 से हटा लिया गया है। इस कमी को प्रत्याशा में तीसरी तिमाही में आयातों में गिरावट आई। इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता अपने ग्राहकों को अपने पक्ष में रखने में समर्थ रहा। सीमा शुल्क हटा लिए जाने के पश्चात वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में आयातों में भारी वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग की स्थिति में और भी अधिक गिरावट आ गई। वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के बीच तुलना निम्नलिखित को अभिव्यक्त करती है :

2013-14	Q1	Q2	Q3	Q4
आयात (एमटी)	12408	13872	13162	18176
प्रवृत्ति	100	112	106	146
कुल घरेलू उत्पाद के संगत रूप में आयात (प्रतिशत) (अनुक्रमित)	100	125	121	192
उतराई मूल्य (रुपए/एमटी)	81924	94944	102154	102800
प्रवृत्ति	100	116	124	125
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (शुल्क सहित) (रुपए/एमटी) (अनुक्रमित)	100	109	119	131
कीमत अधोरदन	100	-120	-63	306
उत्पादन लागत (रुपए/एमटी) (शुल्क के बिना)	100	99	112	132
निवल लाभ/हानि (रुपए/एमटी)	-100	-35	-69	-128

ड.3. उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में पिछली अवधि की तुलना में पिछली में भारी गिरावट आई है। तीसरी तिमाही में मामूली से सुधार का प्रभाव चौथी तिमाही में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।

ड.4. इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि गंभीर क्षति कारित की गई है और इससे अधिक गंभीर क्षति की चुनौती आसन्न है। आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधी भी स्थापित हो गया है।

च. क्षति कारित करने वाले अन्य कारकों की मौजूदगी न होना

च1. अन्य कोई ऐसे कारक नहीं हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो। वसीय अल्कोहलों की मांग में पिछले तीन वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है। मांग में लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग बाजार में हुई इस वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पादन, बिक्री या लाभ में वृद्धि नहीं कर सका।

च2. याचिकाकर्ता एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है इसके कारण से इसे डीटीए इकाइयों से प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त हो रहा है। कच्चे माल (पी के ओ) जैसे पाम गिरी आयल (जो यथामूल्य 7.5 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की रेंज में होता है) पर लगा सीमाशुल्क परिष्कृत उत्पाद पर लागू शुल्क की तुलना में बहुत अधिक होता है। चूंकि एक निर्यातोन्मुख इकाई कच्चे माल (पाम गिरी आयल) का आयात शुल्कों का भुगतान किए बिना कर सकती है और अपने परिष्कृत उत्पाद की निकासी 7.725 प्रतिशत की दर, (जो अब 18 फरवरी, 2014 से 3.86 प्रतिशत हो गया है), से शुल्क का भुगतान करके कर सकता है, इसलिए निर्यातोन्मुख इकाई पर लागू निवल शुल्क आयातित सामग्री से वसीय अल्कोहलों का विनिर्माण करने वाली डीटीए यूनिटों द्वारा दिए जा रहे शुल्क की तुलना में बहुत कम होता है। डीटीए इकाइयों को कच्चे माल पर सीमा शुल्क का भुगतान करना होता है, जिससे उनकी लागत में भारी वृद्धि हो जाती है। इसलिए, घरेलू इकाई के लिए निवल शुल्क ई ओ यू इकाइयों के शुल्क की तुलना में बहुत अधिक होता है।

च3. यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में डीटीए और ईओयू इकाइयों को समान स्थान पर रखा गया है। पीकेयू कुल उत्पादन लागत का लगभग 2/3 होती है। चूंकि पाम गिरी आयल भारत में, वाणिज्यिक मात्रा में, उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इस कच्चे माल का आयात किए जाने की जरूरत होती है और यह दोनों प्रकार की इकाइयों को समरूप या समान आयात कीमत पर उपलब्ध होता है। इसकी संपरिवर्तन लागत भी भिन्न नहीं होती है। तथापि, शुल्क ढांचा निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए फायदे मंद है, क्योंकि कच्चे माल पर शुल्क सामान्यतः 100 प्रतिशत होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई डीटीए यूनिट 70 रुपए मूल्य के कच्चे माल का आयात करता है तो उसे 70 रुपए शुल्क देना पड़ता है, जबकि निर्यातोन्मुख इकाई को यह कच्चा माल छूट लाभ के अंतर्गत किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान किए बिना प्राप्त होता है। इसी तरह, एक निर्यातोन्मुख इकाई से निकासी किया गया समान उत्पाद जिसपर 7.725 प्रतिशत प्रभारित किया जाता है जो 8 रुपए से 10 रुपए की रेंज में होता है। इस प्रकार निर्यातोन्मुख इकाइयों का निवल शुल्क डीटीए इकाइयों के लिए निर्धारित शुल्क से बहुत कम होता है। ईओयू द्वारा डीटीए क्लीयरेंस के लिए लागू शुल्क में और अधिक कमी करके उसे 3.86 प्रतिशत कर दिया गया है।

च4. खपत की प्रणाली में भी कोई परिवर्तन नहीं है, जिससे यह सुझाव मिलता हो कि यह क्षति इन्हीं कारकों द्वारा पहुंचाई जा रही है। किसी भी मामले में, यह जरूरी नहीं है कि आयात क्षति का प्रमुख कारक हो, बशर्ते कि इसे इस तरह दिखाया जा सके कि वह क्षति का एक कारक है।

च6. वर्तमान मामले में, ऐसी कोई अन्य परिस्थितियां या कारक नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई जा रही हो और कारणात्मकता की जरूरत पूर्णतया पूरी होती है।

छ. समालोचनात्मक परिस्थितियां

छ 1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिक निर्धारण के लिए यह एक सबसे अच्छा मामला है, यह कि आयातों को बढ़ोतरी से गंभीर क्षति पहुंचाई गई है और इससे भविष्य में भी गंभीर क्षति पहुंचाई जाने की चुनौती उत्पन्न हो रही है।

छ 2. आयातों में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक लगभग तीन गुना बढ़ोतरी हो गई। यहां तक कि घरेलू उत्पादन के संबंध में भी, आयातों में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 44 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2013-14 में 72 प्रतिशत हो गया। मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत आने वाले स्रोतों से आयातों पर शुल्क हटा लेने के परिणामस्वरूप इन आयातों में और अधिक बढ़ोतरी होगी। घरेलू उद्योग अव्यवहार्य स्तर पर प्रचालन कर रहा है और उसे उसके उत्पादन की प्रत्येक अगली इकाई पर घाटा हो रहा है।

छ 3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयातों में यह उद्रेक घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत से भी कम कीमतों पर हो रहा है। वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में आयातित वस्तु का उतराई मूल्य 102800/-रुपए था जबकि वीवीएफ की घरेलू बिक्री कीमत 110520/-रुपए थी। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में और इस वस्तु का उत्पादन करने तथा भारतीय बाजार में उसकी बिक्री करने में तेजी से गिरावट आ रही है।

छ 4. इन मदों के आयात पर ईयू द्वारा भी पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, दक्षिण पूर्व एशिया में ये विनिर्माता अपनी मालसूची का, भारत सहित, अन्य बाजारों की ओर अंतरण कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख उत्पादक देशों में उनके उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग बहुत कम है। इसमें से उत्पादन के अधिकांश भाग की बिक्री एशियाई देशों में, खासकर भारत में, करने का इरादा होता है।

छ 5. यह तथ्य कि इन देशों से आयातों में एफटीए के अंतर्गत शुल्क को भी दिनांक 01.01.2014 से हटा दिया गया है, इससे भी इस वस्तु का विपथन की अन्य बाजारों से भारत की ओर हो रहा है और आयातों की इस वृद्धि के प्रभाव को दूर करने के लिए किसी अनंतिम शुल्क का उदग्रहण करने की तत्काल आवश्यकता है। इन्हीं हालातों में, यूरोपीय काउंसिल ने कतिपय स्टील उत्पादों के आयातों पर अनंतिम उपाय का अधिरोपण किया है।

छ 6. कतिपय स्रोतों से आयातों पर सीमा-शुल्क को हटाने से घरेलू उद्योग की स्थिति पहले से ही बहुत कमजोर थी। निरंतर वृद्धि से इसमें तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की जरूरत महसूस होती है, और ऐसा न करने याचिकाकर्ता को अपूर्ण क्षति सहन करनी पड़ेगी।

ज. “घरेलू उद्योग 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है

ज1. वाणिज्य मंत्रालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कई जांचों में ईओयू को घरेलू उद्योग के एक अंग के रूप में माना है। जिस स्थिति तक किसी निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई अनुरक्षित रखा जाता है तब तक भारत में विनिर्मित वस्तुओं की घरेलू रूप से बिक्री करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विदेश व्यापार नीति में उक्त उत्पाद की घरेलू निकासी पर (निर्यात के लिए एफओबी मूल्य का 50 प्रतिशत तक) शुल्क की रियायती दर के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य उत्पादों पर अर्जित हकदारी का प्रयोग वसीय अल्कोहलों के लिए निर्यातों के कुल एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक किया जा सकता है। उक्त सीमा से परे, किसी निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा बिक्री समुचित उत्पाद कर का भुगतान करने पर की जा सकती है। अतः, भारत में निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा विनिर्मित उत्पाद की बिक्री करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है जब तक उसका एनएफई सकारात्मक है। इस मामले में, विटामिन ए के संदर्भ में निर्दिष्ट प्राधिकारी की जांच परिणाम के पैराग्राफ 35 का उद्धरण यहां दिया जा रहा है, जिसमें पीरामल हेल्थकेयर (एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई) को घरेलू उद्योग के रूप में माना गया था :

“ किसी उद्योग के 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई हेनित था और इसलिए उसके घरेलू उद्योग की पात्र नहीं होने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि ईओयू सुविधा स्वयं याचिकाकर्ता की “घरेलू उद्योग” के रूप में स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। वास्तव में यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में किए गए क्लियरेंस विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं या वे आपातिक नहीं हैं और उन्हें घरेलू रूप से संदत्त उत्पाद कर बिक्रियों के रूप में माना जाता है, न कि आयातों के रूप में। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता इस संबद्ध वस्तु का भारत में समस्त उत्पादन के लिए उत्तरदायी है और इस प्रकार वह नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।”

कोई निर्यातोन्मुख इकाई कोई ऐसी इकाई नहीं होती है जो भारत से बाहर स्थित हो और इसलिए वह घरेलू उद्योग का एक भाग होती है।

ज 2. याचिकाकर्ता पुनः यह प्रस्तुत करते हैं कि वीवीएफ समान वस्तु या प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करता है। वीवीएफ द्वारा उत्पादित वसीय अल्कोहलों की आयातित उत्पादों से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा होती है और इसलिए वह घरेलू उद्योग की परिभाषा को संतुष्ट करता है।

झ. आशियान देशों (ए आई एफ टी ए) के साथ विदेशी व्यापार करार के अनुसार शुल्क में कमी

झ1. भारत ने व्यापार सुगमीकरण के लिए आशियान – भारत मुक्त व्यापार करार (ए आई एफ टी ए) नामक एक करार किया है जिसके अनुसरण में प्रशुल्क अवरोधों को समयबद्ध ढंग से कम किया जाना/समाप्त किया जाना है। इस संधि प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप इस विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क प्रारंभ में दिनांक 01 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011 के द्वारा 10 प्रतिशत कम किया गया था और तत्पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 57/2013 के तहत उसका उपशमन कर दिया गया था।

झ 2. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को एआईएफटीए के कारण ही क्षति होती है और यह क्षति आयातों पर उपरोपित नहीं की जानी चाहिए।

झ 3. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि एआईएफटीए द्वारा कारित की जा रही क्षति का उपरोपण न करना नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा 2 के अनुसार इस कारण से वांछित नहीं है कि एआईएफटीए "आयातों के अलावा" एक अन्य कारक नहीं है।

झ 4. नियमावली के अनुबंध-2 के पैराग्राफ 2 में संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारकों द्वारा घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति का उपरोपण न करने का प्रावधान है जो निम्नवत् है :

"पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच, प्रयोजनमूलक साक्ष्यों के आधार पर, संबंधित वस्तु के संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति या उसकी चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी प्रदर्शित न करती हो। जब संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक साथ-साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हों तो इस क्षति के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।"

झ 5. उपर्युक्त प्रावधान यह अपेक्षा करता है कि घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों के अलावा उन अन्य कारकों का अभिज्ञान करना चाहिए जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है और उनके द्वारा कारित क्षति का उपरोपण आयातों पर नहीं करना चाहिए। विचाराधीन कारक दो प्रकार के हैं :

- क. वे कारक जो आयातों में वृद्धि में अपना योगदान देते हों।
- ख. वे कारक (संवर्धित आयातों के अलावा) जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते हों।

झ 6. एआईएफटीए के परिणामस्वरूप शुल्कों में कमी करना उन कई कारकों में से एकमात्र ऐसा कारक है जिसके आयातों में भारी वृद्धि हुई है। ऐसे ही कुछ अन्य कारकों में शामिल हैं विदेशी उत्पादकों द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, विचाराधीन उत्पाद के लिए वैकल्पिक निर्यात बाजार उपलब्ध न होना, विचाराधीन उत्पाद की निर्यात के देशों में कम मांग, भारत में शुल्क में कमी आदि। यह वे कारक हैं जो आयातों की वृद्धि में योगदान करते हैं जिनके लिए गैर-उपरोपण किए जाने की अपेक्षा नहीं होती है।

झ 7. दूसरे प्रकार के कारकों में घरेलू उद्योग द्वारा तकनीकी उन्नयन की कमी, भारत में खपत की प्रणाली में परिवर्तन आपूर्ति की ओर से अवरोध आदि जैसे कारक शामिल होते हैं। आपूर्ति भारत में ऊपर सूचीबद्ध द्वितीय श्रेणी के कारकों का अर्थात् घरेलू उद्योग को आयातों के अलावा क्षति कारित करने वाले अन्य कारकों का ही गैर-उपरोपण विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इसलिए शुल्क में कमी के लिए गैर-उपरोपण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

झ 8. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी दावा किया गया है कि चूंकि एआईएफटीए व्यापार असंतुलन का समाधान करने का एक वैकल्पिक तंत्र का प्रावधान करता है इसलिए महानिदेशक रक्षोपाय का रक्षोपाय कार्रवाई प्रारंभ करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। यह प्रस्तुतिकरण तथ्यात्मक रूप से गलत और इसलिए स्वीकार करने योग्य नहीं है। एआईएफटीए के अंतर्गत, उप पक्षकारों के अधिकार एवं प्रतिबद्धता का उल्लेख है जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। एआईएफटीए के अनुच्छेद 10(1) में प्रावधान है कि इस संधि के होने के बावजूद भी डब्ल्यूटीओ सदस्य (जिनमें भारत भी शामिल है) रक्षोपायस करार के अंतर्गत अपने अधिकार एवं अपने दायित्वों को प्रतिधारित करेंगे। इस करार का एक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :

"अनुच्छेद 10

रक्षोपाय साधन

प्रत्येक पक्षकार, जो डब्ल्यूटीओ का सदस्य है, गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX और डब्ल्यूटीओ करार (रक्षोपाय संबंधी करार) के अनुबंध-1क में रक्षोपाय संबंधी करार और डब्ल्यूटीओ करार (कृषि संबंधी करार) के अनुबंध-1क में कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को प्रतिधारित करता है। गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX और रक्षोपाय संबंधी करार या कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 5 के अनुसरण में किया गया कोई कार्य ढांचागत करार (आशियान -भारत डीएसएम करार) के अंतर्गत विवाद निपटान तंत्र करार के अध्यक्षीन नहीं होगा।

ज 1. यह तथ्य है कि एफटीए के अंतर्गत शामिल देशों से होने वाले आयातों पर शुल्क को दिनांक 01.01.2014 से हटा लिया गया है, इसके परिणामस्वरूप भी अन्य बाजारों से भारत को संबद्ध वस्तु का विपथन हो रहा है और आयातों में इसके उद्रेक के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अनंतिम शुल्क का तत्काल उद्घरण करना आवश्यक है। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियों में यूरोपियन काउंसिल ने कतिपय स्टील उत्पादों के आयातों पर अनंतिम साधन अधिरोपित किया है। इस संदर्भ में इस निर्धारण के पैराग्राफ 51 से 57 का उल्लेख नीचे किया जाता है :

"(51) इस आयोग ने यूएस बाजार से विपथित की जा रही वस्तु की भारी मात्रा के संभावित गंतव्य का प्रारंभिक आकलन किया है। यह नोट किया जाता है कि अन्य बाजारों (विशेष रूप से जापान, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी अमेरिका) की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए, इस बात की संभावना नहीं है कि इन बाजारों को भारी मात्रा में विपथन किया गया है या विपथन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, तृतीय देशों के उत्पादकों को अपनी घरेलू बाजारों में कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और वे अब यूएस बाजार के लिए पहले से निर्धारित वस्तुओं को समाहित करने में अक्षम हैं। कम्युनिटी बाजार की उन्मुक्तता पर ध्यान देते हुए, विदेशी उत्पादकों को यूएस बाजार से अपवर्जित वस्तु के

लिए एक उपयुक्त स्थान हो सकता है। इन हालातों में आयोग यह निष्कर्ष निकालता है कि यूएस बाजार से अपवर्जित निर्यातों का पर्याप्त भाग कम्यूनिटी को विपक्षित कर दिया गया है या विपक्षित कर दिया जाएगा।

(52) अतः, यह प्रत्याशा की जा सकती है कि यूएस बाजार में आयात प्रतिबंधों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप इस विचाराधीन उत्पाद के कम्यूनिटी में होने वाले आयातों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। विश्लेषण यह दर्शाता है कि लगभग 15 मिलियन टन स्टील उत्पाद (लगभग 4.1 बिलियन डालर मूल्य के), जो वर्ष 2000 में इस उत्पाद के कम्यूनिटी द्वारा किए गए कुल आयातों के बराबर है, यूएस साधनों के अंतर्गत कवर है और इस जोखिम को कम्यूनिटी की बाजारों की ओर विपक्षित किया जा रहा है।

(53) यूएस द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2002 को घोषित यूएस साधनों द्वारा समुदाय के उत्पादकों की स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई है क्योंकि इन साधनों ने कम्यूनिटी के उत्पादकों को अपने प्रक्षेपण संशोधित कर अधोगामी करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे उनके अर्जन (निर्यात और घरेलू बिक्री से होने वाला) में कमी आ गई है तथा उनकी लाभप्रदायकता को और अधिक क्षति पहुंची है। यह कम्यूनिटी उद्योग के बीच वर्तमान पुनर्गठन के लिए समझौताकारी है। यह इस उद्योग के लिए विगत में किए गए पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण प्रयासों को कम कर रहा है।

(54) चूंकि कम्यूनिटी उत्पादकों के प्रक्षेपण अधोगामी संशोधित हुए हैं, इसलिए लागत में कमी करने के उद्देश्य से इन उत्पादन सुविधाओं को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से बंद होने से बचना मुश्किल है। इस तालाबंदी न केवल समान उत्पादों का उत्पादन प्रभावित होगा बल्कि समान सुविधाओं का प्रयोग करके अन्य उत्पाद का उत्पाद भी प्रभावित होगा। उद्योग के आकलनों के अनुसार इसका सामाजिक प्रभाव यह हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में 20,000 से अधिक नौकरियां समाप्त हो सकती हैं। इसका ऋणात्मक प्रभाव उन क्रियाकलापों पर भी पड़ सकता है जो इस साधन से प्रभावित कम्यूनिटी के सदस्यों पर निर्भर हैं।

(55) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबंधित 15 उत्पादों की घरेलू खपत स्थिर बनी हुई है या उसमें कमी आ रही है और यूएस साधनों की घोषणा से पहले जिन दरों पर आयात में वृद्धि हो रही थी, घरेलू उत्पादों की स्थिति कमजोर ही हो रही है।

(56) यूएस द्वारा अपनाए गए साधन से आयातों में भारी वृद्धि से कम्यूनिटी के उत्पादकों को अपने लाभ और बिक्रियों का प्रक्षेपण अधोगामी करना पड़ा है। यह संशोधित प्रक्षेपण कम्यूनिटी उत्पादकों से अपनी लागत में कमी करने और प्रत्याशित घाटे से बचने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग करते हैं जिसमें उत्पादन सुविधाओं को समाप्त करना, कर्मचारियों की छंटनी करना आदि शामिल है। ऐसी कार्रवाई करके कम्यूनिटी उत्पादकों को कारित की जाने वाली क्षति अपूरणीय होगी। यदि इनसे बचा जाना है तो अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक होगा।

(57) इसलिए, आयोग ने यह विचार किया है कि एक ऐसी नाजुक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने में किया गया कोई विलंब से ऐसी क्षति पहुंच सकती है जिसकी भरपाई होना मुश्किल हों। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि बिना किसी विलंब के अनंतिम रक्षोपाय साधन का प्रयोग किया जाना चाहिए।

ज2. कतिपय स्रोतों से आयातों पर सीमाशुल्क हटाने के पहले से ही घरेलू उद्योग की स्थिति बहुत कमजोर थी। सतत उद्रेक से तत्काल हस्तक्षेप करना अपेक्षित हो गया है, ऐसा न करने से याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

11. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच शुरुआत पश्चात किए गए प्रस्तुतिकरण

क. रूसी परिसंघ

चूंकि उपशीर्षक संख्या 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 और 29051700 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का रूसी परिसंघ से भारत को आयात सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख तथा डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है, इसलिए रूसी परिसंघ को जांचाधीन देशों की सूची से हटा दिया जाना चाहिए।

ख. फिलीपीन्स केएओ इंक

चूंकि सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख तथा डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 के अनुसार 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है, इसलिए इसका रक्षोपाय शुल्क से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए जबकि चोटी के तीन निर्यातकों (इंडोनेशिया मलेशिया और थाईलैंड) से आयातों का हिस्सा 98 प्रतिशत से अधिक है।

ग. इंडिया ग्लायकोल लिमिटेड

भारत में केवल दो ही उत्पादक हैं मैसर्स वीवीएफ और गोदरेज़ लारिल अल्कोहल, जिसमें प्रथम उत्पादक की 63 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वह एक 100 प्रतिशत निर्यातान्मुख इकाई है। चूंकि उनके पास भारी निर्यात दायित्व है, इसलिए मांग तथा गैर प्रतिस्पर्धी कीमतों की तुलना में उनकी घरेलू बिक्रियां सीमित ही हैं साथ ही उनकी प्रदाय अवधि भी दीर्घ है। वे अपनी एकाधिकारवादी स्थिति में समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं।

आशियान देशों के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार करार के अनुसार आयात शुल्क में कमी करने पर जोर दिया गया है।

वर्ष 2013-14 में उत्पादन और मांग में वृद्धि हुई तथा लाभप्रदता में सुधार हुआ। जब जांच पूरी न हो जाए और क्षति का सुनिश्चयन न हो जाए तब तक कोई भी रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

घ. एमटी ओलियोकैमिकल्स मलेशिया

एक आवेदक की इंडोनेशिया में विनिर्माण इकाई है और उसे निर्यात लाभ प्राप्त हो रहा है तथा वह भारत में इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए मध्यवर्ती फीडस्टाक का प्रयोग कर रहा है। मलेशिया के उत्पादकों को यह लाभ प्राप्त नहीं है।

ड. आरटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

इंडोनेशिया और मलेशिया को अंतर्निहित लागत लाभ प्राप्त है और वे इस विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धी स्थान है जबकि आवेदक प्राथमिकतः निर्यात बाजारों के लिए एक निर्यातोन्मुख इकाई है क्योंकि उनकी विनिर्माण लागत घरेलू बाजार में उन्हें अप्रतिस्पर्धी बना देती है।

यदि शुल्क अधिरोपित कर दिया गया तो अधोगामी उद्योग तहस-नहस हो जाएगा क्योंकि एसएलएस और एसएलईएस का आयात आशियान एफटीए के अंतर्गत शून्य शुल्क पर किया जाता है। किसी भी प्रकार के शुल्क से भारतीय उद्योग के हित को नुकसान होगा क्योंकि आधोगामी उत्पाद अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा और मूल्यवर्धन अन्य देशों को अंतरित हो जाएगा।

च. विन्हात कैमिकल्स लिमिटेड

स्थानीय अधिप्रापण भरोसेमंद नहीं है और उसकी कीमत आयातों की तुलना में बहुत अधिक है, जबकि आवेदक की प्राथमिकता निर्यात है।

छ. काविन केयर लिमिटेड

हम एसएलईएस और एसएलएस का प्रयोग करके शैम्पू बनाते हैं जिसके लिए वसीय अल्कोहलों की जरूरत पड़ती है जिनका आयात मुख्यतः इंडोनेशिया और मलेशिया से किया जाता है जिसे प्राकृतिक एवं तुलनात्मक लाभ प्राप्त हैं। एसएलईएस और एसएलएस दोनों पर भारत-आशियान एफटीए के अंतर्गत शून्य शुल्क है।

पाम गिरी का तेल और इसके अधोगामी उत्पादों की विशिष्ट बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से यह उत्पाद महंगा हो जाएगा और कम कीमत वाले शैम्पू शेसे की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी जिससे भारी जनसंख्या को अपने बाल स्वस्थ रखने में नुकसान होगा और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग प्रभावित होगा।

ज. मेजरहब ओलियोकैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक यह छुपा रहे हैं कि वे भी सी8, सी10, सी12, सी14, सी16, वसीय अम्लों और सी18.1 (ओलिक एसिड) की बिक्री करते हैं और वे इसका गलत प्रतिनिधित्व करते हैं कि इसका उत्पादन करना और सी8, सी10 अल्कोहलों का बिक्री करना वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं है।

वित्तीय क्षति से संबंधित आवेदक के अभिकथन का प्रतिनिधित्व गलत है, चूंकि वसीय अम्लो – सी16, सी18, सी1618 की बिक्री में आवेदक के हिस्से में भारी गिरावट आई है (जो वसीय अल्कोहलों की तुलना में उनका प्रमुख व्यवसाय है) और वे यूरोप में इस वस्तु का स्वयं पाटन कर रहे हैं और जब वहां पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित कर दिया गया तो उन्होंने अपना रुख भारत की ओर कर लिया।

उन्होंने इस तथ्य का विलोपन किया है कि गोदरेज उद्योग सी1214 अल्कोहल का आयातक है।

वर्ष 2013-14 में आयात में कमी होने के लिए आवेदक द्वारा दिया गया कारण कि मलेशिया और इंडोनेशिया में तालाबंदी से ऐसा हुआ, एक गलत सूचना है क्योंकि ओलियो उद्योग में कैटालिस्ट का परिवर्तन करने के लिए नियमित बंदी की जाती है।

अधिकांश मलेशियाई और इंडोनेशियाई उत्पादकों का कच्चे माल सीपीकेओ और सीपीओ के लिए खुद का तेल संयंत्र है परंतु यह सुविधा बीवीएफ और गोदरेज दोनों के ही पास नहीं है।

भर्ती में वर्ष 2010-11 की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 तक 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसलिए रोजगार में क्षति होने का उनका दावा निराधार है।

सी16, सी1618 और सी18 अल्कोहलों में आवेदक का हिस्सा घरेलू और निर्यात बाजारों दोनों में बढ़ा है।

झ. मैसर्स पीटी मुसिम मास

आवेदक ने बेशी एवं अवांछित गोपनीयता का दावा किया है जिसने पक्षकार को आवेदक के दावे और भरोसा की गई सामग्री को तर्कसंगत रूप से समझने से वंचित कर दिया।

घरेलू उत्पादक किसी ऐसे एसएफए का उत्पादन नहीं करते हैं जिसकी लंबाई सी8 और सी10 हो और जो उनका सम्मिश्रण हो और इन वस्तुओं के आयात से आवेदक को क्षति नहीं हो सकती है। इस विचाराधीन उत्पाद को सही-सही परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे एसएफए के प्रकारों को पृथक् किया जा सके।

आवेदक का यह दावा सिद्ध नहीं होता है कि आयातों में अचानक वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि आयातों में वर्ष 2011-12 से 2013-14 (वार्षिकीकृत) की अवधि के दौरान और खासकर 2013-14 में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

आवेदक ने वर्ष 2013-14 के आंकड़ों की अनदेखी कर दी और उन्होंने प्रत्येक तिमाही का विश्लेषण विगत वर्ष की तिमाही से करना प्रारंभ कर दिया।

आवेदक का यह दावा कि मलेशिया और इंडोनेशिया में संयंत्र की तालाबंदी दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 की पहली और दूसरी तिमाही में आयातों में कमी है, विश्वसनीयता नहीं है क्योंकि उत्पादन फिर से प्रारंभ हो जाने के पश्चात वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में उत्तरवर्ती उद्रेक नहीं हुआ।

इस विचाराधीन उत्पाद का चयन जानबूझकर एसएफए के आयातों पर कम प्रकाश डालने के लिए किया गया क्योंकि आधार वर्ष 2010-11 (जैसा कि आवेदक ने प्रस्ताव किया है) के साथ आयातों की प्रवृत्ति बिल्कुल भिन्न तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और यदि आधार वर्ष 2011-12 लिया जाए तो बिल्कुल भिन्न तस्वीर उपस्थित होगी।

आवेदक का क्षति का दावा स्थापित नहीं होता है क्योंकि इसकी क्षमता और इसके उत्पादन में वर्ष 2013-14 में भारी सुधार हुआ।

आवेदक के बाजार हिस्से में गिरावट इसकी ईओयू स्थिति तथा निर्यात उन्मुखी होने के कारण इस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हो सकता है।

रक्षोपाय शुल्क से आवेदक को इंडोनेशिया और मलेशिया के एसएफए के उत्पादकों की तुलना में कोई लाभ नहीं पहुंचेगा क्योंकि मुख्य कच्चे माल का उत्पादन वहां स्वयं किया जाता है।

व. थाई फेटी अल्कोहल कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड, विल्सर ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर, केएल – कियांग ओलियोमास एसडीएन बीएचडी एवं गैलेक्सी सरफैक्टेंड्स

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने केवल सी12, सी14, सी16, सी18 और उनके सम्मिश्रणों का ही उत्पादन एवं बिक्री की है, न कि सी8 और सी10 कार्बनों की। इसके अतिरिक्त, कतिपय कार्बन शृंखला लंबाई और संयोजनों, जिनका आयात भारत में नहीं किया जा रहा है या जिनका जांच की अवधि के दौरान कदाचित ही प्रयोग किया गया वे हैं सी810 और सी14। अतः इन उत्पादों की परिभाषा में इस ग्रेड को शामिल करना गलत होगा।

वर्तमान विधिक एवं वाणिज्यिक स्थिति में वीवीएफ घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया है और उसे क्षति हो रही है। वीवीएफ कच्चे माल के आयात पर निर्भर है जो इंडोनेशिया और मलेशिया में निर्यात करके अध्यधीन है, जबकि वीवीएफ जब घरेलू बाजार में वसीय अवकोहलों की बिक्री करता है, तो प्रयोक्ताओं को सीमा शुल्क के बराबर उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जो भारत-आशियान करार के अंतर्गत इन देशों से वसीय अल्कोहल के आयात के मामले में अनुप्रयोज्य नहीं है।

पिछले वर्ष की तुलना में, आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई और केवल आयातों तथा विचाराधीन उत्पाद पर विचार करते समय प्राधिकारी को सभी उत्पाद ग्रेडों/कार्बन शृंखला की लंबाइयों की अलग से जांच करनी होती है।

वास्तव में अधिकांश ग्रेडों के आयात में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई और जांच की अवधि (दिसम्बर, 2013-14 तक) के दौरान वे सबसे कम स्तर पर थे।

याचिकाकर्ता और अन्य उत्पादक गोरदेज़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ईओयू) दोनों ही का प्राथमिक उद्देश्य भारत की संबद्ध वस्तु का निर्यात करना है।

आयातों में बढोतरी होने का एक बड़ा कारण आशियान देशों के साथ व्यापार बढाने की भारत की पहल है और उन्हें शुल्क की रियायती पर प्रदान करना है।

याचिकाकर्ता डीटीए क्लीयरेंस केवल उच्च दर पर ही प्राप्त कर सकता है न कि आशियान एफटीए के अंतर्गत भारत की शर्तों के अनुसार सीमाशुल्क की अधिमानी दर पर।

रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण इस अंतर को समाप्त नहीं कर सकता है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा लिया गया एक नीति निर्णय है और याचिकाकर्ता का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

त. पीटी इकोग्रनी

1. एनओआई और शिकायत में उपयुक्त ढंग से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या ये संबंधित आयात अभिनव, अचानक, तेजी से एवं महत्वपूर्ण स्थिति में घटित हुए।
2. शिकायतकर्ता निर्यातोन्मुखी इकाई स्कीम के अंतर्गत प्रचालन कर रहा है और भारतीय बाजार में घरेलू बिक्री मात्रा उत्पादन की कुल मात्रा के एक तिहाई तक सीमित है और यह भारतीय बाजार की घरेलू मांग को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर सकती है।
3. भारत में वसीय अल्कोहल के दो उत्पादक हैं नामशः शिकायतकर्ता और गोदरेज, उसका भी भारत में घरेलू उत्पाद के भारी भाग पर अधिकार है और इस प्रकार दोनों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।
4. गोदरेज शिकायतकर्ता के साथ नहीं है और शिकायत में प्रस्तुत किया गया इसका समग्र निष्पादन सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है।

थ. रोडिया स्पेशियलिटी कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड (साल्वे ग्रुप)

भारत इथायलीन आक्साइड की समुचित कीमत निर्धारण और लौरिल अल्कोहल की उपलब्धता के कारण इस समय इथाक्सीलेशन हब हैं और विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क समस्त मूल्यवर्धन को समाप्त कर देगा जिससे रोजगार एवं राजस्व में घाटा होगा।

द. हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड

1. आयातों की मात्रा इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से संकेंद्रित है और उससे वैश्विक रक्षोपाय साधन वांछित नहीं है। आवेदनकर्ता को व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी ढांचागत करार के अंतर्गत वस्तु व्यापार करार के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत उपलब्ध उपचारों पर विचार करना चाहिए।
2. इस तथ्य का स्पष्टतः कोई कारण नहीं है कि कुछ कार्बन शृंखलाएं जिनका उत्पादन नहीं किया जा रहा है उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित क्यों कर दिया जाना चाहिए। आवेदनपत्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक सी8 और सी10 लंबाई के वसीय अल्कोहल और उनके सम्मिश्रणों का आयात नहीं करता है।
3. अनपेक्षित विकास के पहलू की पूरी तरह से अनदेखी की दी गई है और आवेदन में उसकी मौजूदगी ही नहीं है।
4. आवेदक के प्रचालन कम निर्यात निष्पादन और निर्यात बाजार में न्यूनतम प्रापण तथा उच्च वित्त लागत के कारण प्रभावित हो सकते हैं और क्षति, यदि कोई हो, स्वतः पहुंचाई गई है और वह संबंधित आयातों पर आरोप्य नहीं है।
5. संबद्ध वस्तु का आशियान सीईसीए के अंतर्गत इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों से भारत को प्रशुल्क मुफ्त आयात किया जा सकता है। इस क्षति का कारण आधारभूत रूप से व्युत्क्रमित शुल्क ढांचा है और इसे संबद्ध वस्तु के बढ़ते आयातों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है।
6. आवेदक ने समायोजन योजना का प्रकटन करने के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता के दावे का अनुचित लाभ प्राप्त किया है।
7. रक्षोपाय शुल्क का कोई अधिरोपण जनहित के विपरीत होगा क्योंकि उपभोक्ता उद्योग के हितों पर सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।

12. घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए उपर्युक्त सभी जांच शुरुआत पश्चात प्रस्तुतिकरणों का उत्तर दिया है और उसके शुरुआती प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

12.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 ("अधिनियम") की धारा 8ख के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा रक्षोपाय करार से संगत नहीं है। यह तर्क सही नहीं है क्योंकि चूंकि वाक्यांश घरेलू उत्पादन का आशय भारत में उत्पादन से होता है न कि भारत में खपत के लिए निर्धारित उत्पादन से। यह अनुरोध अनुचित है कि स्थायी जरूरत की जांच केवल घरेलू उत्पादन के संदर्भ में की जानी चाहिए। उत्पादन के स्तर पर यह ज्ञात नहीं होता है कि क्या किसी वस्तु की खपत भारत में की जाएगी या अन्यत्र। किसी भी हाल में भारतीय उत्पादकों का कुल उत्पादन, उनके निर्यात को घटकर, भी यह प्रदर्शित करता है कि याचिकाकर्ता का इस जांच के प्रयोजनार्थ आधार है।

12.2 "घरेलू उद्योग 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई होने और इसलिए घरेलू उद्योग के रूप में उसके अपात्र होने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि निर्यातोन्मुख इकाई की सुविधा याचिकाकर्ता के "घरेलू उद्योग" के रूप में दर्जे की विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में किया गया क्लीयरेंस विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के लिए प्रतिबंधित अथवा आयातिक नहीं है और उसे उत्पाद कर संदत्त घरेलू बिक्रियों के रूप में माना जाता है न कि आयातों के रूप में। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों के लिए उत्तरदायी है और इस प्रकार वह नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।"

12.3 कोई निर्यातोनमुख इकाई, भारत के बाहर स्थित इकाई नहीं होती है और इसलिए यह घरेलू उद्योग का ही भाग होती है।

12.4 कास्को ब्लासम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा-शुल्क आयुक्त के मामले में, जिसे वर्ष 2004 (164) ईएलटी 423 (ट्रि दिल्ली) में रिपोर्ट किया गया, माननीय अधिकरण ने यह उल्लेख किया कि किसी ईओयू द्वारा निकासी की गई वस्तु को घरेलू वस्तु के रूप में माना जाता है। इसका संगत पैराग्राफ नीचे उद्धृत किया जा रहा है।

"5. यह सुस्थापित 12000 (120) ईएलटी 8001 है कि किसी निर्यातोनमुखी इकाई में उत्पादित वस्तु को आयातित वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है और उसे सीमा-शुल्क के अध्याधीन नहीं किया जा सकता है। ऐसी वस्तु के संबंध में संदेय शुल्क केंद्रीय उत्पाद कर अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अंतर्गत की धारा 28 के अंतर्गत किए गए प्रतिवादी ओदश में की गई शुल्क की मांग संधारणीय नहीं है। तदनुसार हम इस प्रतिवादी आदेश पर ध्यान न देते हुए वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं। तथापि, हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि राजस्व प्राधिकारी आयातित इनपुटों, यदि कोई हो, जिनका उपयोग प्रश्नाधीन कट-फ्लावर्स का उत्पादन करने में किया जाता है, पर शुल्क की मांग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।"

12.5 याचिकाकर्ता का घरेलू उत्पादन में हिस्सा 60 प्रतिशत है और इसलिए यह "घरेलू उद्योग" बनने के योग्य है।

12.6 याचिकाकर्ता एक 100 प्रतिशत निर्यातोनमुख इकाई है, इसलिए यह डीटीए इकाइयों की तुलना में प्रतिवर्षी लाभ का उपयोग करता है। कच्चे माल (पीकेओ) जैसे पाम गिरी का तेल (जो यथामूल्य 7.5 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की रेंज में होता है) पर सीमा-शुल्क परिष्कृत वस्तुओं पर लागू शुल्क से कहीं अधिक होती है। चूंकि कोई निर्यातोनमुख इकाई इस कच्चे माल (पीकेओ) का आयात शुल्क का भुगतान किए बिना कर सकता है और अपने परिष्कृत उत्पादन की निकासी 7.725 प्रतिशत की दर से (जिसे अब दिनांक 18 फरवरी, 2014 से 3.86 प्रतिशत कर दिया गया है) शुल्क का भुगतान करके कर सकता है। इसलिए ईओयू लागू निवल शुल्क आयातित सामग्री से वसीय अल्कोहल विनिर्मित करने वाली इकाइयों से बहुत कम होती है। डीटीए इकाइयों को कच्चे माल पर सीमा-शुल्क वहन करना होता है जिससे उनकी लागत पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। अतः घरेलू यूनिट का निवल शुल्क ईओयू इकाई के निवल शुल्क की तुलना में बहुत अधिक होता है।

12.7 यह दावा सही नहीं है कि आयातों और लाभप्रदायकता के बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता है। ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण भ्रामक है क्योंकि यह इंडेक्स संख्याओं पर आधारित होता है। पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयातों तथा घरेलू उद्योग को कारित की गई क्षति के परस्पर संबंध है। यह आयात वर्ष 2012-13 और 2013-14 में सर्वाधिक थे। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, लाभप्रदायकता, निवेश पर अर्जन, घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की स्थिति में पर्याप्त बदतरी आई है जबकि उन दिनों आयात उच्चतर स्थिति में थे।

12.8 एफटीए के अंतर्गत आने वाले देशों से वसीय अल्कोहल के आयातों पर लगे शुल्क को दिनांक 01.01.2014 से समाप्त कर दिया गया है। इस कमी की प्रत्याशा में आयातों में तीसरी तिमाही में कमी आई। याचिकाकर्ता इस अवधि के दौरान अपने ग्राहकों का प्रतिधारण करने में समर्थ रहा। सीमा-शुल्क की समाप्ति के पश्चात वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में आयातों में भारी वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग की स्थिति में और अधिक गिरावट आ गई।

12.9 यह देखा जा चुका है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में विगत अवधि की तुलना में पिछली तिमाही में भारी बदतरी आई है। तीसरी तिमाही में मामूली से सुधार के प्रभाव को चौथी तिमाही में पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में कच्चे माल की कीमतों में तीव्र वृद्धि होने के बावजूद संबद्ध वस्तु की आयात कीमतों में कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई।

2013-14	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4
पीकेओ की कीमतें (अनुक्रमित)	100	104	127	154
आयातों का उतराई मूल्य	81924	94944	102155	102800
प्रवृत्ति	100	116	124	125

12.10 इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि गंभीर क्षति कारित की गई है और उससे भी अधिक गंभीर क्षति की चुनौती आसन्न है। आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध भी स्थापित हो जाता है।

12.11 यह क्षति ऐसे "घरेलू उद्योग" को कारित की जानी चाहिए जो समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद का आयात करता हो। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वसीय अल्कोहल आयातित वस्तु के तुलनीय है और वे आयातित वस्तु से वाणिज्यिक रूप से और तकनीकी रूप से अंतर्निमेय हैं।

12.12 इस उत्पाद में उन ग्रेडों/प्रकारों को कवर किया जाता है जो उनके तकनीकी गुणधर्मों, रासायनिक संघटनों और अन्य आधारभूत विशिष्टताओं के रूप में समान होते हैं। इन सभी शीर्षकों के उत्पादों का समान उपयोग होता है। इसलिए यह उत्पाद समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं। मामूली से सतही संभावित अंतर के बावजूद, इन उत्पादों के समरूप आधारभूत भौतिक गुणधर्म होते हैं और इनके समरूप अंतिम प्रयोग भी होते हैं। इनकी बिक्री समान या समरूप बिक्री सारणियों से की जाती है। यह उत्पाद मुख्यतः कीमत पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक आठ अंकीय स्तर के एक शीर्षक पर या एक प्रकार पर, विवक्ति में, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा क्योंकि आयातगण अन्य प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद का आयात करना प्रारंभ कर देंगे। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त को ध्यान में

रखते हुए इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित उत्पाद पर रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में समुचित ढंग से विचार किया गया है।

12.13 पाटनरोधी प्रक्रिया में, ई यू संख्या 1138/2011 में ई सी के समक्ष ऐसा ही एक मुद्दा उठा काउंसिल इमप्लीमेंटिंग रेगुलेशन (ई यू) संख्या 1138/2011 दिनांक 8 नवम्बर, 2011

12.14 अनन्तिम विनियम की प्रस्तुति संख्या 10 और 11 में यथानिर्धारित संबंधित उत्पाद सी8, सी10, सी12, सी14, सी16, या सी18 लम्बाई के कार्बन चैन युक्त (जिनमें शाखायुक्त आइजोमर्स शामिल नहीं हैं), जिनमें एकल अनुबिद्ध वसीय अल्कोहल शामिल हैं (जिन्हें सिंगल कट्स के नाम से भी जाना जाता है) और जिनमें सी6-सी8, सी6-सी10, सी8-सी10, सी10-सी12 लंबाई की कार्बन शृंखला संयोजनयुक्त सम्मिश्रण शामिल हैं) (जिन्हें सामान्यतः सी8-सी10 के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है, सी12-सी14, सी12-सी16, सी12-सी18, सी14-सी16 (जिन्हें सामान्यतः सी12-सी14 के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है) लम्बाई के कार्बन शृंखला के संयोजनयुक्त प्रमुख सम्मिश्रण और सी16-सी18 लंबाई की कार्बन शृंखला के संयोजनयुक्त प्रमुखतः सम्मिश्रण शामिल हैं, जो भारत इंडोनेशिया और मलेशिया मूल के हों और जो इस समय सी एन कोड ई एक्स 2905 16 85, 2905 17 00, ई एक्स 2905 19 00 और ई एक्स 3823 17 00 के अंतर्गत आने वाले अनुबिद्ध वसीय अल्कोहल्स हैं।

12.15 अनन्तिम शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात् कुछ पक्षकारों ने सम्बंधित उत्पाद की परिभाषा की अस्पष्टता के संबंध में शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि एन ओ आई के अनुसार केवल लीनियर एफ ओ एच को ही इस उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाता है और इसलिए शाखा युक्त आइजोमर्स सहित एफ ओ एच अथवा शाखायुक्त एफ ओ एच का अपवर्जन किया जाता है। अन्य पक्षकारों ने यह दावा किया है कि आक्सो प्रक्रिया द्वारा उत्पादित शाखायुक्त आइजोमर्स युक्त एफ ओ एच का अपवर्जन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है क्योंकि उनका समान उपयोग होता है और बाजार में एफ ओ एच के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

"12.16 यह स्थापित किया गया है कि इस जांच में शामिल एफ ओ एच के सभी प्रकार, जिनका प्रस्तुति 8 में वर्णन किया गया है, उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल के रूप में संभावित अंतर होने के बावजूद या उत्पादन प्रक्रिया में अंतर होने के बावजूद उनके समान या बहुत समान आधारभूत भौतिक, रासायनिक और तकनीकी गुणधर्म होते हैं और उनका प्रयोग समान प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संबंधित उत्पाद में संभावित अंतर इसकी मूलभूत परिभाषा, गुणधर्मों अथवा इस अवबोधन में कोई अंतर नहीं लाते हैं कि विभिन्न पक्षकारों के पास यह उपलब्ध है"।

12.17 विचाराधीन उत्पाद में एक एकल कच्चे माल से व्युत्पन्न ग्रेड/प्रकार शामिल हैं। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी एकल सम्मिश्रण/कट को विविक्ति में नहीं लिया जा सकता है इसलिए सी 8 से सी 18 तक की कार्बन शृंखलाओं के संपूर्ण सेट को इस उत्पाद की एकल श्रेणी के रूप में माना जाएगा। इनके अनुप्रयोग मौटे तौर पर एक समान हैं, यह कि इनका प्रयोग डिटर्जेंट और निजी देखभाल उद्योग में किया जाता है। वास्तव में सी12, सी14 और सी16 सी18 को इथोक्सीलेट में संपरिवर्तित किया जा सकता है और उनका प्रयोग डिटर्जेंट अनुप्रयोगों में सर्फैक्टेंट के रूप में किया जाता है। सी12 सी18, जो सी12 सी14 तथा सी16, सी18 का सम्मिश्रण होता है का प्रयोग भी समान अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। सी 14 पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सी12 सी14 सम्मिश्रण का एक भाग होता है।

12.18 यह विचार करना भी संगत होगा कि वसीय अल्कोहलों का प्रयोग साबुन, डिटर्जेंट और निजी देखभाल उत्पादों में 10 प्रतिशत से भी कम होता है। विभिन्न सम्मिश्रणों में वाणिज्यिक/ तकनीकी अंतरनिमेयता होती है। अन्तिम उत्पाद का प्रमुख गुणधर्म वसीय अल्कोहलों से प्राप्त नहीं किया जाता है बल्कि यह अन्य सामग्री के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है।

12.19 याचिकाकर्ता तलोजी इकाई में लगी प्रक्रिया का अनुपालन करता है। इस प्रक्रिया द्वारा वाणिज्यिक रूप से नारियल अल्कोहल के रूप में ज्ञात उत्पाद, जो सी8 से सी 18 का सम्मिश्रण है, का उत्पादन किया जा सकता है। प्रभाजन आसवन की प्रक्रिया द्वारा सी8 से सी 18 के किसी प्रभाजन को किया जा सकता है।

12.20 याचिकाकर्ता ने सी10 की विक्री उत्पाद कर शुल्कों का भुगतान करके की है।

(ग) महानिदेशक (रक्षोपाय) के निष्कर्ष

13. मैंने इस मामले के रिकॉर्डों, घरेलू उद्योग, निर्यातकों और निर्यातक राष्ट्रों द्वारा दायर प्रत्युत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों का इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर समाधान कर दिया गया है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध की जांच घरेलू विधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत समालोचनात्मक परिस्थितियों की मौजूदगी के संदर्भ में की गई। रक्षोपाय करार के प्रावधानों और

डब्लू टी ओ निकायों के निर्णयों के प्रावधानों का समुचित स्थानों पर उल्लेख किया गया/उन पर चर्चा की गई। तदनुसार ही अपने जांच परिणाम दिए गए हैं। यह, अनन्तिम जांच परिणाम जो घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों/आवेदन पत्रों, हितबद्ध पक्षकारों के जांच शुरुआत पश्चात प्रत्युत्तरों तथा अन्य आंकड़ों के आधार पर किया गया है। मैं इस तथ्य के प्रति जागरूक हूँ कि घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया विस्तृत प्रस्तुतीकरण एतदपश्चात इस कार्रवाई में रिकॉर्ड में ले ली जाएगी जिस पर अन्तिम जांच परिणाम देते वक्त विचार किया जाएगा, विचार किया गया है।

13.1 सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का वर्णन करती है। धारा 8ख(1) में केन्द्रीय सरकार द्वारा उन वस्तुओं पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रावधान है जिसका भारत में आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जा रहा हो जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती हो या जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख की उप-धारा 2 में निम्नलिखित प्रावधान है:

केन्द्रीय सरकार उप-धारा(1) के अंतर्गत निर्णय लंबित रहने पर इस उपधारा के अधीन इस प्रारंभिक निर्धारण के आधार पर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है कि संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई गई है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी गई है।

परन्तु यह कि जहां अन्तिम निर्धारण होने पर केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति न तो कारित की है और न ही उसकी चुनौती उत्पन्न करने की परिस्थितियां सृजित की हैं तो वह इस तरह संग्रहित शुल्क वापस ले लेगा।

परन्तु यह और कि यह अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क उसके अधिरोपण की तारीख से 200 दिनों से अधिक के लिए नहीं लगाया जा सकता है।

14. सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 में जांच को शासित करने वाले तरीकों एवं सिद्धांतों का प्रावधान है। यह नियम सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख के अंतर्गत बनाए गए हैं। मुझे इन नियमों के अंतर्गत विधि के अनुरूप रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उपर्युक्त नियमावली के नियम 9 में यह प्रावधान किया गया है कि "महानिदेशक यह जांच आयोजित करने में शीघ्रता करेंगे और संवेदनशील परिस्थितियों में वह गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम रिकॉर्ड करेंगे"। उपर्युक्त नियमावली के नियम 10 में यह प्रावधान किया गया है केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार महानिदेशक के प्रारंभिक जांच परिणामों के आधार पर अनन्तिम शुल्क का अधिरोपण कर सकती है, परन्तु शर्त यह है कि यह शुल्क इसके अधिरोपण किए जाने की तारीख से 200 दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी नहीं रहेंगे।

14.1 उपर्युक्त नियमावली के नियम 2(ख) में प्रावधान है कि "संवेदनशील परिस्थितियों" का आशय उन परिस्थितियों से है जिनमें इस आशय के स्पष्ट साक्ष्य हों कि यह आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में हुए हैं कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है। और अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण में विलंब करने से घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति होगी;

14.2 मैं उपपादित करता हूँ कि हितबद्ध पक्षकारों में से एक हितबद्ध पक्षकार ने आशियान द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार के मद्देनजर इस रक्षोपाय आवेदन पर कार्रवाई करने में इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया और यह धारित किया है कि चूंकि अधिकांश आयात आशियान राष्ट्रों में उद्धवित हुए हैं और वाणिज्य विभाग जो इन एफ टी ए में वार्ताकारी रहा है, ही राहत प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होना चाहिए।

14.3 इस संबंध में, मैंने उक्त द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार का गंभीरता से अध्ययन किया। इस संधि से एक उद्धरण देना पर्याप्त होगा।

अनुच्छेद 10

रक्षोपाय साधन

प्रत्येक पक्षकार जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है उसे गाट 1994 के अनुच्छेद XIX, डब्लू टी ओ करार के अनुबंध 1क में उल्लिखित (रक्षोपाय करार) और डब्लू टी ओ करार (कृषि संबंधी करार) के अनुबंध 1क में कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अपने अधिकार एवं दायित्व प्रतिधारित करता है। गाट 1994 के अनुच्छेद XIX और रक्षोपाय करार या कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 5 के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई ढांचागत करार के अंतर्गत (आशियान भारत डी एस एम करार) विवाद निपटान तंत्र करार के अध्याधीन नहीं होगा।

उपर्युक्त प्रावधानों के मद्देनजर हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के विपरीत कि इस मामले में राहत प्रदान करने के लिए रक्षोपाय निदेशालय एक उपयुक्त मंच नहीं है। यह प्रेक्षण किया जाता है कि विभिन्न करारों में व्यापार असंतुलन का समाधान करने के लिए वैकल्पिक तंत्र का प्रावधान किया गया है जिससे कि व्यापार असंतुलन दूर हो सके, रक्षोपाय महानिदेशालय के क्षेत्राधिकार को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के

तत्वाधान में कार्य कर रहे के, अंतर्गत अपवर्जित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में आशियान मुक्त व्यापार करार में स्वयं यह प्रावधान किया गया है कि इस संधि के होते हुए भी डब्लू टी ओ सदस्य (भारत सहित) रक्षोपाय करार के अंतर्गत आने वाले अपने सभी अधिकार एवं दायित्वों का प्रतिधारण करेंगे।

14.4 इसके अतिरिक्त सामान्य रक्षोपाय साधन का अधिरोपण बिना किसी भेदभाव के विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर, निर्यात के देश पर विचार किए बिना, न्यूनतम के प्रावधान को छोड़कर और उसके अलावा सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (1) के परन्तुक के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने वर्तमान मामले में सामान्य रक्षोपाय साधनों के अंतर्गत राहत प्राप्त करने का आश्रय लिया है जो मौजूदा विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पूर्णतया न्यायोचित है। इसलिए, प्रचुर मात्रा में यह स्पष्ट है कि इस कार्यालय को आवेदक के वर्तमान मामले में रक्षोपाय आवेदन पर कार्रवाई करने का प्राधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है और तदनुसार मैं इस पर अनंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड करने की कार्रवाई करता हूँ।

15. जांचाधीन उत्पाद

15.1 इसमें अंतर्ग्रस्त उत्पाद, 'सी8, सी10, सी12, सी14, सी16, या सी18 लम्बाई के कार्बन चैन युक्त एकल, मिश्रण और अमिश्रण सहित (जिनमें शाखायुक्त आइजोमर्स शामिल नहीं हैं), जिनमें एकल सी12-सी14, सी12-सी16, सी12-सी18, सी16-18 और सी14-सी16 (जिन्हें सामान्यतः सी12-सी14 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है) सैचुरेटेड वसीय अल्कोहल शामिल हैं' जिन्हें एतदपश्चात् 'पी यू सी' (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है। आयात किया जा रहा यह विचाराधीन उत्पाद सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के उपशीर्षक संख्या 38237010, 38237020, 38237040, 23237090 और 29051700 के अंतर्गत आता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। इस विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग मुख्यतः सर्फेक्टेंट्स, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, भेषजों और कृषि संबंधी अंतिम अनुप्रयोगों, चर्म, वस्त्र, फर, पल्प, कागज, पेट्रोलियम उत्पाद कैमिकल रबड़ उत्पादों के श्रेष्ठ रसायनों के लिए किया जाता है, रबड़ उत्पादों, प्लास्टिक और फेब्रिकेट किए गए धातु उत्पाद जिसमें खनन अपतटीय प्रचालन निर्माण कार्य साल्वेंट के रूम में और डीग्रीजिंग उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस उत्पाद की बिक्री खुदरा स्तर पर नहीं की जाती है और यह केवल औद्योगिक प्रयोगों के लिए ही होता है।

15.2 कुछ हितवद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उत्पाद के दायरे को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न शाखा शृंखला के संमिश्रित/ वसीय अल्कोहल भिन्न मर्दें हैं मैं यह उपादित करता हूँ कि ऐसे घरेलू उद्योग को क्षति होनी चाहिए जो समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उत्पादन करते हों। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वसीय अल्कोहल आयातित वस्तु के तुलनीय है और वे वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से आयातित वस्तु के अंतर्निमेय हैं। इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद में उन ग्रेडों/प्रकारों को शामिल किया गया है जो तकनीकी गुणधर्मों, रासायनिक संघटन और अन्य संबंधित आधारभूत पहलुओं के रूप में समान हों। इन सभी शीर्षकों के उत्पादों का प्रयोग समान होता है। इसलिए यह सभी उत्पाद समान या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं। छोटे-छोटे संभव आभासी अंतरों के बावजूद, इन सभी उत्पादों का समान भौतिक गुणधर्म होता है और उनके समान प्रयोग होते हैं। उनकी बिक्री समान या समरूप बिक्री सारणियों के जरिए की जाती है।

15.3 घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद में एक कच्चे माल से व्युत्पन्न सभी ग्रेडों/प्रकारों तथा कार्बन चैन सी8 से सी18 के संपूर्ण सेट को एकल श्रेणी के उत्पाद के रूप में देखे जाने की जरूरत है। इन सभी का अनुप्रयोग मोटे तौर पर सामान्य होता है अर्थात् इनका प्रयोग डिटर्जेंट और निजी देखभाल उद्योग में किया जाता है। वास्तव में, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार सी12 सी14 और सी16 सी18 दोनों को इथोक्सीलेट्स में संपरिवर्तित किया जा सकता है और डिटर्जेंट अनुप्रयोगों में उनका प्रयोग सर्फेक्टेंट के रूप में होता है। सी12 सी18 जो कि सी12 सी14 और सी16 सी 18 का संमिश्रण है, का प्रयोग भी उन्हीं अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। सी14 पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सी12 सी14 के संमिश्रण का एक भाग है। इसके अतिरिक्त, यह विचार करना संगत होगा कि साबुन, डिटर्जेंट, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में वसीय अल्कोहलों की मात्रा 10 प्रतिशत से भी कम होती है। विभिन्न संमिश्रणों की वाणिज्यिक एवं तकनीकी अंतरनिमेयता होती है। अंतिम प्रयोग उत्पाद का आवश्यक गुणधर्म वसीय अल्कोहल से प्राप्त नहीं होता है बल्कि यह अन्य सामग्री, जो प्रमुख होती है और/या भारी मात्रा में अंतिम उत्पाद में मौजूद होती है, से प्राप्त होता है। इन उत्पादों के बीच कीमत के संबंध में प्रतिस्पर्धा होती है। यह रिकॉर्ड में उपलब्ध है कि याचिकाकर्ता तलोजा यूनिट में लुर्गी प्रक्रिया का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया द्वारा एक उत्पाद जिसे वाणिज्यिक रूप से कोकोनट अल्कोहल के रूप में जाना जाता है और जो सी8 से सी18 का संमिश्रण होता है, का उत्पादन किया जाता है। प्रभाजन आसवन प्रक्रिया द्वारा किसी प्रभाजन-सी8 से सी18 को लिया जा सकता है।

15.4 हितवद्ध पक्षकार के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग सी8 और सी10 वसीय अल्कोहल का विनिर्माण नहीं करता है, मैं यह पाता हूँ कि घरेलू उद्योग ऐसे साक्ष्य प्रदान किए हैं कि उन्होंने सी10 का उत्पादन किया है और उत्पाद कर का भुगतान करके उसकी बिक्री की है। जहां तक सी8 का संबंध है, घरेलू उद्योग में उल्लेख किया है कि उनके पास सी8 का विनिर्माण करने की क्षमता है परन्तु उस उत्पाद की मांग

नहीं है। इसके अतिरिक्त, मैं यह पाता हूँ कि हितबद्ध पक्षकारों ने केवल इस बात का उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग ने सी8 वसीय अल्कोहल का उत्पादन नहीं किया है परन्तु उन्होंने सी8 वसीय अल्कोहलों का विनिर्माण करने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है और न ही कोई विवाद किया है।

15.5 अतः, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं यह पाता हूँ कि रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ एकल या विभिन्न कार्वन चैनों के संमिश्रण वाले अल्कोहलों, जिनका जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, पर विचाराधीन उत्पाद के रूप में समुचित ढंग से विचार किया गया है। अतः, चूंकि यह सभी उत्पाद अंतरनिमेय हैं तथा उनका उत्पादन समरूप विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा समरूप कच्चे माल से किया जाता है, इसलिए इस मामले में इस विचाराधीन उत्पाद को बिलकुल सही-सही परिभाषित किया गया है।

16. घरेलू उद्योग

सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख के खंड (6) (ख) में उल्लेख है कि "घरेलू उद्योग" का आशय उन उत्पादकों से होता है :-

- (i) जो भारत में समग्र रूप से समान वस्तु हो या
- (ii) जिनका भारत में समान उत्पाद प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी उत्पाद का सामूहिक रूप से उत्पादन भारत में उस घरेलू उत्पाद के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता हो।

16.1 यह आवेदन पत्र मैसर्स वी वी एफ (भारत) लिमिटेड मुम्बई, एक 100 प्रतिशत निर्यातान्मुख इकाई, द्वारा दायर किया गया है। यह आवेदक कुल भारतीय उत्पादन के 63 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करता है और इसलिए वह घरेलू उद्योग है।

16.2 रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात् यह निर्धारित किया जाता है कि याचिका दायर करने वाले घरेलू उत्पादक का उत्पादन और उसका उत्पादन जिसने संगत सूचना प्रदान कराई है भारत में उक्त अनुच्छेद के अनुसार कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। तदनुसार, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख के अनुसार वे घरेलू उत्पादक हैं। इस आवेदनपत्र का समर्थन मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया है जो इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाला देश में एक मात्र दूसरा उत्पादक है।

17. जांच की अवधि (पी ओ आई) :

सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975, सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997, रक्षोपाय करार और गाट के अनुच्छेद 19 में विशेषरूप से यह परिभाषित नहीं किया गया है कि जांच की अवधि कितनी होनी चाहिए। मेरा अपना विचार है कि भारत में विधि सक्षम प्राधिकारी को जांच की ऐसी अवधि की दीर्घता का निर्धारण करने का विवेक प्रदान करती है जो गंभीर क्षति पहुंचाने वाले संबंधित आयातों तथा अन्य आकारों के बारे में सही-सही तुलना करने में सक्षम हो सके। वास्तव में ऐसे विवेक का प्रयोग बहुत ही सोच-विचार कर किया जाना चाहिए।

17.1 जांच की अवधि से संबंधित मुद्दे का समाधान अर्जेंटीना फुटवीयर संबंधी अर्जेंटीना फुटवीयर पर पैनल रिपोर्ट में व्यापक रूप से निराकरण किया गया है जिसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

पदत्राण आयातों पर अर्जेंटीना रक्षोपाय साधन; पैनल की रिपोर्ट (डब्ल्यू टी/डीएस 121/आर दिनांक 25.06.1999)

"8.216 उद्योग की स्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण करने में अंतिम बिन्दु से अंतिम बिन्दु तक तुलना करने पर जांच के अत्यधिक व्यापक भरोसे के संबंध में हमारी भी वही चिन्ता है जैसी कि संबंधित आयातों के संबंध में ऊपर नोट की गई थी। हम यहां विशिष्ट रूप से यह नोट करते हैं कि हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति पर यदि सममिति रूप से विचार नहीं किया गया और उनको विश्लेषण में प्रभावित नहीं किया गया तो सक्षम प्राधिकारी सभी संगत कारकों का विश्लेषण करने के लिए अपेक्षित 4.2 (क) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग की स्थिति का पूर्णतया सुनिश्चयन नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए घरेलू उद्योग की स्थिति, जिसका उत्पादन एक वर्ष में तेजी से कम हो जाता है परन्तु उसके पश्चात् पुनः अपना उत्पादन प्राप्त कर लेती है हालांकि उसके उत्पादन का स्तर शुरुआती स्तर से कम होता है, उसकी स्थिति उस उद्योग की स्थिति से बिलकुल भिन्न होगी जिसका उत्पादन संबंधित अवधि तक निरंतर कम होता रहता है। अंतिम बिन्दु का यह विश्लेषण दो मामलों में बिलकुल समान होना चाहिए जबकि वर्ष दर वर्ष आधार पर हुए परिवर्तनों और प्रवृत्तियों से संपूर्ण विरोधी निष्कर्ष निकल सकता है।"

"8.217 हम विश्वास करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान होने वाले परिवर्तन, विभिन्न क्षति कारकों में यह निर्धारण करने के लिए अनिवार्य होते हैं कि उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है या गंभीर क्षति की चुनौती आसन्न है। हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तियों पर विचार किए बिना अंतिम बिन्दु से अंतिम बिंदु की तुलना यथापेक्षित मूल्यांकन प्रदान नहीं करती है।"

17.2 उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि रक्षोपाय करार के उपबंधों में जांच की अवधि के लिए विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में अपने जांच परिणाम संदिग्ध भाषा में दिए गए हैं कि संगत जांच अवधि न केवल अभिनव विगत में समाप्त होनी चाहिए बल्कि जांच की अवधि अभी हाल ही का विगत होना चाहिए।

17.3 मोटे तौर पर आवेदक ने वर्तमान आवेदन-पत्र में घरेलू उद्योग की आयातों में वृद्धि के कारण कारित की जा रही गंभीर क्षति से रक्षा करने के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने हेतु रक्षोपाय जांच प्रारंभ किए जाने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार उसने अपने रक्षोपाय आवेदन-पत्र में आयात एवं घरेलू आंकड़ों के संबंध में सभी आंकड़े वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक (दिसम्बर 2013 तक) के आंकड़े, प्रदान कराए हैं जिससे गंभीर क्षति प्रदर्शित होती है और उन्होंने अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के रूप में अंतरिम राहत प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों की जांच करने के शुरुआत जांच शुरुआत का नोटिस दिनांक 13.02.2014 को जारी किया गया था। उसके पश्चात् घरेलू उद्योग में अप्रैल, 2014 के आस-पास इस कार्यालय को पुनः आया और अनुरोध किया कि आयातों में और अधिक तेजी से वृद्धि होने और उससे घरेलू उद्योग को भारी क्षति पहुंचाए जाने अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होने के कारण अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का तत्काल अधिरोपण किया जाना चाहिए घरेलू उद्योग की संवेदनशील परिस्थितियों तथा जनवरी 2014 से अप्रैल 2014 तक आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति में और अधिक पतन हुआ है, एतद्वारा उन्हें अन्तरिम राहत प्रदान न किए जाने पर उन्हें गंभीर क्षति कारित होगी जिसमें सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चयन की गई जांच अवधि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 है जो संवर्धित आयातों द्वारा कारित गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती पर विचार करने के लिए पर्याप्त हैं। तथापि अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करने की जरूरत का सुनिश्चयन करने हेतु संवेदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी है या नहीं उनकी जांच मासिक और त्रैमासिक आधार पर, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए जनवरी 2014 से अप्रैल 2014 तथा वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही से वर्ष 2014-15 तक की पहली तिमाही (अप्रैल 2014 के आंकड़ों का वार्षिकीकरण) तक के आंकड़ों, जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराया गया था, की मासिक और त्रैमासिक आधार पर जांच, जांच शुरुआत नोटिस के दौरान पहले से ही विचार किए गए आंकड़ों के अतिरिक्त की गई।

18. सूचना का स्रोत :

18.1 विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़े वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014 के अप्रैल माह के वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के वार्षिकीकृत आंकड़े (लेन-देन वार) आई वी आई एस मुम्बई से प्राप्त किए गए हैं और विश्लेषण के लिए विचारार्थ उन्हीं को लिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के घरेलू आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

18.2 घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में प्रस्तुत जांच की अवधि के लिए क्षति आंकड़ों पर भरोसा किया गया है जिनका इस विभाग द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन दौरा करके सत्यापन किया गया है और क्षति विश्लेषण पर विचार करने के लिए इन्हीं सत्यापित आंकड़ों को लिया गया है। क्षतिमार्जिन तथा लागत आंकड़ों को एक स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित आंकड़े याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए हैं।

19. संवर्धित आयात :

सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति का उल्लेख है और उसमें निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

“(1) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे, इस बात से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है कि उससे गंभीर क्षति हुई है अथवा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने की चुनौती उत्पन्न हो गई है तो यह उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए शासकीय राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी”।

19.1 इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 में ‘संवर्धित मात्रा’ को निम्नवत् परिभाषित किया गया है:

“संवर्धित मात्रा” में आयातों में वृद्धि शामिल होती है चाहे वह वृद्धि घरेलू उत्पादन के संबंध में हुई हो या संगत रूप से हुई हो”।

19.2 उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि विधि अर्थात् धारा 8ख और नियमावली में रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के लिए आयातों में एक मूलभूत पूर्वापेक्षा है। अतः यह निर्धारित करने के लिए कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों में “इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है” कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किया जा सकता है, नियमों में आयातों में समग्र रूप में या घरेलू उत्पादन के संगत रूप में हुई वृद्धि का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित होता है। यह भी देखा जाता है कि अभिव्यक्ति “संवर्धित मात्रा” को समावेशी रूप में परिभाषित किया गया है

और इस परिभाषा में दो पैरामीटर शामिल हैं अर्थात् आयातों में समग्र रूप से वृद्धि और आयातों में संगत रूप से वृद्धि। यह भी देखा जाता है कि यह जरूरी नहीं है कि यह दोनों पैरामीटर एक साथ मौजूद हों। संवर्धित मात्रा की तुलना या तो समग्र रूप में की जाए या घरेलू उद्योग के संगत रूप में। इस विधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक पैरामीटर की मौजूदगी/संतुष्टि पर्याप्त है।

19.3 डब्लू टी ओ पैनल और अपीलीय निकाय ने अंतरराष्ट्रीय विधि के इस मुद्दे का और अधिक स्पष्टीकरण किया तथा इन निकायों के निर्णयों के कुछ संगत उद्धरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

1. अर्जेंटीना-फुटवीयर (ई सी) (डब्लू टी/डीएस/आर दिनांक 25.06.1999) में पैनल ने इस बात की पुनः जांच की कि क्या किसी जांच की अवधि के शुरूआती बिंदु पर आयातों की मात्रा और उक्त अवधि की समाप्ति पर आयातों की मात्रा की तुलना (अंतिम बिन्दु से अंतिम बिन्दु की तुलना) के आधार पर संवर्धित आयातों के बारे में परिणाम निकालना अनुच्छेद 2.1 और 4.2 (क) से संगत है। इस बारे में पैनल ने बाद में अपीलीय निकाय के निर्णय की पुष्टि की और यह निष्कर्ष निकाला कि:

“8.156 यह आकलन करने में कि क्या आयातों में अंतिम बिन्दु से अंतिम बिंदु तक वृद्धि अनुच्छेद 2.1 के संवर्धित आयातों की जरूरत को पूरा करती है, किसी विशिष्ट वर्ष, जिसका प्रयोग अंतिम बिंदु के रूप में किया गया है की तुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रत्यक्ष शुरूआती निष्कर्ष की पुष्टि कर सकती है या उसको पलट सकती है। यदि शुरूआती बिंदु और/या जांच की अवधि के अंतिम बिंदु में केवल एक वर्ष का परिवर्तन कर देने का आशय यह हो कि यह तुलना आयातों में वृद्धि के बजाय गिरावट को प्रदर्शित करने लगती हो तो आयातों में हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति कम से कम अनिवार्यतः शुरूआती वृद्धि के समनुरूप हो अतः यह निष्कर्ष निकाला गया हो कि आयातों में वृद्धि हुई है।”

“8.157 दूसरे शब्दों में आयातों में वृद्धि वास्तव में मौजूद है तो यह अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु दोनों की तुलना में स्पष्ट होनी चाहिए और उक्त अवधि के दौरान मध्यस्थ प्रवृत्ति के विश्लेषण में भी यह स्पष्ट होना चाहिए। यह कि दोनों विश्लेषण परस्पर प्रवलनकारी होने चाहिए। जबकि यहां यदि उनके परिणाम में संपरिवर्तन होता है तो इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि आयातों में अनुच्छेद 2.1 के अर्थ में वृद्धि हुई है।”

19.4 अर्जेंटीना फुटवीयर (ई सी) में पैनल द्वारा पुनः यह जांच की गई कि, जिसे जिसकी अपीलीय निकाय द्वारा इस संबंध में विचार किए जाने पर एक जांच परिणाम में उत्तरवर्ती रूप से संपुष्टि की गई कि आयातों की हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना अनिवार्य है।

8.159 यह प्रश्न कि क्या आयातों में कोई गिरावट अस्थायी है यह आकलन करने के लिए संगत है या नहीं कि क्या संवर्धित आयात अनुच्छेद 2.1 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या नहीं। इस संदर्भ में हम अनुच्छेद 4.2 (क) की जरूरतों को पुनः स्मरण करते हैं कि ‘आयातों में वृद्धि की दर और राशि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हमारे विचार से इसमें एक अपेक्षा यह बनती है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों की हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। हम नोट करते हैं कि वाक्यांश ‘दर’ में गति और दिशा दोनों का उल्लेख है और इसलिए हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तियों (अधोगामी और उपरिगामी) पर पूर्णता: विचार किया जाना चाहिए। जहां यह प्रवृत्तियां जांच की अवधि के दौरान मिली जुली हैं वहां वे यह निर्धारित करने के लिए निर्णायक होंगी कि आयातों में यह वृद्धि अनुच्छेद 2.1 के आशय के अंतर्गत हुई है या नहीं। व्यावहारिक रूप में हम विचार करते हैं कि आयातों में ऐसी किसी मिली जुली प्रवृत्ति का विश्लेषण करने का सर्वोत्तम तरीका यह मूल्यांकन करना है कि क्या आयातों में कमी की कोई प्रवृत्ति अस्थायी अथवा यह दीर्घकालिक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है।”

19.5 अर्जेंटीना फुटवीयर (ई सी) में पैनल ने पुनः यह पाया कि उसके समक्ष उपस्थित मामले में आयातों की मात्रा में गिरावट को आयातों की मात्रा में वृद्धि के अस्थायी विपर्यय के रूप में पाया गया है। तब इसने उल्लेख किया कि :

8.161 “कारार में आयातों में न केवल वृद्धि (अर्थात् कोई वृद्धि) अपेक्षित है बल्कि यह वृद्धि इतनी अधिक ----- मात्रा में होनी चाहिए कि उससे क्षति कारित हो सके अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके ----- आयातों में यह वृद्धि इसके पूर्ण संदर्भ में निर्णीत की जानी चाहिए खासकर अनुच्छेद 4.2(क) में यथापेक्षित इसकी दर और राशि के संबंध में की जानी चाहिए। अतः संपूर्ण जांच अवधि के दौरान आयात के स्तर में परिवर्तन पर विचार करते हुए, जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, यह निर्धारण करते वक्त अपरिहार्य प्रतीत होता है कि क्या आयातों में यह वृद्धि ‘ऐसी मात्रा’ में हुई है जैसी अनुच्छेद 2.1 में अपेक्षित है।

19.6 अर्जेंटीना-फुटवीयर (ई सी) (डब्लू टी/डी एस/121/ए बी/आर दिनांक 14.12.1999) में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि आयातों में यह वृद्धि अभिनव, अचानक, तीव्र और इतनी अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि उससे गंभीर क्षति हो अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाए। वहां से संगत उद्धरण निम्नलिखित हैं:

131 “यह निर्धारण कि क्या आयातों में ‘इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि की जरूरत पूरी होती है या नहीं केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं होता है। दूसरे शब्दों में किसी जांच के लिए साधारण रूप से यह दर्शाना ही पर्याप्त नहीं होता है कि इस उत्पाद के आयात इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अथवा पांच वर्ष पहले हुए की तुलना में अधिक हुए हैं। पुनः, और यह दोहराया गया सा प्रतीत होता है कि केवल आयातों की कोई संवर्धित मात्रा ही पर्याप्त नहीं होगी। आयातों में वृद्धि इतनी अधिक मात्रा में हुई हो कि उससे रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने के लिए अपेक्षित घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न करने की जरूरत पूरी होती हो और रक्षोपाय कारार के अनुच्छेद 2.1 तथा गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX : 1(क) दोनों की भाषा यह अपेक्षा करती है कि आयातों में यह वृद्धि पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त

तीव्र और बहुत अधिक मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में हुई हो जिससे कि गंभीर क्षतिकारित की गई हो या गंभीर क्षतिकी चुनौती उत्पन्न हो गई हो।

19.7 यू एस व्हीट ग्लूटिन (डब्ल्यू टी/डी एस/166/आर दिनांक 31.7.2006) में पैनेल ने वाक्यांश "इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में" को निम्नवत् स्पष्टीकृत किया है:

8.31 गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX : 1(क) और रक्षोपाय करार (एस ए) के अनुच्छेद 2.1 में आयातों में केवल वृद्धि का उल्लेख नहीं है। बल्कि उनमें संबंधित उत्पाद के आयातों में वृद्धि की गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रकृति के संबंध में विशिष्ट जरूरतों का उल्लेख है। गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX : 1(क) तथा रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 में यह अपेक्षा की जाती है कि किसी संबंधित सदस्य के भू-भाग में किसी उत्पाद का आयात इतनी अधिक मात्रा में (घरेलू उत्पादन के समग्र एवं संगत रूप में) की जाती है जिससे गंभीरक्षति हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। अतः आयातों में केवल वृद्धि होना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि हम अर्जेंटीना-फुटवीयर रक्षोपाय मामले में अपीलीय निकाय के इस जांच परिणाम से सहमत हैं कि आयातों में यह वृद्धि परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में पर्याप्त रूप से अभिनव, अचानक, तीव्र और इतनी अधिक हुई हो कि उससे गंभीर क्षति कारित हुई हो अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।

19.8 'संवर्धित आयातों के संबंध में विधि की उपर्युक्त जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रयोजनमूलक एवं परिगणनीय आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण निम्नवत् किया गया है:

20. आयातों में वृद्धि (समग्र रूप में)

20.1 भारत में वसीय अल्कोहलों के आयात में समग्र रूप से एवं संगत रूप से तीव्र वृद्धि प्रदर्शित हुई है। दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 तक की अवधि के दौरान आंकड़ों का मासिक आधार पर तुलना करने से आयातों में 4304 एमटी से वृद्धि होकर 640 एमटी होने, अनुक्रमित स्केल पर 100 से वृद्धि होकर 149 होने का संकेत है, जिससे 49 की भारी वृद्धि हुई जिसे नीचे की तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1

विवरण	दिसम्बर, 2013	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014
आयात					
आयात (एमटी)	4304	4,605	5,942	7,629	6,402
प्रवृत्ति	100	107	138	177	149

20.2 इसी तरह, यदि हम तिमाहीवार आंकड़ों पर विचार करते हैं, तो आयात जो वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 13161 एमटी थे, बढ़कर चौथी तिमाही में 18176 एमटी हो गए और वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में इनमें और अधिक वृद्धि हुई तथा यह 19206 एमटी हो गए, अनुक्रमित स्केल पर यह वृद्धि 100 बिन्दुओं से बढ़कर 146 बिन्दु हो गई, जिससे एक बार फिर 46 प्रतिशत की भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई, जिसे अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है।

तालिका 2

	2013-14		2014-15
विवरण	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1 (अप्रैल, 2014 के आंकड़ों के अनुसार पर परिकलित)
आयात			
आयात (एमटी)	13161	18176	19206
प्रवृत्ति	100	138	146

21. उत्पादन के संबंध में आयातों में वृद्धि

21.1 दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 की अवधि के दौरान कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात के प्रतिशत में माहवार तुलना करने पर दोगुने से अधिक वृद्धि हुई अर्थात् यह दिसम्बर, 2013 में 30 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल, 2014 में 77 प्रतिशत हो गए, यही वृद्धि अनुक्रमित स्तर पर 100 से बढ़कर 256 हो गई, जो 156 बिंदुओं की भारी वृद्धि है जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

विवरण	दिसम्बर, 2013	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014
आयात (एमटी)	4304	4,605	5,942	7,629	6,402
कुल भारतीय उत्पादन	14279	12080	8892	11484	8311
कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात	30%	38%	67%	66%	77%
प्रवृत्ति	100	126	222	220	256

21.2 यदि हम तिमाहीवार आंकड़ों पर विचार करते हैं तो कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात का प्रतिशत वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 35 प्रतिशत से बढ़कर चौथी तिमाही में 56 प्रतिशत हो गया और फिर 2014-15 की पहली तिमाही में बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया, यही वृद्धि उसी अवधि के दौरान अनुक्रमित स्तर पर 100 से बढ़कर 159 से 218 प्वाइंट हो गई, जो 118 प्रतिशत बिंदुओं की तीव्र वृद्धि है, जैसाकि नीचे की तालिका से देखा जा सकता है :

	2013-14		2014-15
विवरण	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1 (अप्रैल, 2014 के आंकड़ों के अनुसार पर परिकलित)
आयात			
आयात (एमटी)	13161	18176	19206
कुल उत्पादन	37345	32456	24953
कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात	35%	56%	77%
प्रवृत्ति	100	159	218

22. संबंधित आयातों का निर्धारण

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इस मामले में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में संगत अवधि के दौरान उत्पादन के संबंध में और समग्र रूप से दोनों तरह से भारी वृद्धि हुई है। हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के विपरीत कि संबंधित आयातों में निरंतर वृद्धि नहीं हो रही है, मैं यह उपपादित करता हूँ कि आयात आंकड़े उनके तर्क का समर्थन नहीं करते हैं। मैंने यह पाया कि आयातों में मासिक आधार पर और तिमाही आधार पर, दोनों तरह से वृद्धि हो रही है और मेरे विचार से यह वृद्धि भारी तीव्र एवं आकस्मिक है जो रक्षोपाय शुल्क से संबंधित विधि के अंतर्गत आयातों से एकाएक वृद्धि की शर्त को पूरा करती है।

23. गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती

23.1 "गंभीर क्षति" का आशय घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र अपक्षयण होना है और "गंभीर क्षति की चुनौती" से आशय गंभीर क्षति का स्पष्ट एवं आसन्न संकट से है।

23.2 रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2 (क) और सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 8 के अनुबंध (2) में तकनीकी रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए कतिपय सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तथापि, इन प्रावधानों में यह विशेषीकृत नहीं किया गया है कि इन मूल्यांकनों में क्या प्रदर्शित होना चाहिए। इस तरह का किया गया प्रत्येक मूल्यांकन विभिन्न मामलों में किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर विभिन्न उद्योगों के लिए भिन्न-भिन्न होंगे। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन अनिवार्यतः यह नहीं दर्शाएगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही है। उदाहरण के लिए एक मामले में बिक्रियों, रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट हो सकती है जो उद्योग की स्थिति में भारी समग्र अवक्षयण को दर्शाता हो और इसलिए यह गंभीर क्षति के निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराएगी। वही दूसरे मामले में, हो सकता है कि कुछ कारकों में गिरावट न आ रही हों परंतु समग्र तस्वीर तब भी उद्योग की "भारी समग्र अवक्षयण" की स्थिति प्रदर्शित करती हो। इस प्रकार सभी सूचीबद्ध कारकों की और किसी अन्य संगत कारकों की तकनीकी जांच के अलावा यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी संगत कारकों के आलोक में किया जाए जिनका घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ता हो।

23.3 तदनुसार, अनंतिम शुल्क का अधिरोपण करने के विचारार्थ समालोचनात्मक परिस्थितियों का विश्लेषण करने में गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के सभी कारकों का, जिनका नियमावली में उल्लेख है, तथा अन्य कारकों पर, जो गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए संगत हों, पर निम्नवत् विचार किया गया है।

24. बाजार हिस्सा

24.1 दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 की अवधि के दौरान संवर्धित आयातों का बाजार हिस्सा जो दिसम्बर, 2013 में 72 प्रतिशत था, बढ़कर अप्रैल, 2014 में 80 प्रतिशत हो गया जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो दिसम्बर, 2013 में 15 प्रतिशत था, घटकर अप्रैल, 2014 में 9 प्रतिशत हो गया, जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :-

विवरण	दिसम्बर, 2013	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014
आयात					
आयात (एमटी)	4304	4,605	5,942	7,629	6,402
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	903	1,805	315	846	739
अन्य (गोदरेज) की बिक्री	780	980	755	927	844
कुल मांग (डीआई+अन्य+आयात)	5988	7390	7012	9402	7985
घरेलू बिक्रियों का बाजार हिस्सा (प्रतिशत)	15	24	4	9	9
आयातों का बाजार हिस्सा (प्रतिशत)	72	62	85	81	80

24.2 वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही से वर्ष 2014-15 (अप्रैल 2014 से आंकड़ों के आधार पर परिकलित) की पहली तिमाही से तुलना करने पर आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 70 प्रतिशत था (वर्ष 2014-15 की) पहली तिमाही में बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया, जबकि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 19 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत रह गया, जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

	2013-14		2014-15
विवरण	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1 (अप्रैल, 2014 के आंकड़ों के अनुसार पर परिकलित)
आयात			
आयात (एमटी)	13161	18176	19206
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	3557	2965	2217
अन्यों की बिक्री (गोदरेज)	2132	2662	2532
कुल मांग (डीआई+अन्य+आयात)	18850	23803	23955
घरेलू बिक्रियों का बाजार हिस्सा	19%	12%	9%
प्रवृत्ति	100	63	47
आयातों का बाजार हिस्सा	70%	76%	80%
प्रवृत्ति	100	109	114

25. उत्पादन

25.1 दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पाद 10396 एमटी से कम होकर 3652 एमटी हो गया अर्थात् अनुक्रमित बिंदु 100 से घटकर 35 हो गया। यही प्रवृत्ति कुल घरेलू उत्पादन में भी देखी जाती है (समर्थनकर्ता सहित) जो दिसम्बर, 2013 में 14279 एमटी से घटकर अप्रैल, 2014 में 8311 एमटी हो गई, जैसाकि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

विवरण	दिसम्बर, 2013	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014
उत्पादन (डीआई) एमटी	10,396	7,483	4,560	7,268	3,652
प्रवृत्ति	100	72	44	70	35
कुल उत्पादन	14279	12080	8892	11484	8311

25.2 तिमाहीवार आंकड़ों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग का उत्पादन जो वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 37345 एमटी था, घटकर वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) की प्रथम तिमाही में 24953 एमटी हो गया जैसा कि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

	2013-14		2014-15
विवरण	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1 (अप्रैल, 2014 के आंकड़ों के अनुसार पर परिकलित)
उत्पादन (डीआई) एमटी	25171	19311	10956
प्रवृत्ति	100	77	44
कुल उत्पादन	37345	32456	24953
प्रवृत्ति	100	87	67

26. बिक्रियां

26.1 दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां जो दिसम्बर, 2013 में 903 एमटी थी अप्रैल, 2014 में घटकर 739 एमटी रह गई अर्थात् दिसम्बर, 2013 में 100 अनुक्रमित बिंदु से घटकर अप्रैल, 2014 में 82 रह गई जैसाकि निम्नलिखित तालिका से परिलक्षित होता है :

विवरण	दिसम्बर, 2013	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	903	1,805	315	846	739
प्रवृत्ति	100	200	35	94	82

26.2 तिमाहीवार आंकड़ों पर विचार करते हुए वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में घरेलू बिक्री 3557 एमटी से घटकर वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में 2965 एमटी हो गई और वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में और अधिक घटकर 2217 एमटी हो गई अर्थात् उक्त अवधि के दौरान 100 अनुक्रमित बिंदुओं से घटकर 83 और अंततः 62 हो गए। यह प्रवृत्ति तिमाही रूप से और भी अधिक स्पष्ट है जैसाकि नीचे की तालिका में देखा जा सकता है :

	2013-14		2014-15
विवरण	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1 (अप्रैल, 2014 के आंकड़ों के अनुसार पर परिकलित)
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री	3557	2965	2217
प्रवृत्ति	100	83	62

27. क्षमता उपयोग

27.1 घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता संपूर्ण जांच की अवधि के दौरान और इस समय विश्लेषण के अधीन मासिक/तिमाही अवधि के दौरान समान बनी रही। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जो दिसम्बर, 2013 में 104 प्रतिशत था घटकर अप्रैल, 2014 में 37 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार इसमें लगभग 65 प्रतिशत की कमी आई जैसाकि अनुक्रमित पैमाने पर निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित होता है।

विवरण	दिसम्बर, 2013	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014
संस्थापित क्षमता घरेलू उद्योग	10000	10000	10000	10000	10000
क्षमता उद्योग घरेलू उद्योग	104%	75%	46%	73%	37%
प्रवृत्ति	100	72	44	70	35

27.2 तिमाही विश्लेषण पर यह देखा जाता है कि वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही से वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही की अवधि (अप्रैल, 2014 आंकड़ों के आधार पर परिकलित) के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग ने भी समान प्रवृत्ति प्रदर्शित की है अर्थात् घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जो वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 84 प्रतिशत था से घटकर वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 37 प्रतिशत हो गया, जो अनुक्रमित पैमाने पर लगभग 65 प्रतिशत की गिरावट है अर्थात् यह वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 100 से घटकर वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 44 रह गया जैसाकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

	2013-14		2014-15
विवरण	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1 (अप्रैल, 2014 के आंकड़ों के अनुसार पर परिकलित)
संस्थापित क्षमता घरेलू उद्योग	30000	30000	30000
क्षमता उद्योग घरेलू उद्योग	84%	64%	37%
प्रवृत्ति	100	76	44

28. रोजगार (अनुक्रमित)

यह देखा जाता है कि रोजगार के स्तर में भारी परिवर्तन हुआ जैसा कि यह मासिक आधार (दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 तक) और तिमाही आधार (वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही से वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही तक) (वार्षिकीकृत) दोनों रूपों में कमोबेश रूप से समान ही बना रहा जैसा कि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

मासिक आधार :

विवरण	दिसम्बर, 2013	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014
रोजगार	100	102	102	102	101

तिमाही आधार

	2013-14		2014-15
विवरण	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1 (अप्रैल, 2014 के आंकड़ों के अनुसार पर परिकलित)
रोजगार	100	101	100

29. उत्पादकता (अनुक्रमित)

ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता पर भारी प्रभाव पड़ा है जो प्रथमदृष्टया इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि घरेलू उद्योग के स्तर को बनाए रखा गया है, जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट होता है :

तालिका 1 (मासिक आधार)

विवरण	दिसम्बर, 2013	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014
उत्पादक (प्रतिदिन मी.टन.)	100	70	43	70	33

तालिका 2 (तिमाही आधार)

	2013-14		2014-15
विवरण	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1 (अप्रैल, 2014 के आंकड़ों के अनुसार पर परिकलित)
उत्पादकता (एमटी प्रतिदिन)	72	55	31

30. लाभ/हानि

घरेलू उद्योग ने जांच शुरुआत का नोटिस जारी होने के समय वर्ष 2013-14 के लिए दिसम्बर 2013 तक के आंकड़े प्रदर्शित किए थे। घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता की स्थिति में दिसम्बर, 2013 के पश्चात् अर्थात् जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2014 तक की अवधि के दौरान यह पाया गया कि लाभ/हानि के मासिक कर आंकड़े घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे उस क्रम में अनुरक्षित नहीं रखे जाते हैं। तथापि, उन्होंने संपूर्ण वर्ष 2013-14 (मार्च, 2014 तक) के सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित आंकड़े प्रदान कराए हैं क्योंकि उन्हें वित्त वर्ष 2013-14 का वित्तीय समापन अभी घोषित करना है। प्रस्तुत आंकड़े से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही में और अधिक गिरावट आई जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वित्त वर्ष	लाभ एवं हानि (रुपए/एमटीएस में) अनुक्रमित
2010-11	100
2011-12	-266
2012-13	-2796
2013-14 (दिसम्बर, 2013 तक)	-1696
2013-14	-2232

31. अन्य कारक

31.1 मांग के संबंध में आयात :

दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 की अवधि के दौरान कुल मांग के संबंध में आयातों का प्रतिशत जो दिसम्बर, 2013 में 72 प्रतिशत था बढ़कर अप्रैल, 2014 में 80 प्रतिशत हो गया जो अनुक्रमित पैमाने पर दिसम्बर, 2013 में 100 के स्तर से बढ़कर अप्रैल, 2014 में 111 हो गया जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

विवरण	दिसम्बर, 2013	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014
आयात (एमटी)	4304	4,605	5,942	7,629	6,402
कुल मांग (डीआई बिक्री+अन्य बिक्री + आयात)	5988	7390	7012	9402	7985
मांग के प्रतिशत के रूप में आयात	72	62	85	81	80
प्रवृत्ति	100	86	118	113	111

31.2 तिमाहीवार आंकड़ों पर विचार करते हुए कुल मांग के संबंध में आयात का प्रतिशत भी बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है अर्थात् यह वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 70 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 80 प्रतिशत हो गया। अनुक्रमित बिंदुओं के रूप में भी मांग के संबंध में आयात में उसी अवधि के दौरान 100 से वृद्धि होकर 109 तथा फिर 114 बिंदु हो गई जो निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है :

विवरण	2013-14		2014-15
	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1 (अप्रैल, 2014 के आंकड़ों के अनुसार पर परिकल्पित)
आयात (एमटी)	13161	18176	19206
कुल मांग (डीआई बिक्री+अन्य बिक्री + आयात)	18850	23803	23955
मांग के प्रतिशत के रूप में आयात	70%	76%	80%
प्रवृत्ति	100	109	114

32. निर्यात

32.1 अधोलिखित तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अप्रैल, 2013 से अप्रैल, 2014 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को निर्यात में भारी कमी का सामना करना पड़ा अर्थात् यह दिसम्बर, 2013 में 8406 एमटी से घटकर अप्रैल, 2014 में 2653 एमटी हो गया, जो अनुक्रमित पैमाने पर 68 प्रतिशत बिंदु की गिरावट है :

विवरण	दिसम्बर, 2013	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014
घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा (एमटी)	8,406	5,018	3,748	5,933	2,653
प्रवृत्ति	100	60	45	71	32

32.2 तिमाही आधार पर की गई तुलना में भी समान प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है, जैसाकि अधोलिखित तालिका में देखा जा सकता है, निर्यात जो वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में 19445 एमटी थे, घटकर वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) की पहली तिमाही में 7959 एमटी रह गए जो अनुक्रमित बिंदु पर 59 प्रतिशत की तीव्र गिरावट है।

	2013-14		2014-15
विवरण	तिमाही 3	तिमाही 4	तिमाही 1 (अप्रैल, 2014 के आंकड़ों के अनुसार पर परिकलित)
घरेलू उद्योग की निर्यात की मात्रा (एमटी)	19445	14699	7959
प्रवृत्ति	100	76	41

33. मालसूची

दिसम्बर 2013 से अप्रैल 2014 की अवधि के दौरान कोई मालसूची नहीं थी। यह भी प्रतीत होता है कि इस मालसूची का पंजीकरण वर्ष 2013-14 की दूसरी तिमाही में किया गया, उसके पश्चात् फिर कोई मालसूची नहीं हुई।

34. गंभीर क्षति और उसकी चुनौती का निर्धारण

34.1 उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह नोटिस किया जाता है कि वसीय अल्कोहल के संवर्धित आयातों ने वसीय अल्कोहल के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी है क्योंकि लगभग सभी कारकों में अवक्षयण प्रदर्शित होता है। यह भारी समग्र अवक्षयण तत्काल अनंतिम शुल्क का अधिरोपण करने पर विचार करने के लिए संवेदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी की जांच करने हेतु विश्लेषणार्थ ली गई अवधि अर्थात् दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 (माहवार आधार पर) तथा वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही और वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही (वार्षिकीकृत) (तिमाही आधार पर) में स्पष्टतः विवेकाधीन है। उत्पादन और बिक्री में तीव्र गिरावट आई है तथा उत्पादकता में प्रणाली गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में भी घाटा हुआ है जो आयातों में समग्र और संगत दोनों रूपों में प्रपाती उछाल से स्पष्ट है। वास्तव में एक ओर घरेलू उद्योग का लगभग सभी आर्थिक पैरामीटरों में कमजोर प्रदर्शन और दूसरी ओर आयातों में जांच शुरुआती के नोटिस की अवधि के तत्काल पश्चात् प्रपाती वृद्धि, किसी ऐसे साधन की तत्काल जरूरत को स्पष्टतः दर्शाती है जो आयातों में इस वृद्धि को रोक सके, ऐसा न करने पर घरेलू उद्योग को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसमें सुधार करना दुष्कर हो जाएगा।

34.2 यह भी देखा जाता है कि आशियान देशों (ए आई एफ टी ए) से प्रशुल्क अवरोध कम होने के कारण आयातों में तीव्र वृद्धि हुई जिसने घरेलू उद्योग को पहले ही गंभीर क्षति कारित की है। तथापि, ऊपर नोटिस किए गए रुझान के अनुसार, यह स्थिति बने रहने की संभावना है और आने वाले समय में उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने की संभावना है।

35. कारणात्मक संबंध

35.1 सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपायशुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1977 का नियम 5(3)(ग) यह उल्लेख करता है कि संवर्धित आयातों तथा कथित क्षति या क्षति की गंभीर चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध अपेक्षित होता है।

35.2 कारणात्मकता का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन सभी प्रयोजनात्मक एवं परिणात्मक प्रकृति के संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाता है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

35.3 उपर्युक्त विश्लेषण से यह उपपादित किया जाता है कि आयात एवं घरेलू आंकड़ों का मासिक और तिमाही दोनों तरह से विश्लेषण करने पर आयातों में समग्र रूप से तथा उत्पादन के संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है। आयातों के बाजार हिस्से में दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 में और वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही से लेकर वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही (वार्षिकीकृत) में पर्याप्त वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में तेजी से गिरावट आई है। यह स्पष्टतः आयातों में भीषण वृद्धि और इस मामले में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करता है।

35.4 इसके अतिरिक्त, उसी अवधि के दौरान, यह देखा गया कि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है जिसके कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि होनी चाहिए थी। परंतु घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई जबकि आयातों में तीव्र वृद्धि हुई, यह वह स्थिति है जिसमें घरेलू उद्योग की पहले से ही खराब आर्थिक स्थिति को और भी अधिक तीव्र बना दिया है। उसी अवधि अर्थात् वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही के दौरान इन घाटों में और अधिक वृद्धि हुई है जो घरेलू उद्योग की नाजुक आर्थिक को प्रदर्शित करता है। इसलिए मैं यह पाता हूं कि यदि इस स्थिति का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसका समाधान/सुधार/पुनरुत्थान मुश्किल हो जाएगा।

36. हितबद्ध पक्षकारों के विचारों की जांच

घरेलू उद्योग के अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण करने की मांग से निपटते वक्त मुझे हितबद्ध पक्षकारों के कई जांच शुरुआत पश्चात प्रस्तुतिकरण भी प्राप्त हुए जिनसे उनमें से कुछ ने कतिपय मुद्दे उठाए थे। तदनुसार, वर्तमान रक्षोपाय जांच में जांच शुरुआत पश्चात् प्रस्तुतिकरणों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का संक्षेप में निम्नलिखित समाधान किया गया है।

36.1 याचिकाकर्ता का आवेदनपत्र दायर करने का कोई स्थानीय आधार नहीं तथा उसके ईओयू दायित्व पर विचार किया जाए।

36.1.1 कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता रक्षोपाय प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षण की मांग करने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि वह एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है। इस संदर्भ में उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी के चीन जन गण से सेफ्टिआक्सोन डायसोडियम हेमीहेप्टाहाइड्रेट स्टाराइल (दिनांक 2 जुलाई, 2008 के अंतिम जांच परिणाम पर) मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा व्यक्त किया है। पाटनरोधी नियमावली प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत वे उत्पादकों का "घरेलू उद्योग" के दायरे से अपवर्जन कर दिया जाता है जो आयातक या आयातक अथवा निर्यातक से सहबद्ध हों। तथापि, उक्त जांच परिणाम में इओयू ने जांचाधीन उत्पाद का भारी मात्रा में आयात किया है और चूंकि पाटनरोधी शुल्क विधि के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयातकों को विशेष रूप से बाधित किया गया है, इसलिए उस मामले में उसे घरेलू उद्योग के दायरे से अपवर्जित कर दिया गया था। चूंकि रक्षोपाय प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे किसी अपवर्जन का प्रावधान नहीं किया गया है इस हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को निराधार पाया गया है।

36.1.2 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पुनः यह तर्क दिया गया है कि उस घरेलू बिक्री की प्रमात्रा पर प्रतिबंध है जो निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा की जा सकती है। इसकी जांच की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने के अध्यधीन है, ईओयू यूनिट/याचिकाकर्ता द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु की बिक्री करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात् भारत में घरेलू रूप से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री करने पर तब तक कोई प्रतिबंध नहीं है जब तक ईओयू यूनिट द्वारा सकारात्मक एनएफई अनुरक्षित है। विदेश व्यापार नीति में उस उत्पाद की घरेलू निकासी (निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत तक) पर शुल्क की रियायती दर का प्रावधान है। इसलिए वर्तमान मामले में अन्य उत्पादों में अर्जित हकदारी का प्रयोग वसीय अल्कोहलों के लिए निर्यात के कुल एफओबी मूल्य का 90 प्रतिशत तक किया जा सकता है। उपर्युक्त सीमा के परे ईओयू/याचिकाकर्ता द्वारा बिक्री समुचित उत्पादकर का भुगतान करके की जा सकती है। इसलिए जब तक सकारात्मक एनएफई है तब तक भारत में ईओयू द्वारा विनिर्मित वस्तु की बिक्री करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संदर्भ में घरेलू उद्योग ने विटामिन "ए" मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी (पाटनरोधी) के जांच परिणाम के पैराग्राफ 34 पर भरोसा किया है जिसमें पीरामल हेल्थकेयर (एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई) को घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है :

“इस संबंध में कि घरेलू उद्योग एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई है और इसलिए वह घरेलू उद्योग बनने की पात्र नहीं है, यह नोट किया जाता है कि ईओयू की सुविधा स्वतः ही याचिकाकर्ता की "घरेलू उद्योग" के रूप में स्थिति पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। वास्तव में, यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र के अंतर्गत की गई निकासी विचाराधीन के निर्यातों के संबंध में प्रतिबंधित या आपातक नहीं है और इसलिए उन्हें उत्पाद कर संदत्त घरेलू बिक्रियों के रूप में माना गया है, न कि आयातों के रूप में। इस प्रकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादन के लिए उत्तरदायी है और इस प्रकार वह नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

36.1.3 पुनः यह प्रस्तुत किया गया है कि एक निर्यातोन्मुख इकाई भी एक घरेलू इकाई है और इसकी निकासियों को आयातों के रूप में नहीं मानना चाहिए। विक्रम इस्पात बनाम केंद्रीय उत्पाद कर आयुक्त मामले में जिसे 2000 में (120) ईएलटी 800 अधिकरण दिल्ली (एलबी) के तहत रिपोर्ट किया गया था, माननीय न्यायाधिकरण ने यह धारित किया कि ईओयू द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों को आयात के रूप में नहीं माना जाता है और उन्हें घरेलू वस्तु के रूप में माना जा सकता है। संगत पैराग्राफ को (पैरा 16) यहां उद्धृत किया जाता है :

“राजस्व सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत संदत्त अतिरिक्त सीमा शुल्क के संघटक को मोडवैट क्रेडिट की उपलब्धता को यह कल्पना करके प्रतिबंधित करना चाहता है कि 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई वह स्थान होता है जो भारत में नहीं होता है और उसके द्वारा भारत में की गई बिक्री को भारत में आयातों के समान माना गया है। हम राजस्व के इन विचारों को ठोसपन नहीं पाते हैं। किसी 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा की गई निकासी उस रूप में आयात नहीं है जिस रूप में उसे सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 2(23) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अपने व्याकरणिक और अकाद्व्य अभिव्यक्ति के रूप में आयात का आशय भारत से बाहर स्थित किसी वस्तु को भारत में लाना है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि जब किसी 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा किसी वस्तु की निकासी भारत में की जाती है तो केंद्रीय उत्पाद कर अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद कर का उदग्रहण किया जाता है न कि सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा-शुल्क का। यदि वे आयात के रूप में माना जाता है तो इस पर सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत शुल्क प्रभारित किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व को कर मापन के साथ-साथ कर की प्रकृति के संदर्भ में संभ्रम में है। किसी 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई से किसी वस्तु उदग्रहित शुल्क की प्रकृति उत्पाद कर होती है न कि कोई अन्य, जबकि शुल्क की प्रमात्रा का निर्धारण करने के लिए अपनाया गया साधन सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत विधिवत उदग्रहण करने योग्य होता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित कई मामलों में धारित किया गया है। कर वसूली करने के लिए विधि निर्माताओं द्वारा अपनाए गए तरीके से इसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जहां एक बार यह धारित हो जाता है कि किसी 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा भारत में किसी स्थान पर निकासी की गई वस्तु के संबंध में लगाया गया शुल्क उत्पाद कर होता है, इसलिए उक्त शुल्क को आधारभूत सीमा शुल्क, अनुषंगी शुल्क, सीमा-शुल्क का अतिरिक्त कर, या किसी अन्य सीमा शुल्क के रूप में विभिन्न घटकों में संविभाजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। एआर-1क का प्रपत्र जिस पर विद्वान डीआर द्वारा भरोसा जताया गया है, उस विधिक स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता है कि 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई पर उदग्रहित शुल्क उत्पाद कर होता है, न कि सीमाशुल्क।”

36.1.4 कास्को ब्लासम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा-शुल्क आयुक्त, 2004 (164) ईएलटी 423 (अधि. दिल्ली) में रिपोर्ट किए गए, मामले में माननीय न्यायाधिकरण ने पुनः दोहराया कि किसी निर्यातोन्मुख इकाई द्वारा घरेलू रूप से क्लीयर की गई वस्तु को घरेलू वस्तु के रूप में माना जाता है। संगत पैराग्राफ नीचे उद्धृत किया जाता है :

“5. यह सुस्थापित 2000 (120) ईएलटी 800 है कि किसी निर्यातोन्मुख इकाई में उत्पादित वस्तु को आयातित वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है और उन पर सीमा-शुल्क नहीं लगाया जाता है। इन वस्तुओं के संबंध में संदेय शुल्क केंद्रीय उत्पादकर अधिनियम 1944 की धारा 3 के अंतर्गत उत्पादन कर होता है। इसलिए, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत उल्लिखित आदेश में की गई शुल्क की मांग संधारणीय नहीं है। तदनुसार, हम उस आदेश को दरकिनार करते हैं और वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं। तथापि, हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि राजस्व प्राधिकारियों को आयातित इनपुटों, यदि कोई हों, जिनका प्रयोग प्रश्नावधीन कट-फ्लावर्स का उत्पादन करने के लिए किया गया है, पर शुल्क की मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं।”

36.1.5 इसलिए उपर्युक्त के मद्देनजर हम घरेलू उद्योग के इस तर्क से सहमत हैं कि कोई निर्यातोन्मुख इकाई, भारत से बाहर स्थित इकाई नहीं होती है और इसलिए वह घरेलू उद्योग का ही एक भाग होती है और इसलिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क में कोई गुण नहीं है।

37. कुछ प्रकार के उत्पादों के लिए आयातों में कोई उद्रेक नहीं अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विश्लेषण करने के आधार पर वर्ष 2013-14 में आयातों में असमुचित विश्लेषण करने के आधार पर वर्ष 2013-14 में आयातों में कोई उद्रेक नहीं आया है और यह कि आयातों में वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ प्रकार के विचाराधीन उत्पाद के ऐसे चयनित विश्लेषण का कुछ हितबद्ध पक्षकारों के दावे में कोई संगतता नहीं है और वह विधि के अंतर्गत अनुमेय नहीं है। विधि में बिना किसी भेदभाव के सभी स्रोतों से कुल आयातों का विश्लेषण करने का प्रावधान है और यह उपपादित किया गया है कि वसीय अल्कोहलों के आयात उच्च स्तर पर हैं तथा यह बढ़ते रहेंगे। अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना तथा मासिक एवं तिमाही आधार पर हस्ताक्षेपकारी प्रवृत्तियों का विश्लेषण इंगित करता है कि आयातों में यह वृद्धि समग्र रूप से तथा घरेलू उद्योग के संगत रूप से दोनों से हो रही है। इसलिए आयातों में उद्रेक जांचाधीन उत्पाद के संबंध में, न कि उसके ग्रेडों/टाइपों के संबंध में देखा जाना चाहिए।

38. अन्य भारतीय उत्पादकों को कोई क्षति नहीं

एक हितबद्ध पक्षकार का यह तर्क है कि अन्य उत्पादक अर्थात् मैसर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज को कोई क्षति नहीं हुई, पूर्णतया गलत है। अन्य उत्पादक भी इस उत्पाद के लिए घाटा उठा रहा है। वार्षिक रिपोर्ट से उल्लिखित अधिकांश प्रेक्षण ओलियोकैमिकल प्रभाग तथा बाजार में उसकी स्थिति से संबंधित हैं। वे इस विचाराधीन उत्पाद के लिए इस अन्य उद्योग की स्थिति को साराहने में असफल रहे। वसीय अल्कोहल के लिए घरेलू बाजार में अन्य उत्पादक की स्थिति क्षति अवधि के दौरान बदतर हुई है, जो 18 प्रतिशत से कम होकर 11 प्रतिशत हो गई।

39. संवेदनशील परिस्थितियां

39.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरणों और क्षति पैरामीटरों का विश्लेषण करने पर यह पाया जाता है कि घरेलू उद्योग ने तत्काल अंतरिम रक्षोपाय साधन का अधिरोपण करने का अनुरोध किया है। संवेदनशील परिस्थितियों के मद्देनजर उन्होंने अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किये जाने की मांग की है।

39.2 दिनांक 29.07.1997 की अधिसूचना संख्या 35/97-एनटी-सीमाशुल्क के तहत अधिसूचित सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 9 में यह प्रावधान है कि महानिदेशक शीघ्र ही एक जाँच का आयोजन किये जाने की कार्यवाई करेंगे और संवेदनशील परिस्थितियों में वह गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के संबंध में प्रारंभिक जाँच परिणाम रिकार्ड करेंगे/करेंगी। इस जाँच को शासित करने वाले सिद्धांतों का उल्लेख सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 15 में, उस स्थिति में रक्षोपाय शुल्क के रिफंड का प्रावधान है। यदि जाँच के निष्कर्ष के पश्चात अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क पहले से ही अधिरोपित एवं संग्रहित अनन्तिम शुल्क से कम है। नियमावली के नियम 6, 9 और 15 का सुमेलीकृत पाठन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नियमावली में प्रारंभिक जांच परिणाम के आधार पर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क की तत्काल सिफारिश करने और यदि यह निश्चय हो जाता है कि नियम 6 में उल्लिखित प्राकृतिक न्याय के अनुसरण में जांच के निष्कर्ष के पश्चात अधिरोपित शुल्क अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क से कम है तो इस विभेदकारी शुल्क का रिफंड किया जाएगा। तथापि, संवेदनशील परिस्थितियों में अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण में विलंब ऐसी क्षति पहुँचा सकता है जिसकी भरपाई करना दुष्कर हो।

39.3 तदनुसार, यह आकलन करने के लिए परिस्थितियों का विश्लेषण करना बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया है कि क्या वह संवेदनशील परिस्थितियों की श्रेणी में आती है या नहीं। दिसम्बर, 2013, की तुलना में जनवरी, 2014 तक आयातों में अचानक उद्रेक तथा घरेलू उद्योग के तदनुसारी निष्पादन पर संवेदनशील परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए मासिक (दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 तक) आधार पर तथा तिमाही से वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही, अप्रैल, 14 के आधार पर (वार्षिकीकृत) विचार किया गया है।

39.4 आयातों में वर्ष 2013-14 तक आधार वर्ष तथा विगत वर्ष दोनों की तुलना में वृद्धि हुई है। आयातों में इस वृद्धि की समान प्रवृत्ति मासिक और तिमाही आधार पर उपर किये गये विश्लेषण में प्रदर्शित होती है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, लाभप्रदत,

निवेश पर अर्जन, घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है। याचिकाकर्ता की स्थिति जनवरी, 2014 से अप्रैल, 2014 की अवधि के दौरान और भी बदतर हो गई जब आयात उच्च स्तर पर थे।

39.5 कतिपय श्रोतों से वसीय अल्कोहल के आयात पर शुल्क दिनांक 01.01.2014 से हटा लिया गया है। इस कमी की प्रत्याशा में तीसरी तिमाही में आयातों में कमी आई। इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता अपने ग्राहकों को प्रतिधारित रखने में सक्षम रहा। सीमा-शुल्क समाप्त कर दिये जाने के पश्चात्, वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में आयातों में भीषण वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग की स्थिति बदतर हो गई।

39.6 यह देखा जा सकता है कि विगत अवधि की तुलना में घरेलू उद्योग के निष्पादन में पिछली तिमाही में भारी गिरावट आई है। तीसरी तिमाही में हुए किसी मामूली से सुधार को चौथी तिमाही में पूरी तरह से धो डाला गया। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को इन आयातों के कारण गंभीर कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण और कीमत निग्रहण का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उद्योग के लाभ में भी तीसरी तिमाही में भारी कमी आई है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि गंभीर क्षति कारित की गई है और गंभीर क्षति की चुनौती आसन्न है। क्षति एवं आयातों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित हो गया है।

39.7 इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि इस मामले में आयातों में तीव्र वृद्धि के समनुरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आने से मेरा यह विचार है कि इससे घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए आयातों में उद्रेक तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट लगभग सभी प्राचलों में, ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी की संपुष्टि करती है जिससे और अधिक गिरावट को रोकने के लिए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का तत्काल अधिरोपण करना जरूरी हो जाता है। चूंकि हालात बद से बदतर हुए हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस विचाराधीन उत्पाद पर अनंतिम शुल्क का अधिरोपण करने में किया गया थोड़ा सा विलंब घरेलू उद्योग के हित में नहीं होगा क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियों को देखा गया है जिससे इस स्थिति में और अधिक गिरावट आएगी तथा यह संकट और अधिक बढ़ेगा।

40. अनपेक्षित परिस्थितियां:

40.1 यह नोट किया जाता है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) ऐसी कोई अभिव्यक्त प्रतिबद्धता/ अपेक्षा नहीं है कि वह अनपेक्षित परिस्थितियों का विश्लेषण करें क्योंकि क्रियापद्धति संबंधी भारतीय नियमों में ऐसी कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं है जिसका अनपेक्षित परिस्थितियों का विश्लेषण करते वक्त अनुसरण किया जाए या रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में भी क्रियापद्धति संबंधी ऐसा कोई नुस्खा नहीं है जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए या ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसे अनपेक्षित विकास का निर्धारण करते वक्त पूरा किया जाना चाहिए।

40.2 अर्जेन्टीना फुटवियर (ईसी) मामले में अपील निकाय ने यह धारित किया कि "अनपेक्षित विकास" की आवश्यकता रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए एक पृथक "शर्त" नहीं है परन्तु उसे "परिस्थितियों" के एक निर्धारित सेट के रूप में वर्णित किया गया है।

40.3 अर्जेन्टीना फुटवियर मामले में (ईसी) अपील निकाय ने यह धारित किया कि पदबंध "अनपेक्षित विकास" का आशय ऐसे विकास से होता है जो अप्रत्याशित हो। 'अनपेक्षित विकास' में यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास 'अप्रत्याशित' होना चाहिए जिसके कारण इस उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थिति में आयात हुआ कि उससे घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई अथवा उनके समक्ष गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई। कोरिया डेयरी मामले में अपील निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित विकास वह विकास है जो उस समय पेक्षित या प्रत्याशित न हों जब सदस्य ने वह प्रतिबद्धता अर्जित की।

40.4 मैं उपपादित करता हूँ कि इस संदर्भ में आवेदक ने निम्नवत् अर्ज की है कि भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर एवं अपूरणीय क्षति पहुंची। कुछ हितवद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह स्थिति तो स्पष्टतः पेक्षित थी क्योंकि एफटीए में समयबद्ध न्यूनीकरण करने और प्रासंगिक रूप से आयात प्रशुल्क अवरोधों का उपशमन करने के लिए अंतःनिमित्त दिशानिर्देश थे। मैं हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क से उस सीमा तक सहमत हूँ कि एफटीए के प्रावधानों में प्रशुल्क का न्यूनीकरण करने और तर्कसंगत प्रत्याशा रखने की पहले से ही प्रकल्पना की गई है कि इसके कारण आयातों में वृद्धि हो सकती है। तथापि, इस आयात प्रशुल्क का न्यूनीकरण/ उपशमन करने से अप्रैल, 2014 तक की अत्यधिक अभिनव अवधि तक आयातों में असाधारण गति और अप्रत्याशित त्वरण से उद्रेक हुआ। यह आयात प्रशुल्क सम्बर्धित आयातों के लिए सभी विधिक सीमाएं लांघ गया। दिसम्बर, 2013 से अप्रैल, 2014 की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद में अभूतपूर्व उद्रेक तथा वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही से वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 46-49 प्रतिशत तक की वृद्धि यह इंगित करती है कि देश में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग की तुलना में आयातों में भारी वृद्धि लगभग 33 प्रतिशत (प्वाइंट) स्पष्टतः अनपेक्षित परिस्थिति थी। आयातों में इतनी वृद्धि, जो सम्पूर्ण जांच की अवधि के दौरान बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता रहा, इसलिए अनपेक्षित परिस्थिति प्रतीत होती है।

41. जनहित

घरेलू उद्योग द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य आयातों के उद्रेक द्वारा धारित क्षति का उपशमन करना है। चूंकि भारत में सस्ते आयातों में प्रपाती उद्रेक रहा है, जिसके द्वारा बढ़ती मांग के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि नहीं हुई और घरेलू

उद्योग को नुकसान उठाना पड़ा। इसके अतिरिक्त आयातों में प्रपाती वृद्धि से घरेलू उद्योग की लाभप्रदायकता में भी ऐसे नाजुक स्तर तक गिरावट आई कि इस घाटे में वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही की तुलना में वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसलिए देश में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अबोध वृद्धि को रोकने तथा घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति से बचाने के लिए तत्काल कोई उपाय करना तर्कसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। चूंकि कोई भी रक्षोपाय शुल्क से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी और इससे घरेलू उद्योग की और अधिक गिरावट होने पर रोक लगेगी तथा उपभोक्ताओं को इस संबद्ध वस्तु की व्यापक उपलब्धता होने में सहयोग लेगा, इसलिए मैं यह उपपादित करता हूँ कि ऐसा करना जनहित में होगा।

42. समायोजन योजना

घरेलू उद्योग ने अपने मूल आवेदन पत्र में समायोजन योजना प्रदान कराई थी जिसमें इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में लगभग 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक समायोजनों पर बल दिया गया था। उसमें की गई प्रकल्पना के अनुसार कच्चे माल अर्थात् विखण्डित पाम गिरी का तेल के अधिप्रापण में लागत लाभ का मुकाबला करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग हने ओलियो रसायनों का उत्पादन करने के लिए मेडान, इण्डोनेशिया में एक नई हरित क्षेत्र परियोजना की स्थापना करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी जो भारतीय प्रचालनों के लिए मध्यवर्ती उत्पादों की आपूर्ति का एक स्रोत होगा। ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार इससे, एसपीकेओ प्रदान करके, तलोजा, भारत में स्थिति इसके वसीय अल्कोहल संयंत्र को सहायता प्राप्त होगी जो किसी एक निर्यातक देश द्वारा पाम और पाम गिरी के तेल पर निर्यात कर में अक्सर होने वाले परिवर्तनों से भारतीय प्रचालनों की रक्षा होगी। मैं यह उपपादित करता हूँ कि इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल सेगमेंट में लागत बचत के लिए घरेलू उद्योग द्वारा यथा परिकल्पित समायोजन योजना एक अर्थक्षम समायोजन योजना प्रतीत होती है।

43. विचाराधीन उत्पाद का वित्त वर्ष 2013-14 में अन्य विकासशील देशों से आयात (न्यूनतम) आयात आंकड़ों से यह देखा जाता है कि मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य विकासशील देशों से इस विचाराधीन उत्पाद के भारत को कुल आयात व्यक्तिगत रूप से 3 प्रतिशत से और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। इसलिए मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य विकासशील देशों में उदभवित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परंतुक में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट नहीं होगा।

44. निष्कर्ष

मैं वर्तमान मामले में उपपादित करता हूँ कि संवेदनशील परिस्थितियां मौजूद हैं और इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अचानक एवं प्रपाती वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में प्रपाती गिरावट को देखते हुए अंतरिम उपाय करना अधिदेशित है। अतः, यदि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने में कोई विलंब किया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति होगी। तदनुसार इस मामले में वांछित गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती का अंतिम निर्धारण लंबित रहने तक अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का तत्काल अधिरोपण किया जाना चाहिए।

45. सिफारिश

45.1 उपर्युक्त उपपत्ति को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि "सी8, सी10, सी12, सी14, सी16 और सी18 की कार्बन शृंखला लंबाई के, एकल, मिश्रण एवं असम्मिश्रित (जिनमें शाखायुक्त आइजोमर्स शामिल नहीं हैं) जिसमें सी12, सी14, सी12-सी16, सी12-सी18, सी16-18 तथा सी14-सी16 की कार्बन शृंखला लंबाई के संयोजन के सम्मिश्रण (जिन्हें सामान्य सी12-सी16 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है) सहित अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों" अर्थात् "पीयूसी" के भारत में संवर्धित आयातों ने इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित की है या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 6 के साथ पठित सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 10 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के भारत में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जनहित में होगा। लगाई गई पूंजी पर तर्कसंगत आवक की अनुमति देने के पश्चात् घरेलू उत्पादकों द्वारा इस विचाराधीन उत्पाद की औसत उत्पादन लागत पर विचार करते हुए, सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्षक संख्या 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 और 29051700 (केवल संकेतात्मक प्रकृति के) अंतर्गत आने वाले "सी8, सी10, सी12, सी14, सी16 और सी18 की कार्बन शृंखला लंबाई के, एकल, मिश्रण एवं असम्मिश्रित (जिनमें शाखायुक्त आइजोमर्स शामिल नहीं हैं) जिसमें सी12, सी14, सी12-सी16, सी12-सी18, सी16-18 तथा सी14-सी16 की कार्बन शृंखला लंबाई के संयोजन के सम्मिश्रण (जिन्हें सामान्य सी12-सी16 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है) सहित अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों" पर, जिनका आयात किया जा रहा है, 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) यथामूल्य की दर से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क, जिसे घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता के रूप में माना जाता है, एतद्वारा 200 दिनों के लिए अधिरोपित करने की सिफारिश की जाती है।

45.2 चूंकि मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों से आयात व्यक्तिगत रूप से 3 प्रतिशत से अधिक तथा सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होते हैं इसलिए मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों में उद्भवित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के परंतुक में उल्लिखित शर्तों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट नहीं होगा।

46. अगली प्रक्रिया

- (i) विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान कराई गई सूचना, जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां सत्यापन के अधीन होगी, जिसके लिए उन्हें अलग से सूचित किया जाएगा।
- (ii) अंतिम निर्धारण करने से पहले उचित समय पर एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी।

[फा. सं. डी-22011/26/2013]

आर. के. सिंगला, महानिदेशक

**DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS
(CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2014

Subject : Safeguard investigation concerning imports of “Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8,C10,C12,C14,C16, and C18 including single, blends and unblended (Not including branched isomers) which includes blends a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18,C-16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14) ” hereinafter referred to as ‘PUC’ (Product Under Consideration) into India – Preliminary findings.

G.S.R. 357(E).—having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

(A) Procedure

1. An application has been filed before me under Rule 5 of the Custom (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as “Safeguard Rules”] by M/s. VVF (India) Limited, Mumbai, 100% Export Oriented Unit seeking imposition of Safeguard Duty on imports of “ Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8,C10,C12,C14,C16, and C18 including single, blends and unblended (Not including branched isomers) which includes blends a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18,C16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14) ” hereinafter referred to as ‘PUC’ (Product Under Consideration) into India, as shown in the petition alleging that increased imports of "PUC" was causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producer and to protect the domestic producer against market disruption and threat of market disruption caused by the increased imports of "PUC" into India.

2. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met with, safeguard investigation against imports of "PUC" was initiated vide notice of initiation dated 13th February, 2014 and published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day.

3. A Copy of the Notice of Initiation dated 13th February, 2014 along with copy of non-confidential version of the application filed by the domestic industry were forwarded to the Central Government in the Ministry dealing with Commerce and other Ministries concerned, related embassies in New Delhi and known interested parties listed below :

3.1 EXPORTERS

- (1) **Emery Oleochemicals**, Level 5, Building E, Peremba Square, Saujana Resort, Section U2 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
- (2) **Wilmar International Limited**, 56 Neil Road Singapore 08883.
- (3) **P&G Chemicals**. Procter & Gamble International Operations SA Singapore Branch, 238A Thomson Road #20-01/10, Novena Square Tower A, Singapore 307684.
- (4) **Sasol Limited**. Sasol Germany GmbH Anckelmannsplatz 120537 Hamburg.
- (5) **KLK Oleo**. Level 8, Menara KLK, No.1, Jalan PJU 7/6 Mutiara Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor DarulEhsan, Malaysia.
- (6) **Musim Mas**. PT Musim Mas Jl KL YosSudarso KM 7,8TanjungMulia - Medan 20241 North Sumatra – Indonesia.
- (7) **EcogreenOleochemicals (Singapore) Pte Ltd**. 99 Bukit Timah Road # 03-01 Alfa Centre, Singapore – 229835
- (8) **FPG OleochemicalsSdnBhd**, FPG OleochemicalsSdn. Bhd.(184896-U) Lot 3831 Kuantan Port Industrial Area, TanjungGelang, PO Box 26, PejabatPosBalok, 26080 Kuantan, Pahang DarulMakmur, MALAYSIA.
- (9) **Kao Corporation**, Pilipinas Kao, Inc. A Kao Group Company 7th Floor Tower One & Exchange Plaza Ayala Triangle, Ayala Avenue, 1226 Makati City, Philippines.
- (10) **Thai Oleochemicals Co. Ltd**. 123 Suntowers Building A,14th, Vibhavadi - Rangsit Road, Chomphon Chatuchak Bangkok 10900 Thailand.
- (11) **Teck Guan**. Teck Guan (China) Ltd. No. 1 Tecf Guan Road, Rugao Port Economic Development Zone Rugao, Jinagsu Province,China, 226532.

(12) **Oxiteno.** Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 1343 - Bela Vista – CEP 01317-910, São Paulo – SP, Brazil.

(13) **BASF/Cognis.** Henkelstrasse 6740551 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Germany.

3.2 MAJOR IMPORTERS / INDUSTRIAL USERS IN INDIA

(1) **(Galaxy Surfactants Limited.** C-49/2, TTC Industrial Area, Pawne, Navi Mumbai, Maharashtra, 400703.

(2) **Viswaat Chemicals Limited.** “Viswaat”, 7 Satsang Complex, Upper Govind Nagar, L.S. Raheja Marg, Malad (East), Mumbai – 400 097.

(3) **Rhodia Speciality Chemicals India Ltd.** Phoenix House “A/B” Wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai, 400013.

(4) **Indian Glycols Limited.** 2B, Sector-126, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, 201304.

(5) **Sterling Auxiliaries Pvt. Ltd.** 30/31, Marol Co-op. Ind. Est., M.V. Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059.

(6) **Matangi Industries.** Plot No. 28, Phase -1, Behind Nilsin Industries, GIDC, Vatva, Ahmedabad - 382 445, Gujarat.

(7) **Venus Ethoxylates Pvt. Ltd.** Plot Nos. 109-111, Bicholim Industrial Estate, Bicholim, Goa – 403529.

(8) **Gujarat Chemicals.** 111, Jalnidhi Complex, Opp. Bahumali Bldg., Nanpura, Surat -1.

(9) **Aarti Industries Limited.** 71, UdyogKshetra, 2nd Floor, Mulund Goregaon Link road, Mulund (W), Mumbai 400080.

(10) **Kusa Chemicals Pvt Ltd.** 101, Varun Apartment, Dattatraya Road, Santacruz (West) Mumbai- 400054

(11) **Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.** 1 Lopes Manor, Mumbai 400103.

3.3 Domestic Producers

(1) **VVF (INDIA) Limited, (Domestic Industry), 109, Sion (East),** Mumbai-400022.

(2) **Godrej Industries Ltd.** Piroshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli, Mumbai- 400079.

3.4 NAME OF EMBASSY AND ADDRESS

(1) **Philippines Embassy,** H.E. (Mr.) Benito B. Valeriano Ambassador, 50-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri New Delhi: 110021.

(2) **Belgium Embassy,** TCG Financial Centre, 7th floor, C-53, G-Block, BandraKurla Complex, Bandra (E) - Mumbai 400051. / 50-N, Shanti Path, Chanakypuri, New Delhi-110021.

(3) **USA Embassy,** U.S. Embassy, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi – 110021.

(4) **UK Embassy,** Niti Marg, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi- 110021.

(5) **UAE Embassy,** 12, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021 (INDIA)

(6) **Switzerland Embassy,** Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110021

(7) **Poland Embassy,** 50-M, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021.

(8) **Singapore Embassy,** E-6, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021.

(9) **Netherlands Embassy,** "Forbes Building" 1st floor, Charanjit Rai Marg, Mumbai 400001. / 6/50 F, Shanti Path, Kwame Nkrumah Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021.

(10) **Italy Embassy,** 50 E, Chandragupta Marg, New Delhi – 110021 (India)

(11) **Finland Embassy,** E-3, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021.

(12) **France Embassy,** 2/50-E, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi 110 021

(13) **Embassy of the Federal Republic of Germany,** P.O. Box 613, New Delhi 110001

(14) **China Embassy,** 50-D, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi-110021, India

(15) **Indonesia Embassy,** 9, Altamount Road, Cumballa Hill, Mumbai – 400 026, / 50-A, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021.

(16) **Thailand Embassy,** D-1/3 VasantVihar, New Delhi 110057.

(17) **Malaysia Embassy,** 50-M, Satya Marg Chanakyapuri, New Delhi 110 021.

4. Questionnaires were sent to the known exporters of other countries, known importers/users in India and other interested parties as per the information available with request to make their views known in writing within 30 days of the initiation notice.

5. Request to consider as interested parties was received and accepted as under:

5.1 New interested Parties after issue of notice of initiation within prescribed period

1. Mr. Mohd Radhi Abdul Razak (Director), Trade Practices Section, Ministry of International Trade and Industry, Level-14, Block-8, Government offices complex, Jalan Duta, 50622 Kuala Lumpur, Malaysia. E-mail- alltps@miti.gov.my
2. M/s. Majorhub Oleochemicals P Ltd., 10th, Siddhivinayak Appt, 4th floor, Society Road, Jogeshwari East, Mumbai-400060. E-mail- majorhubindia@vsnl.net
3. M/s. Hindustan Unilever Limited (HUL), Unilever House, BD Sawant Marg, Chakala, Andheri East, Mumbai-400099
4. Ms. Chan Pek Wan, Secretariat, Chemical Industries Council of Malaysia, Malaysian Oleochemical Manufacturers group (MOMG) Wisma FMM, No. 13, Persiasan Dagang, PJU 9, Bandar Shri Damamsara-52200 Kuala Lumpur, Malaysia. E-mail- pek_wan@FMM.ORG.MY

5. M/s. Pan Oleo Enterprise Pvt. Ltd, 309,10,11, Aditya Banarasi Heritage, Mind Space Off Link Road, Malad West, Mumbai-400064. E-mail- panoleo@panoleo.com
6. Mr. Manoj Jha, M/s Unidus, E-mail- manoj@unidusonline.com
7. The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India, Block-50E, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021. E-mail- rusintrade@mail.ru
8. M/s. PT Ecogreen Oleochemicals, Indonesia, Po Box-1010 Nagoya Plaza, Batam Island 29432, Indonesia. E-mail- info.batam@ecogreenoleo.com
9. Trade & Economic Section, Delegation of the European Union of India, 65, Golf Links, New Delhi-110003. E-mail- chaitanya.kaushal@eeas.europa.eu
10. M/s. Cavinkare Private Limited, 12, Cenotaph Road, Teynampet, Chennai-600018.
11. Directorate General of Foreign Trade, Jalan, M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta-10110.
12. M/s. Ratnasagar Herbs Pvt. Ltd.
13. M/s. Emami Limited, 687, Anandapur e.m. bypass Kolkata-700107. E-mail sapan.barik@emamigroup.com
14. M/s. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd. 555/1, Energy Complex, Building A, 15th floor, Vibhavadi- Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

5.2. Request for an extension of time to submit their reply was made by M/s. PT Musim Mas, Indonesia.

5.3 After taking into account the time limits for completing the investigation within the prescribed period, request for extension of time to submit reply as per Rule 6(4) of Safeguard Rules' 1997' were allowed.

5.4 The information presented by the applicant was verified by on-site visit to the plant of the domestic producer. The non-confidential version of verification report is kept in the public file.

5.5 All the views expressed by the interested parties have been taken into account in making appropriate determination. The non-confidential information received or acquired has been kept in the public file.

(B) Views of Domestic Producer (Applicant)

6. **Domestic Industry:** M/s. VVF (India) Limited, Mumbai, 100% Export Oriented Unit, claimed that his production account for 63% of the total production of 'PUC' in the country & represent a major proportion of the Indian production of 'PUC' in the country and thus have the standing to file the present petition. Apart from the applicant, the subject goods are being produced by M/s. Godrej Industries Ltd., Mumbai in this case, who is supporting this safeguard application.

7. **Product Involved:** Fatty Alcohols are an aliphatic alcohols and occur in saturated and unsaturated forms. The alcohols can be grouped and most common lengths are C12, C14 and blends thereof. The 'PUC' are produced by the reduction of methyl ester or wax ester, through the conversion of natural fats and oils, mostly coconut and palm kernel oil. The process starts with splitting of vegetable oils, such as Crude Palm Kernel Oil, at high temperature and pressure, as a continuous process. The vegetable oils/fats (non-edible) are basically triglycerides of fatty acids which get converted to fatty acids and glycerol by the hydrolysis reaction commonly known as fat splitting. The crude fatty acids are then subjected to plain/ fractional distillation, at a high temperature and vacuum, followed by esterification resulting from a reaction between fatty acid and fatty alcohol in an inert atmosphere to make wax- ester. Pure wax- ester is then subjected for hydrogenation which takes place in the presence of fixed bed copper catalyst, resulting in crude fatty alcohol. This is then distilled and purified. 'PUC' are sold in the form of flakes, pastilles and liquids.

8. The import and injury related data for 4 year period has been filed by the applicant. The petitioner has provided the quarter wise information for the year 2010-11 to 2013-14 (till Dec.'13) based on which the Notice of Initiation was issued. However, the DI has filed their additional information vide letter dated 21-04-2014 and dated 15-05-2014 containing information about imports and other economic parameters for the period Jan' 14 till Apr'14, emphasizing their critical situation and with a prayer to impose immediate provisional safeguard duty on the PUC, failing which they would suffer in wake of rising imports so much so that, it would be difficult to repair.

9. Petitioner requested imposition of provisional safeguard duty in their safeguard application. The interim measures are imperative in view of the steep deterioration in performance of the domestic industry and the threat of market disruption as a result of increased imports of the product under consideration. The domestic industry has been forced to undertake production cuts. Domestic sales of the domestic industry have declined significantly. The capacity utilization of the domestic industry has steeply declined in the most recent period in view of decline in sales caused by surge in imports. Inventories with the domestic industry are rising significantly. Further, the domestic industry is facing financial losses from "PUC" operations.

10. In the light of the critical circumstances, the applicant submitted that any delay in the application of safeguard measures would cause grave damage to the domestic industry. It is requested to the Authority to take immediate necessary actions in the form of provisional safeguard duty to prevent the domestic industry from suffering irreparable damage. In order to support their contention of existence of critical circumstances for provisional levy of safeguard duty, the domestic Industry has submitted data till Apr'14, i.e., annually (for the period 2010-11 till 2013-14) as well as quarterly for Q4 2013-14 and Q1 2014-15 (annualized on April'14 data) to justify accentuation of their already worse situation, in wake of rising imports. Details are as under:

A. Legal Provisions

A1. Article 6 of the Agreement on Safeguards under, GATT 1994, provides that in critical circumstances where delay would cause damage, which it would be difficult to repair, a member may take a provisional safeguard measures pursuant to a preliminary determination that there is a clear evidence that increase in imports have caused or are threatening to cause serious injury. The basic requirements for provisional levy under Article 6 are as under:

Evidence of increased imports, Such imports have caused or are threatening to cause serious injury and Existence of critical circumstances, where delay would cause damage which it would be difficult to repair.

B. Increased Imports

B1. The imports of fatty alcohols are at a high level, and continue to increase. The details of the imports are as under:

Particulars	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Imports (MT)	19843	34142	51055	57616
Trend	100	172	257	290

B2. **Imports relative to domestic production:** The imports relative to domestic production have also increased significantly. The imports relative to domestic production (i.e. production less exports) of the petitioner have increased sharply, from 60% in 2010-11 to 247% in 2013-14. Over the entire period, there has been a consistent increase in Imports relative to Domestic Production.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Imports relative to domestic production	60%	118%	226%	247%
Trend	100	195	375	412

B2.1 Imports relative to Production (Including export)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Imports relative to domestic production	29%	69%	75%	62%
Trend	100	237	260	213

B2.2 The imports relative to total Indian production have also increased:

Financial Year	Total Imports	All India Production	All India Production less exports	% imports w.r.t .total Indian production	% imports w.r.t total Indian domestic production
2010-11	19843	118582	43338	17	46
2011-12	34142	96344	57145	35	60
2012-13	51055	112613	31046	45	164
2013-14	57616	142350	35951	40	160

C. SERIOUS INJURY CAUSED TO DOMESTIC INDUSTRY

C1. Share of imports in Domestic Market

The share of imports in the consumption or demand has increased from 44% in 2010-11 to 72% in 2013-14. The market share of imports was as under:

C2. In the year 2010-11, the market was almost evenly distributed between the domestic industry and the imports, and the Indian industry commanded more than 50% of the market share. In 2011-12, there was a surge in imports, and the imports captured more than 61% of the market. As is evident from the table as under the imports are continuously on a rise since 2011-12, and are now holding more than 72% of the market share.

Financial Year	Total Imports	Sales of DI	Sales of Other Indian Producer	Total Demand	Market Share	
					DI	Imports
2010-11	19843	17080	8242	45165	38%	44%
2011-12	34142	15285	6677	56104	27%	61%
2012-13	51055	12891	7573	71519	18%	71%
2013-14	57616	14776	8088	80480	18%	72%

C3. The Market Share of the Domestic Industry, on the other hand, has drastically decreased from 38% in 2010-11 to 18% in 2013-14.

C4. Change in the levels of Sales

The trend of Domestic sales of the petitioner is as under:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Domestic sales of DI	17080	15285	12891	14776
Trend	100	89	75	86

C5. Domestic Production

C5.1 The Domestic production, (Production less exports), of the petitioner is as under:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Domestic Production	33319	28974	22560	23303
TREND	100	87	68	70

C5.2 Production, (Production including exports)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Production (Including Export)	68605	49585	67837	93297
TREND	100	72	99	136

C5.3 In a growing market, the bulk of the incremental demand has been met by the imports. The domestic industry has not gained from the growth in domestic demand.

C6. Productivity

The injury is not attributable to this factor. The increase in employees is relatable to the expansions in the splitting plant, fatty acid fractionation plant, Glycerine plant and installation of captive power plant, the benefits of which have now started accruing. This is seen in the improved productivity levels, which have increased from 186 to 205.

C7. Capacity Utilization

The capacity utilization has also declined considerably.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Capacity Utilization %	28	24	19	19
Trend	100	87	68	68

C8. Profit & Loss

The profitability of domestic industry has got fully eroded in 2011-12 and 2012-13. The profitability is reflected in the table below:

Years	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
Profit/loss	745	-1982	-20829	-14151
Trend	100	-266	-2796	-1900

*YTD Feb. 14

Since 2011-12, the domestic industry's position has been worsening rapidly, and it has not been able to recover its costs, in spite of an increase in market size. The production of the like article has become totally unviable, as the domestic industry continues to incur heavy losses.

C9. Employment

The employment in the unit has increased from 100 in 2010-11 to 124 (Indexed) during the last financial year. This increase is largely on account of the expansions in the splitting plant, fatty acid fractionation plant, Glycerine plant and installation of captive power plant., the benefits of which have now started accruing. This is seen in the improved productivity levels

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Employment Indexed	100	109	119	124
Productivity (MT/ Emp)	100	66	83	110

D. Threat of injury is imminent

D1. All the relevant parameters show a decline in the financial position of the domestic industry. In view of the above, unless duties are imposed forthwith, irreparable damage would be caused. Serious injury has been caused, as is evident from the above analysis. Threat of serious injury is imminent, as there is a significant overall impairment in the condition of the petitioner.

D2. The fatty alcohols continue to be imported in large volumes, since 2011-12. The domestic industry has a declining market share, and faces huge losses. The very survival of the petitioner is at stake, as threat of further serious injury is imminent.

E. Causal link between the imports and the serious injury suffered by the domestic industry

E1. There is a direct nexus between the imports and serious injury caused to domestic industry. The imports were at their highest in 2012-13, and 2013-2014. The market share, profitability, return on investment, domestic production of domestic industry declined significantly during this period. The condition of the petitioner has worsened considerably during the period, when the imports were at high levels.

E2. The duties on imports of fatty alcohols from certain sources have been removed with effect from 01.01.2014. Anticipating this reduction, imports declined in the third Quarter. The petitioner was able to retain its customers during this period. In Q4, 2013-2014, after removal of duties of customs, the imports have increased drastically and the condition of domestic industry has further worsened. A comparison of Q3 Vs Q4 of 2013 reveals the following:

2013-14	Q1	Q2	Q3	Q4
Imports (MT)	12408	13872	13162	18176
Trend	100	112	106	146
Imports Relative to Total Domestic Production (%) (Indexed)	100	125	121	192
Landed Value (Rs/MT)	81924	94944	102154	102800
Trend	100	116	124	125
D1 Selling Price (Incl. Duties) (Rs/MT) (Indexed)	100	109	119	131
Price Undercutting	100	-120	-63	306
Cost of Production (Rs/MT) (without duties)	100	99	112	132
Net Profit/Loss (Rs/MT)	-100	-35	-69	-128

E3. From the above, it may be seen that the performance of domestic industry has significantly worsened in the last quarter as compared to the earlier period. The effect of any marginal improvements in Q3 has been totally wiped out in Q4.

E4. This clearly indicates that serious injury has been caused and threat of further injury is imminent. The causal link between the imports and injury is also established.

F. Absence of other factors causing injury

F1. There are no other factors causing injury to the domestic industry. The demand for fatty alcohols has been increasing consistently over the last three years. There is about an 80% increase in demand, yet the domestic industry has not been able to increase its production, sales or profits commensurate to this growth in the market.

F2. The petitioner is a 100% EOU, due to which it enjoys a competitive advantage over DTA Units. The customs duty on the raw materials (PKO), such as Palm kernel oil, (which is in the range of 7.5% to 100% ad valorem) is far in excess of the duty applicable to finished goods. Since an EOU can import the raw material (PKO) without payment of duties, and clear its finished products on, payment of duty @7.725% (which has now become 3.86% w.e.f 18th Feb 2014), the net duty applicable to EOU's is much less than that borne by DTA units manufacturing fatty alcohols from imported materials. The DTA units would have to bear customs duty on raw materials which would substantially increase their costs. The net duty incidence of a domestic unit is, therefore, much higher than in the case of an EOU unit.

F3. It is submitted that the DTA and EOU units in India are similarly placed. The PKO constitutes about 2/3 of the total cost of production. As PKO is not available in India, in commercial quantities, the raw material is required to be imported and is available to both types of units at same or similar import prices. The conversion costs would also not be different. The duty structure is however, advantageous for EOU units, since the duty on raw material is generally 100%. For instance, a DTA unit importing the raw material valued at Rs. 70, would have to pay duty of Rs. 70, whereas the EOU would be able to obtain the raw material without duties under exemption. The like article, cleared from an EOU would be chargeable to duty at 7.725%, which would be in the range of Rs. 8 to Rs. 10. Thus the net duty incidence on the EOU is significantly lower than for DTA units. The duties applicable for DTA clearances by EOU have been further reduced to 3.86%

F4. There are also no changes in the pattern of consumption, to suggest that injury is being caused by such factors. In any case, it is not necessary that the imports should be the sole cause for injury, provided it can be shown that, it is one of the factors causing injury.

F5. In the present case, there are no other circumstances or factors which are causing injury to the domestic industry at the same time and the requirements of causation are fully met.

G. Critical circumstances

G1. It is submitted, that this is a fit case for a preliminary determination, that the increase in imports has caused serious injury and is threatening to cause serious injury in the future.

G2. The imports have increased almost three times, during the period 2010-11 to 2013-14. Even relative to domestic production, the imports have increased more than 4 times. The market share of the imports has increased from 44% in 2010-11 to 72% in 2013-14. The removal of duties on imports from sources covered under the Free Trade Agreement, is resulting in a further surge in the imports. The domestic industry is operating at unviable levels, incurring losses for every additional unit of production.

G3. It is submitted that the surge in imports is taking place at prices below even the cost of production of domestic industry. In the fourth quarter of 2013-14 the landed value of the imported goods was Rs. 102,800/- as against the domestic selling price of VVF of Rs. 110520 /-. The domestic industry is fast losing its market share, and its ability to produce and sell the goods in the Indian market.

G4. Anti dumping duties have also been imposed by the EU on the imports of these items. Consequently, these manufacturers in South East Asia have been shifting their inventories to other markets, including India. The major players in South East Asia have very small domestic demand compared to their respective production capacity. Out of this, the major portion is intended for countries in Asia, especially India.

G5. The fact that the duties on imports from the countries under the FTA has been removed with effect from 01.01.2014 is also resulting in the diversion of goods from other markets to India, and an immediate levy of provisional duty is necessary to offset the effect of the surge in imports. In similar circumstances, European Council has imposed provisional measures, against imports of certain steel products.

G6. The position of domestic industry was already weak prior to the removal of customs duties on imports from certain sources. The continued surge requires an immediate intervention failing which the petitioner would suffer irreparable damage.

H. 100% EOU is " domestic industry"

H1. The Designated Authority in the Ministry of Commerce has been considering EOU's as forming part of domestic industry in a number of investigations. There are no restrictions on the sale of domestically manufactured goods in India, as long as a positive NFE is maintained by the EOU unit. The Foreign Trade Policy provides for concessional rate of duty on domestic clearances (upto 50% of the FOB value of exports) of that product. Additionally, entitlement earned on other products can be used for fatty alcohols upto 90% of total FOB value of exports. Beyond the aforesaid limits, sales can be made by the EOU on payment of appropriate duties of excise. There is hence, no restriction on the sale of goods manufactured by an EOU in India as long as there is positive NFE. In this context, paragraph 34 of the findings of the Designated Authority in the case of Vitamin A, is reproduced below wherein Piramal Healthcare (100% EOU) was considered to be a domestic industry:

"With regard to domestic industry being 100% EOU and therefore it is ineligible to be domestic industry, it is noted that EOU facility in itself does not adversely affect the status of the Petitioner as "domestic industry". In fact, it is noted that the clearances made by the Petitioner to the Domestic Tariff Area are not restricted or contingent on the exports of the Product under Consideration and are treated as excise-paid domestic

sales and not a imports. Thus, based on the Information available on records of the Designated Authority, the Petitioner accounts for all the production of the subject goods in India and thus constitutes domestic industry within the meaning of the Rules".

An export oriented unit, is not a unit located outside India and hence forms part of domestic industry.

H2. The petitioner further submit that VVF is a producer of the like article or directly competitive article. The fatty alcohols produced by VVF are in direct competition with the imported products and hence it satisfies the definition of domestic industry.

I. Duty reduction as per Foreign Trade Agreement with the ASEAN Countries(AIFTA)

I 1. India has entered into an Agreement for facilitation of trade ASEAN- India Free Trade Agreement (AIFTA), pursuant to which tariff barriers are to be reduced/removed in a time bound manner. Consequent to the treaty obligations, the duties on the PUC were initially reduced to 10% by Notification No. 46/2011 –Cus dated June 01, 2011 and thereafter eliminated by Notification No. 57/2013 dated December 31, 2013.

I 2. It has been contended by some of the interested parties that the injury to the domestic industry arises on account of AIFTA and such injury should not be attributed to the imports.

I 3. The domestic industry has claimed that non attribution of injury caused by the AIFTA, is not warranted in terms of Para 2 of Annexure -2 to the Rules, for the reason that the AIFTA is not a factor “other than the imports”.

I 4. Para 2 of Annexure 2 to the Rules provides for non attribution of injury caused to the domestic industry by factors other than increased imports. Para 2 reads as under:

“The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigations demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports”.

I 5. The aforesaid provision requires that factors causing injury to the domestic industry, other than the increased imports should be identified and their injury should not be attributed to the imports. The factors under consideration are of two types:

- A. Factors that contribute to the increase in imports and
- B. Factors that cause injury to the DI, (other than increased imports).

I 6. The reduction in duties consequent to the AIFTA is merely one of the many factors which has resulted in the surge in imports. Other such factors include enhancement of production capacity by foreign producers, non availability of alternate export markets for the PUC, small demand in the country of export of PUC, reduction in duties in India, etc. These are factors which contribute to the increase in imports, for which non attribution is not required to be done.

I 7. The second type of factors include lack of technological upgradation by the domestic industry, changes in pattern of consumption in India, supply side constraints etc. Non attribution analysis is required to be done only for the second category of factors listed above, that is factors other than the imports, causing injury to the domestic industry. Non attribution is, therefore, not required for the reduction in duties.

I 8. It has further been claimed by the interested parties that since AIFTA provides alternate mechanism to address trade imbalances, therefore, the DG safeguards does not have the jurisdiction to initiate safeguard proceedings. This submission is factually incorrect and not acceptable. Under the AIFTA, the rights and obligations of the parties, who are WTO members, have been retained. Article 10 (1) of the AIFTA, provides that notwithstanding the treaty, the WTO Members (including India) shall retain their rights and obligations under the Agreement on Safeguards. An extract from the Agreement is given below:

“ARTICLE 10

Safeguard Measures

Each Party, which is a WTO Member, retains its rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards in Annex. 1A to the WTO Agreement (Agreement on Safeguards) and Article 5 of the Agreement on Agriculture in Annex 1A to the WTO Agreement (Agreement on Agriculture). Any action taken pursuant to Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards or Article 5 of the Agreement on Agriculture shall not be subject to the Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement (ASEAN-India DSM Agreement).”

J1. The fact that the duties on imports from the countries under the FTA has been removed with effect from 01.01.2014 is also resulting in the diversion of goods from other markets to India, and an immediate levy of provisional duty is necessary to offset the effect of the surge in imports. In similar circumstances, European Council has imposed provisional measures, against imports of certain steel products. In this context, paragraphs 51 to 57 of the determination are reproduced below:

“(51) The Commission has made a preliminary assessment of the possible destination of the huge volume of goods diverted from the US market. It notes that, given the weakness of other markets (notably Japan, South East Asia and South America), it is very unlikely that a significant quantity has been, or will be, diverted to such markets. Furthermore, producers in third countries suffer a difficult situation in their domestic markets, which are unable to absorb goods previously destined for the US market. Given the openness of the Community market, it may constitute the only opportunity for foreign producers to find an outlet for goods excluded from the US market. In these circumstances, the Commission concludes that a substantial proportion of the exports excluded from the US market have been, and will be, diverted to the Community.

(52) Therefore, it can be anticipated that the application of import restrictions to the US market will result in a significant further increase in imports of the products concerned into the Community. Analysis indicates that around 15 million tonnes of steel products (worth around \$4,1 billion), equivalent to total Community imports of the products concerned in 2000, are covered by the US measures and risk being diverted to the Community market.

(53) The situation of the Community producers has been significantly worsened by the US measures announced on 5 March 2002 because these measures have forced the Community producers to revise their projections downwards to reflect further reductions in earnings (from both domestic sales and exports), and further damage to profitability. This is compromising current reorganisation within the Community industry. It is also undermining earlier restructuring and modernization within the industry.

(54) Because the Community producers' projections have been revised downwards, in order to cut costs, temporary or permanent closure of production facilities will be difficult to avoid. These closures may affect production not only of the like products, but also of other products produced using the same facilities. The social impact, according to industry estimates, could be the disappearance of a further 20000 jobs in the next few years. The negative impact could also extend to those activities which are dependent on the Community producers affected by the measure.

(55) Bearing in mind that domestic consumption of the 15 products concerned is stagnant or declining and the rate at which imports were growing prior to the announcement of US measures, the situation of the Community producers was weak.

(56) The considerable increase in the growth of imports which the US measures promise has forced the Community producers to revise sales and profits projections downwards. These revised projections demand immediate measures by Community producers to reduce costs and stem anticipated losses, including closing production facilities and laying off employees. The damage caused to the Community producers by taking such action would be difficult to repair. If such action is to be avoided, provisional safeguard measures must quickly be taken.

(57) Therefore, the Commission considers that there exists a critical situation in which any delay in the adoption of provisional safeguard measures would cause damage which would be difficult to repair. It therefore concludes that provisional safeguard measures should be adopted without delay”.

J2. The position of domestic industry was already weak prior to the removal of customs duties on imports from certain sources. The continued surge requires an immediate intervention failing which the petitioner would suffer irreparable damage.

11. Post-Initiation submission by the interested parties:

A. Russian Federation

As imports of goods falling under sub-heading 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 and 29051700 from Russian Federation into India do not exceed 3 percent as per Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 and Article 9 of WTO Safeguards Agreement Russian Federation should be excluded from the list of countries under investigation.

B. Pilipinas Kao, Inc.

As per Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 and Article 9 of WTO Safeguards Agreement, Philippines be excluded from any Safeguard duty as its import share is less than 3 % during the POI while top three exporters (Indonesia, Malaysia and Thailand) has more than 98% share in imports.

C. India Glycols limited

1. In India only M/s. VVF and Godrej manufactures Lauryl Alcohol with former having 63% share and is a 100% EOU unit. Imposed with export obligation they are left with limited domestic sales compared to demand and uncompetitive prices coupled with long delivery period. They are trying to leverage their monopolistic situation.

2. As per the FTAs signed with the ASEAN countries import duty reduction is emphasized.

3. Production and demand increased in 2013-14 along with improvement in profitability. No Safeguard duty should be imposed until investigation completed and injury ascertained.

D. Emery Oleochemicals Malaysia

1. One applicant has manufacturing unit in Indonesia with export duty advantage and uses intermediate feedstock for PUC production in India. Malaysian producers don't enjoy such benefit.

E. Aarthi Industries Limited.

1. Indonesia & Malaysia have inherent cost advantage and are competitive locations for PUC while the Applicants have EOUs primarily for export market as their manufacturing cost make them in competitive in domestic market.

2. Downstream industry would be killed if duty imposed as SLS and SLES are imported at zero duty under the ASEAN FTA. Any duty will harm the larger interests of Indian industry as downstream products will become non-competitive and value addition shift to other countries.

F. Viswaat Chemicals Limited.

1. Local procurement are non dependable and high priced as compared to the imports while applicants priority is exports.

G. Cavin Care Private Limited

1. We manufacture shampoos using SLES & SLS which in turn need Fatty Alcohols predominantly imported from Indonesia & Malaysia which enjoy natural and comparative advantage. Both SLES/SLS and PUC enjoy NIL duty under India-ASEAN FTA.

2. Owing to peculiar market conditions of Palm Kernel Oil and its downstream products Safeguard duty on PUC will make SLES costlier and affect the supply chains of low cost shampoo sachets leading to denial of hygiene hair wash to masses and harm Indian Cosmetic Industry.

H. Majorhub Oleochemicals P. Ltd.

1. Applicants are hiding that they also sell C8, C10, C12, C14, C16, C18 fatty acids and C18.1 (Oleic Acid) and misrepresenting it is not commercially viable to produce and sell C8 and C10 alcohols.
2. Applicants statement of financial injury is misrepresented as there is considerable decline in the applicants share sales of Fatty Acids-C16, C18, C1618 (their core business as against Fatty alcohols) and themselves dumping the goods in Europe and when ADD was imposed, they turned to the Indian customers.
3. They omitted the fact that Godrej Industries is importer of C1214 alcohol.
4. Applicant's reason for decreased imports in 2013-14 as plant shut down in Malaysia and Indonesia is a misinformation as shut down in oleo industry is regular for change of catalyst.
5. Most of the Malaysian and Indonesian producers have their own oil plantation for raw material CPKO and CPO which both VVF & Godrej don't have.
6. Recruitment jumped by 20% from F.Y 10-11 to 13-14 and thus their claim of loss of employment is baseless.
7. Applicants share increased in C16, C1618 and C18 Alcohols in both domestic and export markets.

I. M/s P.T.Musim Mas

1. Applicant has claimed excessive and unwarranted confidentiality which prevented the party to reasonably understand Applicant's claims and the material relied.
2. Domestic producers do not produce SFA with carbon lengths C8 and C10 and blends thereof them and the import of such goods cannot cause injury to the applicants .PUC should be correctly defined to exclude the types of SFA.
3. The Applicant's claims of a sudden surge in imports is not established as imports show a declining trend over the period 2011-12, to 2013-14 (annualized) especially in 2013-14;
4. The Applicant ignored the data for 2013-14 and resorted to analyzing each quarter against the same quarter in the previous year.
5. The Applicant's claim that plant shutdowns in Malaysia and Indonesia slowed imports for the Q1 and Q2 of 2013-14 is not credible as there was no subsequent surge in Q3 of 2013-14 on resumption of production;
6. The POI was chosen deliberately to paint imports of SFA in a poor light as the import trends with base year 2010-11 (as proposed by the Applicant) paints a very different picture from the trends shown if the base year was 2011-12; and
7. The Applicant's injury claim not established as its production and capacity utilization improved significantly in 2013-14.
8. Decline in the Applicant's market share could be due to the restrictions imposed by virtue of its EOU status and the export orientation.
9. Safeguard duty will not assist Applicant due to inherent disadvantages compared to Indonesian and Malaysian SFA producers as the main raw material is produced there.

J. Thai Fatty Alcohols Co.Ltd, Thailand,Wilmar Trading Pte Ltd, Singapore,KL-Kepong Oleomas SDN BHD & Galaxy Surfactants.

1. Petitioner admitted that it has only manufactured and sold C12, C14, C16, C18 and blends thereof and not C8 and C10 carbon. Further, certain Carbon Chain lengths and combinations, which are not being imported into India at all or have been very sporadic during the POI, namely C810 and C14. Thus, it will be incorrect to include such grades in the product definition.
2. In present legal and commercial situation, VVF is not competitive in domestic market and is suffering injury. VVF is dependent on import for its raw material which is subject to export tax in Indonesia & Malaysia while when VVF sells Fatty Alcohol in the domestic market; the users have to pay excise duty equal to the customs duty which is not applicable in case of import of fatty alcohol from these countries under India-ASEAN Agreement.
3. Compared to previous year, there is no increase in imports, let alone surge in imports and while considering the product under consideration, the Authority has to examine all the product grades/Carbon Chain Lengths separately.
4. Imports of most of the grades have in fact fallen significantly during the injury period and were at their lowest during the Period of Investigation (2013-14-up to December).
5. Both Petitioner as well as the other producer – Godrej Industries Ltd is (EOU), whose primary objective is to export the subject goods out of India.

6. A biggest reason for rise in imports is due to India's initiative to boost trade with ASEAN countries and according them concessional rates of duties.
7. Petitioner can make DTA clearance only at a higher rate and not the preferential rate of customs duty in terms of India ASEAN FTA. Imposition of safeguard duty cannot correct this difference since it's a policy decision taken by Government of India and Petitioner has no control over this.

K. PT. Ecogreen

1. NOI and the Complaint do not properly explain whether such increased import occurred is recent, sudden, sharp and significant situation.
2. Complainant is operating under the Export Oriented Unit Scheme and domestic sales volume to the Indian market is limited to one-third of the total volume of production and cannot cover the demand in the domestic market of India sufficiently.
3. There are two producers of fatty alcohol existing in India namely the Complainant and Godrej who also holds significant portion of the domestic production in India and thus should lead to the fierce competition between the two.
4. Godrej is not part of the complainant and its overall performance presented in the Complaint show a positive trend.

L. Rhodia Specialty Chemicals India Limited(Solvay Group)

India is currently ethoxylation hub due to fair pricing of Ethylene oxide and availability of Lauryl alcohol and Safeguard duty on PUC will drive away all value addition from India leading to loss of employment and revenue.

M. Hindustan Unilever Ltd.

1. The volume of imports is concentrated from Indonesia, Malaysia and Thailand and does not warrant a Global Safeguard measure. The Applicant ought to look for remedy available under Article 10 of Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation.
2. There is clearly no reason as to why some of the carbons chains not being produced should be excluded from the product scope as It is clearly stated in the application that the applicant does not produce Fatty Alcohol of Length C8 and C10 along with blends thereof.
3. The aspect of unforeseen developments has been completely ignored and absent in the Application.
4. The operations of Applicant might be affected because of poor export performance and lower realisations in the export market and high finance costs and in the injury, if any is self inflicted and is not attributable to increased imports.
5. The subject goods are importable tariff-free in India from countries like Indonesia, Malaysia and Thailand under the ASEAN CECA. Therefore the cause of injury is basically inverted duty structure and cannot be attributed to increased imports of subject goods.
6. Applicant has clearly taken undue advantage of claiming excessive confidentiality on disclosing the adjustment plan.
7. Any imposition of safeguard duty would be contrary to public interest, as the interests of the consuming industry clear impact the tax revenues earned by the Government.

12. The DI responded to the Post-Initiation submissions of the aforementioned Interested Parties on all the issues, re-iterating their initial submissions as below:

12.1. It has been contended by the interested parties, that the definition of domestic industry under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 ("Act") is inconsistent with the Agreement on Safeguards. This contention is not correct, as the term domestic production implies production in India, and not production destined for *consumption in India*. The request that the standing requirement, be examined with reference to the domestic production alone is misplaced. At the stage of production, it is not known whether an article would be consumed in India, or elsewhere. The interpretation suggested by the parties is therefore untenable. In any case, the total production of Indian producers, less their exports, also reflects that the petitioner has standing for the purposes of investigation.

12.2 *"With regard to domestic industry being 100% EOU and therefore it is ineligible to be domestic industry, it is noted that EOU facility in itself does not adversely affect the status of the Petitioner as "domestic industry". In fact, it is noted that the clearances made by the Petitioner to the Domestic Tariff Area are not restricted or contingent on the exports of the Product under Consideration and are treated as excise-paid domestic sales and not as imports. Thus, based on the Information available on records of the Designated Authority, the Petitioner accounts for all the production of the subject goods in India and thus constitutes domestic industry within the meaning of the Rules".*

12.3 An export oriented unit, is not a unit located outside India and hence forms part of domestic industry.

12.4 In the case of Cosco Blossoms Pvt. Ltd. Vs Commissioner Of Customs reported at 2004 (164) ELT 423 (Tri Del), the Hon'ble Tribunal reiterated that goods cleared by an EOU domestically are treated as domestic goods. The relevant paragraph is excerpted below:

“5. It is well settled 12000 (120) E.L.T. 8001 that goods produced in an EOU cannot be treated as imported goods and subjected to customs duty. The duty payable in respect of such goods is the duty of excise under Section 3 of the Central Excise Act, 1944. Therefore, the duty demand made in the impugned order under Section 28 of the Customs Act is not sustainable. Accordingly, we set aside the impugned order and allow the present appeal. However, we make it clear that revenue authorities will be at liberty to demand duty on the imported inputs, if any, used in the production of the cut-flowers in question”

12.5 The petitioner's share of domestic production is 60% and therefore, qualifies as “domestic industry”.

12.6 The petitioner is a 100% EOU, due to which it enjoys a competitive advantage over DTA Units. The customs duty on the raw materials (PKO), such as palm kernel oil, (which is in the range of 7.5% to 100% ad valorem) is far in excess of the duty applicable to finished goods. Since an EOU can import the raw material (PKO) without payment of duties, and clear its finished products on, payment of duty @7.725% (which has now become 3.86% w.e.f 18th Feb 2014), the net duty applicable to EOU's is much less than that borne by DTA units manufacturing fatty alcohols from imported materials. The DTA units would have to bear customs duty on raw materials which would substantially increase their costs. The net duty incidence of a domestic unit is, therefore, much higher than in the case of an EOU unit.

12.7 The claim that there is no nexus in any excess between the imports and profitability is not correct. The graphical representation is misleading as it is based on indexed numbers. It is further submitted that there is a direct nexus between the imports and serious injury caused to domestic industry. The imports were at their highest in 2012-13, and 2013-2014. The market share, profitability, return on investment, domestic production of domestic industry declined significantly during this period. The condition of the petitioner has worsened considerably during the period, when the imports were at high levels.

12.8 The duties on imports of fatty alcohols from the countries under the FTA have been removed with effect from 01.01.2014. Anticipating this reduction, imports declined in the third Quarter. The petitioner was able to retain its customers during this period. In Q4, 2013-2014, after removal of duties of customs, the imports have increased drastically and the condition of domestic industry has further worsened.

12.9 It may be seen that the performance of domestic industry has significantly worsened in the last quarter as compared to the earlier period. The effect of any marginal improvements in Q3 has been totally wiped out in Q4. In spite of a sharp increase in raw material prices in Q4 of 2013-14, the import prices of subject goods have not increased commensurate with the increase in raw materials costs.

2013-14	Q1	Q2	Q3	Q4
PKO Prices(Indexed)	100	104	127	154
Landed Value of Imports	81924	94944	102155	102800
Trend	100	116	124	125

12.10 This clearly indicates that serious injury has been caused and threat of further injury is imminent. The causal link between the imports and injury is also established.

12.11 Injury must be caused to the “domestic industry” which produces the like or directly competitive products. The fatty alcohols produced by the petitioner are comparable to the imported goods, and are commercially and technically interchangeable with the imported article.

12.12 The product covers grades/types which are same as far as their technical characteristics, chemical composition and other basic features are concerned. The products of all these headings find similar uses. Therefore these products are like and directly competing products. Despite possible minor superficial differences, these products have the similar basic physical characteristics and similar end uses. These are sold via similar or identical sales channel. These products compete mainly on price. Imposition of safeguard duty on one heading at eight digit level or one type, in isolation, will not serve any purpose as importers will start importing other directly competing products. Thus, it is submitted that in view of the above, for the purposes of safeguard investigation, the product mentioned in the initiation notification has been appropriately considered as the 'product under consideration'.

12.13 A similar issue arose before the EC in the Anti-Dumping Proceedings, EU No. 1138/2011

“COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No. 1138/2011 of 8 November, 2011

12.14 *The product concerned is, as set out in recitals 10 and 11 of the provisional Regulation, saturated fatty alcohols with a carbon chain length of C8, C10, C12, C14, C16 or C18 (not including branched isomers) including single saturated fatty alcohols (also referred to as 'single cuts') and blends predominantly containing a combination of carbon chain lengths C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (commonly categorised as C8-C10), blends predominantly containing a combination of carbon chain lengths C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (commonly categorised as C12-C14) and blends predominantly containing a combination of carbon chain lengths C16-C18, originating in India, Indonesia, and Malaysia, currently falling within CN codes ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 and ex 3823 70 00.*

12.15 *After the imposition of provisional measures certain parties complained about the ambiguity of the definition of the product concerned. They claimed that according to the NOI, only linear FOH is included in the product scope, thus excluding FOH containing branched isomers, or branched FOH. Other parties claimed that it does not make sense to exclude FOH containing branched isomers produced from the oxo process because they have the same use and compete with linear FOH in the market.*

12.16 *It has been established that all types of FOH covered by this investigation, as described in recital 8, despite possible differences in terms of raw material used for the production, or variances in the production process, have the same or very similar basic physical, chemical and technical characteristics and are used for the same purposes. The possible variations in the product concerned do not alter its basic definition, its characteristics or the perception that various parties have of it."*

12.17 The product under consideration includes grades/types derived out a single raw material. However, having regard to the fact that no single blend/cut can be taken in isolation, the entire set of carbon chains C8 to C18 needs to be looked at as a single category of product. The applications are broadly common, that is in the detergent and personal care industry. In fact, both C12 C14 and C16 C18 can be converted to ethoxylates and used as surfactants in detergent applications. C12 C18, which is a blend of C12 C14 and C16 C18 can also be used for similar applications. C14 must also be considered as it is a part of the blend C12 C14.

12.18 It may be relevant to consider, that the fatty alcohols constitute less than 10% of the soaps, detergents, personal care products. The different blends have commercial and technical interchangeability. The essential character of end use product, is not acquired from the fatty alcohol, but by use of other materials.

12.19 The petitioner is using the lurgi process at its Taloja unit. By this process, a product commercially known as coconut alcohols which is a blend of C8 to C18 can be produced. By a process of fractional distillation, any of the fractions – C8 to C18 can be taken out.

12.20 The petitioner has sold C10 on payment of duties of excise.

(C) Findings of the Director General (Safeguards) :

13. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, exporters and exporting nation. Submissions made by the various parties and the issues arising there-from are dealt with at appropriate places in the findings below. The request of the DI for imposition of provisional safeguard duty on the import of product under consideration has been examined with reference to the existence of critical circumstances under the domestic law as well as international law. The provisions of Agreement on Safeguards and the decisions of the WTO bodies have been stated/discussed at appropriate places below. The findings have been given accordingly. These are provisional findings, based on the examination of the application/submissions made by the DI, post- Initiation responses of the Interested Parties and other data so far available on record. I am conscious of the fact that detailed submissions from the DI and the interested parties will come on record in the proceedings hereinafter, which would be taken into consideration at the time of giving Final Findings.

13.1 Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Section 8B(1) provides for imposition of Safeguard Duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry. Sub Section 2 of Section 8B of the CTA'75 provide that:

The Central Government may, pending the determination under sub-section (1), impose a provisional safeguard duty under this sub-section on the basis of a preliminary determination that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry:

Provided that where, on final determination, the Central Government is of the opinion that increased imports have not caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry, it shall refund the duty so collected:

Provided further that the provisional safeguard duty shall not remain in force for more than two hundred days from the date on which it was imposed.

14. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation. These Rules have been made under section 8B of the Customs Tariff Act, 1975. I have been conferred powers under these Rules to make recommendations for imposition of safeguard duty in terms of law. Rule 9 of the aforesaid Rules provide that "The Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he may record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury'. Rule 10 of the aforesaid Rules provide that the Central Government may in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 8B of the Act, impose a provisional duty on the basis of the preliminary findings of the Director General: Provided that such duty shall remain in force only for a period not exceeding two hundred days from the date on which it was imposed.

14.1 Rule 2 (b) of the aforesaid rules provide that ““Critical circumstances” means circumstances in which there is clear evidence that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry and delay in imposition of provisional safeguard duty would cause irreparable damage to the domestic industry;

14.2 I find that one of the Interested party has raised the issue of jurisdiction of this office in processing the safeguard application in view of the ASEAN bilateral Free Trade Agreements and have held that since majority of the import is originating from ASEAN nations, the Deptt. of Commerce, who is the negotiator of these FTAs, to be the appropriate authority for providing them relief.

14.3 In this regard, I have gone through the provisions of the said bilateral FTA. An extract from the treaty is given below:

ARTICLE 10

Safeguard Measures

1. Each Party, which is a WTO Member, retains its rights and obligations under Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards in Annex 1A to the WTO Agreement (Agreement on Safeguards) and Article 5 of the Agreement on Agriculture in Annex 1A to the WTO Agreement (Agreement on Agriculture). Any action taken pursuant to Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards or Article 5 of the Agreement on Agriculture shall not be subject to the Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement (ASEAN-India DSM Agreement).

14.4 In view of the above provision, as against the contention of the Interested Parties that safeguard directorate is not an appropriate forum for relief in the instant case, it is found that merely the fact, that various Agreements provide for alternate mechanisms, to address trade imbalances, does not exclude the jurisdiction of DG Safeguards, acting under the aegis of the Customs Tariff Act, 1975. In fact, the ASEAN Free Trade Agreement, itself provides that notwithstanding the treaty, the WTO Members (including India) shall retain their rights and obligations under the Agreement on Safeguards.

14.5 Further, the general Safeguard measures is imposed on a non-discriminatory manner, against all imports of the product under consideration, irrespective of country of export, save and except the de-minimis provision, provided under the proviso to Section 8B(1) of CTA, 1975. Moreover, the applicant in the instant case resorted to relief under General Safeguard measures, which is fully justified under the existing legal provisions. Therefore, it is abundantly clear that this office has the jurisdiction and the authority to process safeguard application of the applicant in the instant case and accordingly therefore, I proceed to record this provisional finding.

15. The product under investigation:

15.1 The product involved is “ Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8,C10,C12,C14,C16, and C18 including single, blends and unblended (Not including branched isomers) which includes blends a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18, C-16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14) ” **hereinafter referred to as ‘PUC’ (Product under consideration)**. The ‘PUC’ being imported is falling under sub-heading 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 and 29051700 of the Customs Tariff Act 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations. The ‘PUC’ are mainly used for the manufacture of surfactants, personal care products, home care products, pharmaceutical and agriculture related end application, processing of articles of leather, textile, fur, pulp, paper, petroleum products, fine chemicals, rubber products, plastic and fabricated metal products, include mining, offshore operations, construction work and as solvent and for degreasing purposes. The product is not sold in retail level and is for industrial users.

15.2 Some of the Interested Parties have contended that the product scope has not been appropriately defined since different branched chain /blended fatty alcohols are different item. I find that the injury must be caused to the “domestic industry” which produces the like or directly competitive products. The fatty alcohols produced by the petitioner are comparable to the imported goods, and are commercially and technically interchangeable with the imported article. Further the product covers grades/types which are same as far as their technical characteristics, chemical composition and other basic features are concerned. The products of all these headings find similar uses. Therefore, these products are like and directly competing products. Despite possible minor superficial differences, these products have the similar basic physical characteristics and similar end uses. These are sold via similar or identical sales channel.

15.3 It has been submitted by the DI that the product under consideration includes grades/types derived out a single raw material and the entire set of carbon chains C8 to C18 needs to be looked at as a single category of product. The applications are broadly common, that is in the detergent and personal care industry. In fact, as stated by the DI, both C12 C14 and C16 C18 can be converted to ethoxylates and used as surfactants in detergent applications. C12 C18, which is a blend of C12 C14 and C16 C18 can also be used for similar applications. C14 must also be considered as it is a part of the blend C12 C14.

Moreover, it may be relevant to consider, that the fatty alcohols constitute less than 10% of the soaps, detergents, personal care products. The different blends have commercial and technical interchangeability. The essential character of end-use product, is not acquired from the fatty alcohol, but by use of other materials, which are predominant and/or are present in the end-product in far greater proportions. These products compete mainly on price. It is on record that the petitioner is using the lurgi process at its Taloja unit. By this process, a product commercially known as coconut alcohols which is a blend of C8 to C18 can be produced. By a process of fractional distillation, any of the fractions – C8 to C18 can be taken out.

15.4 As against the contention of the interested party that the DI has not manufactured C8 and C10 fatty alcohol, I find that the DI has provided evidence that they have produced and sold C10 on payment of duties of excise. So far as C8 is concerned, the DI has stated that they have the capability to manufacture C8, but as the said type is not in demand. Moreover, I find that the Interested party has merely stated that the DI has not produced C8 fatty alcohol, but they have not disputed or questioned the capability of the DI to manufacture C8 fatty alcohol.

15.5 Thus, in view of the above, I find that for the purposes of safeguard investigation, the product Fatty Alcohols of single or blend of different carbon chains mentioned in the initiation notification has been appropriately considered as the 'product under consideration'. Therefore, since these items are interchangeable and originate out of identical raw material by an identical manufacturing process, the PUC in this case has been correctly defined.

16. Domestic Industry:

Clause (6) (b) of Section 8B of the Customs Tariff Act .1975 states that “domestic Industry” means the producers-

- (i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
- (ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.

16.1 The application has been filed by M/S VVF (India) Limited, Mumbai, 100% Export Oriented Unit, the applicant account 63% of the Indian production and hence are major producer.

16.2 After taking into account the information on record, it is determined that production of the domestic producer filing the petition and who have provided relevant information constitutes a major share of the total production of the said article in India. Accordingly, they are Domestic Producer as per Section 8B of the Customs Tariff Act 1975. The instant application is also supported by M/s. Godrej Industries Ltd., who is the only other producer of the PUC in the country.

17. Period of Investigation (POI):

The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguard and the relevant Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. I am of the view that law in India provides discretion to the Competent Authority to decide upon the length of period which may be able to give fair amount of comparison in respect of increased imports and other factors leading to serious injury. Of course, such discretion has to be exercised judiciously.

17.1 The issue of period of investigation has been dealt with extensively in the panel's report on Argentina Footwear on Argentina Footwear, which is being reproduced below:

ARGENTINA– SAFEGUARD MEASURES ON IMPORTS OF FOOTWEAR; Report of the Panel (WT/DS121/R dated 25.06.1999)

8.216 “Regarding the investigation’s almost exclusive reliance on end-point-to-end-point comparisons in its analysis of the changes in the situation of the industry, we have the same concerns as were noted above with regard to the “increased imports” analysis. Here we note in particular that if intervening trends are not systematically considered and factored into the analysis, the competent authorities are not fulfilling Article 4.2(a)'s requirement to analyse "all relevant factors", and in addition, the situation of the domestic industry is not ascertained in full. For example, the situation of an industry whose production drops drastically in one year, but then recovers steadily thereafter, although to a level still somewhat below the starting level, arguably would be quite different from the situation of an industry whose production drops continuously over an extended period. An end-point-to-end-point analysis might be quite similar in the two cases, whereas consideration of the year-to-year changes and trends might lead to entirely opposite conclusions.”

8.217 “We believe that consideration of changes over the course of the investigation period in the various injury factors is indispensable for determining whether an industry is seriously injured or imminently threatened with serious injury. An end-point-to-end-point comparison, without consideration of intervening trends, is very unlikely to provide a full evaluation of all relevant factors as required.”

17.2 From the above, it is clear that the provisions of Agreement on Safeguard do not provide for specific guidelines on the period of investigation. The Appellate Body Report has given its finding in unequivocal terms that the relevant investigation period should not only end in the very recent past; the investigation period should be the recent past.

17.3 Broadly, the applicant filed the instant application for initiation of safeguard investigation for imposition of safeguard duty to protect the DI from serious injury which has been caused due to surge in imports. Accordingly, it has submitted all

the data from 2010-11 to 2013-14 (till Dec'13) in their safeguard application regarding imports and domestic data showing serious injury and also with a request for interim relief in form of provisional safeguard duty. After examining the data provided by the DI, the Notice of Initiation was issued on 13-02-2014. Thereafter, the DI again approached this office around April'14 reiterating their request for immediate imposition of provisional safeguard duty owing to steep rise in imports further and that the same is causing them far serious injury and threatening to cause more serious injury, leading to a critical circumstance on the strength of import and other domestic data from Jan'14 till April'14, which shows further deterioration of the condition of the domestic, whereby any delay in granting any interim relief to them, would cause irreparable damage, which would be difficult to repair. Therefore, the period of investigation selected is 2010-11 to 2013-14 which is long enough in order to take into consideration the serious injury or threat of serious injury caused to them due to increased imports. However, in order to ascertain the need of imposition of Provisional Safeguard Duty, the existence of critical circumstances or otherwise has been examined on both monthly and quarterly basis, based on data from Jan'14 till Apr'14 and from Q3 2013-14 to Q1 2014-15 (annualized on Apr'14 data) respectively, provided by the DI, over and above the data already considered during the Notice of Initiation.

18. Source of Information:

18.1 The import data for the 'PUC' has been taken from IBIS, Mumbai, (Transaction wise) from 2010-11 to 2013-14 and April month of 2014 with annualized of 1st quarter of 2014-15 and same has been taken into consideration for analysis. The domestic data from 2010-11 to 2013-14 and 1st quarter of 2014-15 has been submitted by the domestic industry.

18.2 The injury data for the relevant POI submitted by the domestic industry in their petition has also been relied upon, which has been duly verified after on-site visit by the department to the extent deemed necessary and the verified data has been taken into consideration for injury analysis. The cost data and calculations of injury margin have been provided by the petitioner duly certified by independent Chartered Accountant.

19. Increased Imports:

Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:

"(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article :"

19.1 Further, Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines 'increased quantity' as follows:

*"increased quantity" includes increase in imports whether in **absolute terms or relative to domestic production.**"*

19.2 From the above, it is seen that law i.e. Section 8B and the Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production. It is also seen the expression "increased quantity" has been defined in inclusive terms and the definition includes two parameters i.e. increase of imports in absolute terms and increase of imports in relative terms to domestic production. It is also seen that both these parameters need not exist together. The increased quantity is to be measured either in absolute terms or in relative to domestic production. The satisfaction/existence of one parameter is sufficient to fulfill the legal requirement.

19.3 The WTO Panels and Appellate bodies have further explained the international law on this issue and some of the relevant decisions of these bodies are narrated below:

I. The Panel in *Argentina — Footwear (EC)(WT/DS/R dated 25.06.1999)* further examined whether there is consistency with Articles 2.1 and 4.2(a) in making a finding of increased imports on the basis of a comparison between the volume of imports at the starting-point of an investigation period and the volume of imports at the end of that period ("endpoint-to-end-point-comparison"). The Panel, later upheld in this respect by the Appellate Body, came to the conclusion that:

8.156 "[I]n assessing whether an end-point-to-end-point increase in imports satisfies the increased imports requirement of Article 2.1, the sensitivity of the comparison to the specific years used as the end-points is important as it might confirm or reverse the apparent initial conclusion. If changing the starting-point and/or ending-point of the investigation period by just one year means that the comparison shows a decline in imports rather than an increase, this necessarily signifies an intervening decrease in imports at least equal to the initial increase, thus calling into question the conclusion that there are increased imports."

8.157 "In other words, if an increase in imports in fact is present, this should be evident both in an end-point-to-end-point comparison and in an analysis of intervening trends over the period. That is, the two analyses should be mutually reinforcing.

Whereas here their results diverge, this at least raises doubts as to whether imports have increased in the sense of Article 2.1.”

19.4 It was further examined by the Panel in *Argentina — Footwear (EC)*, in a finding subsequently confirmed by the Appellate Body, considered, in this connection, that an analysis of intervening trends of imports was indispensable:

8.159 “[T]he question of whether any decline in imports is ‘temporary’ is relevant in assessing whether the ‘increased imports’ requirement of Article 2.1 has been met. In this context, we recall Article 4.2(a)’s requirement that ‘the rate and amount of the increase in imports’ be evaluated. In our view this constitutes a requirement that the intervening *trends* of imports over the period of investigation be analysed. We note that the term ‘rate’ connotes both speed and direction, and thus intervening trends (up or down) must be fully taken into consideration. Where these trends are mixed over a period of investigation, this may be decisive in determining whether an increase in imports in the sense of Article 2.1 has occurred. In practical terms, we consider that the best way to assess the significance of any such mixed trends in imports is by evaluating whether any downturn in imports is simply temporary, or instead reflects a longer-term change.”

19.5 The Panel in *Argentina — Footwear (EC)* further found that in the case before it the decline in the volume of imports could not be characterized as a temporary reversal of an increase in the volume of imports. It then stated that:

8.161 “[T]he Agreement requires not just an increase (i.e., any increase) in imports, but an increase in ‘such ... quantities’ as to cause or threaten to cause serious injury. ... the increase in imports must be judged in its full context, in particular with regard to its ‘rate and amount’ as required by Article 4.2(a). Thus, considering the changes in import levels over the entire period of investigation, as discussed above, seems unavoidable when making a determination of whether there has been an increase in imports ‘in such quantities’ in the sense of Article 2.1.

19.6 The Appellate Body in *Argentina-Footwear (EC)* (WT/DS/121/AB/R dated 14.12.1999) held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract there from is as follows:

“131. [T]he determination of whether the requirement of imports ‘in such increased quantities’ is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year—or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be ‘such increased quantities’ as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause ‘serious injury’.”

19.7 The Panel on US-Wheat Gluten (WT/DS/166/R dated 31.07.2000, interpreted the phrase “in such increased quantities” as follows:

8.31 “[A]rticle XIX:1 (a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards (“SA”)] do not speak only of an ‘increase’ in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the ‘increase’ in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and **Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury.** Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body’s finding in *Argentina—Footwear Safeguard* that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury.”

19.8 Keeping in view the above requirements of law with regard to ‘increased imports’, analysis has been done as below on the basis of objective and quantifiable data:

20. Increase in Import (Absolute Terms):

20.1 Imports of fatty alcohols into India have shown sharp increase in absolute terms as well as in relative terms. On comparison of data on monthly basis during the period from December 2013 to April 2014, import has increased from 4304 MT to 6402 MT which on indexed scale increased from 100 to 149, a huge surge of 49 percentage points, as seen from table below:

Table-1

Particulars	Dec '13	Jan '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14
IMPORTS					
Imports (MT)	4304	4,605	5,942	7,629	6,402
Trend	100	107	138	177	149

20.2 Similarly, if we consider quarter-wise data, imports increased from 13161 MT in Q3 to 18176 in Q4 of '13-'14 and further to 19206 in Q1 of '14-'15, which on indexed scale increased from 100 to 146 points, again a huge surge of 46 percentage points, as seen from the table below:

Table-2

	2013-14		2014-15
Particulars	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1 (Calculated on basis of April 2014 data)
IMPORTS			
Imports (MT)	13161	18176	19206
<i>Trend</i>	<i>100</i>	<i>138</i>	<i>146</i>

21. Increase in import in relation to production:

21.1 During the period December 2013 to April 2014 the percentage of import in relation to total domestic production has increased more than twice i.e. from 30 % in December 2013 to 77 % in April 2014 on comparison of month-wise data, which on indexed scale increased from 100 to 256, a very significant surge of 156 percentage points, as seen from the table below:

Particulars	Dec '13	Jan '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14
Imports (MT)	4304	4,605	5,942	7,629	6,402
Total Indian Production	14279	12080	8892	11484	8311
Imports as a % of total production	30%	38%	67%	66%	77%
Trend	100	126	222	220	256

21.2 If we consider quarter-wise data, the percentage of import in relation to total domestic production increased from 35% in Q3 to 56% in Q4 of '13-'14 and further to 77% in Q1 of '14-'15, which on indexed scale increased from 100 to 159 to 218 points during the same period, a rapid surge of 118 percentage points, as seen from the table below:

	2013-14		2014-15
Particulars	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1 (Calculated on basis of April 2014 data)
IMPORTS			
Imports (MT)	13161	18176	19206
Total Production	37345	32456	24953
Imports as a % of total production	35%	56%	77%
Trend	100	159	218

22. Determination of Increased Imports:

From the above analysis, It is clear that there is substantial increase in imports of the product under consideration in this case both in absolute terms and also in relation to production during the relevant period. As against the claim of the interested parties that the increased imports is not continuously rising, I find that the import data do not support their contention. I find that imports are rising, both monthly as well as on quarterly basis and in my view is significant, sharp and sudden which satisfies the condition of surge in imports under the law related to Safeguard duty.

23. Serious Injury and Threat of Serious Injury:

23.1 "Serious injury" means an injury causing overall impairment in the position of a domestic industry; and "threat of serious injury"² means a clear and imminent danger of serious injury.

23.2 The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall *position* of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

23.3 Accordingly, in analyzing critical circumstances for consideration of imposition of provisional duty, serious injury or threat of serious injury of all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered, as discussed hereinbelow.

24. MARKET SHARE:

24.1 During the period December 2013 to April 2014, the Market Share of import increased from 72% in December 2013 to 80 % in April 2014 whereas the market share of Domestic Industry decreased from 15% in December 2013 to 9 % in April 2014, as seen from the table below:

Particulars	Dec '13	Jan '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14
IMPORTS					
Imports (MT)	4304	4,605	5,942	7,629	6,402
Domestic sales of DI	903	1,805	315	846	739
Sale of Others (Godrej)	780	980	755	927	844
Total Demand (DI+Others+Imports)	5988	7390	7012	9402	7985
Market Share of DI Sales (%)	15	24	4	9	9
Market Share of Imports (%)	72	62	85	81	80

24.2 During the period Q3 of 2013-14 to Q1 of 2014-15 (Calculated on basis of April 2014 data), the market share of imports increased from 70% in Q3 of 2013-14 to 80% in Q1 (2014-15) whereas the market share of Domestic Industry decreases from 19% to 9% during the same period, as seen from the table below:

Particulars	2013-14		2014-15
	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1 (Calculated on basis of April 2014 data)
IMPORTS			
Imports (MT)	13161	18176	19206
Domestic sales of DI	3557	2965	2217
Sale of Others (Godrej)	2132	2662	2532
Total Demand (DI+Others+Imports)	18850	23803	23955
Market Share of DI	19%	12%	9%
Trend	100	63	47
Market Share of Imports	70%	76%	80%
Trend	100	109	114

25. PRODUCTION:

25.1 During the period December 2013 to April 2014, the Production of DI decreased sharply from 10396 MT to 3652 MT, i.e from indexed point 100 to 35. The same trend is also seen in the total domestic production (including supporter), which decreased from 14279 MT in December 2013 to 8311 MT in April 2014, as seen from the table below:

Particulars	Dec '13	Jan '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14
Production (DI) MT	10,396	7,483	4,560	7,268	3,652
Trend	100	72	44	70	35
Total Production	14279	12080	8892	11484	8311

25.2 Considering quarter-wise data, production of DI decreased from 25171 MT in Q3 of '13-'14 to 10956 MT in Q1 of '14-'15 i.e from indexed point 100 to 44. During the same period, the total domestic production (including supporter) also declined by about 33 percentage points, from 37345 MT in Q3 2013-14 to 24953 MT in Q1 2014-15(annualized), as per table below:

Particulars	2013-14		2014-15
	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1 (Calculated on basis of April 2014 data)
Production (DI) MT	25171	19311	10956
Trend	100	77	44
Total Production	37345	32456	24953
Trend	100	87	67

26. SALES:

26.1 During the period December 2013 to April 2014, domestic sales of DI decreased from 903 MT in December 2013 to 739 MT in April 2014 i.e. from indexed point 100 in December 2013 to 82 in April 2014, as reflected from the table below:

Particulars	Dec '13	Jan '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14
Domestic sales of DI	903	1,805	315	846	739
Trend	100	200	35	94	82

26.2 Considering quarter-wise data, domestic sales decreased from 3557 MT in Q3 to 2965 MT in Q4 of 2013-14 and further dropped to 2217 MT in Q1 of 2014-15 i.e. indexed point 100 to 83 and finally to 62 during the same period. The trend notice quarterly is more even, as shown in the table below:

	2013-14		2014-15
Particulars	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1 (Calculated on basis of April 2014 data)
Domestic sales of DI	3557	2965	2217
Trend	100	83	62

27. CAPACITY UTILISATION:

27.1 The Installed capacity of the DI has been same throughout the POI and also for the monthly/quarterly period under analysis at present. The capacity utilization of DI has decreased from 104% in December 2013 to 37 % in April 2014 i.e. by about 65 % as reflected on indexed scale, as per table below:

Particulars	Dec '13	Jan '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14
Installed Capacity DI	10000	10000	10000	10000	10000
Capacity Utilisation DI	104%	75%	46%	73%	37%
Trend	100	72	44	70	35

27.2 On quarterly analysis, it is seen that during the period Q3 of 2013-14 to Q1 of 2014-15 (Calculated on basis of April 2014 data) also, the capacity utilization of DI shows the same trend, i.e., it has decreased from 84% in Q3 of 2013-14 to 37% in Q1 of 2014-15, which on indexed scale is a decline of about 56 percentage points, from 100 in Q3 of 2013-14 to 44 in Q1 of 2014-15, as per table below:

	2013-14		2014-15
Particulars	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1 (Calculated on basis of April 2014 data)
Installed Capacity DI	30000	30000	30000
Capacity Utilisation DI	84%	64%	37%
Trend	100	76	44

28. Employment (Indexed):

It is seen that the level of employment has not undergone much change as it shows more or less same figures both on monthly basis (Dec'13 to Apr'14) and quarterly basis (Q3 of 2013-14 to Q1 of 2014-15 (Annualised), as per the tables below:

Monthly basis:

Particulars	Dec '13	Jan '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14
Employment	100	102	102	102	101

Quarterly basis

	2013-14		2014-15
Particulars	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1 (Calculated on basis of April 2014 data)
Employment	100	101	100

29. Productivity (Indexed):

It appears that the productivity of the DI has suffered significantly, which prima facie arises out of the fact that the level of employment has been maintained despite steep fall in production and domestic sales of the DI, as per the tables below.

Table-I(monthly basis)

Particulars	Dec '13	Jan '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14
Productivity (MT per day)	100	70	43	70	33

Table-2 (Quarterly basis)

	2013-14		2014-15
Particulars	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1 (Calculated on basis of April 2014 data)
Productivity (MT per Day)	72	55	31

30. PROFIT/LOSS:

The DI had provided the figure for profitability till Dec'13 for 2013-14 at the time of issuing Notice of Initiation. In order to analyse the change in profitability situation of the DI after Dec'13, i.e. for the period from Jan'14 till Apr'14, it is found that month wise Profit / Loss figures are not available with the DI as it is not maintained in that order. However, they have provided annual figure for complete 2013-14(till Mar'14), duly certified from the chartered accountant as they are yet to declare their Financial closing for FY 2013-14. From the data submitted, it is seen that the profitability of the DI has further worsened in the last quarter of 2013-14, which is shown in the table below:

Financial Year	Profit and Loss (in Rs./MTS) indexed.
2010-11	100
2011-12	-266
2012-13	-2796
2013-14 (till Dec'13)	-1696
2013-14	-2232

31. Other Factors:**31.1 Import in relation to Demand:**

During the period December 2013 to April 2014, the percentage of import in relation to total demand has increased from 72% in December, 2013 to 80 % in April 2014, which on indexed scale increased from 100 in Dec'13 to 111 in Apr'14 as seen from the table below:

Particulars	Dec '13	Jan '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14
Imports (MT)	4304	4,605	5,942	7,629	6,402
Total Demand (DI sale+Other sale+Imports)	5988	7390	7012	9402	7985
Imports as a % of Demand	72	62	85	81	80
Trend	100	86	118	113	111

31.2 Considering quarter-wise data, the percentage of import in relation to total demand also shows the same rising trend, i.e., it increased from 70 % in Q3 of 2013-14 to 80 % in Q1 of 2014-15. In terms of indexed points, imports in relation to demand increased from 100 to 109 and then to 114 points during the same period, as per table below:

	2013-14		2014-15
Particulars	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1 (Calculated on basis of April 2014 data)
IMPORTS (MT)	13161	18176	19206
Total Demand (DI sale+Other sale+Imports)	18850	23803	23955
Imports as a % of Demand	70%	76%	80%
Trend	100	109	114

32. Exports:

32.1 It appears from the table below, that during the period Dec'13 to Apr'14, exports of the DI suffered drastically, from 8406 MT in Dec'13 to 2653 MT in Apr'14, which on indexed scale is a decline of 68 percentage points.

Particulars	Dec '13	Jan '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14
Export Quantity DI (MT)	8,406	5,018	3,748	5,933	2,653
Trend	100	60	45	71	32

32.2 The same trend is noticed when the comparison is being done on quarterly basis as per the table below, when the export declined from 19445 MT in Q3 of 2013-14 to 7959 MT in Q1 of 2014-15 (annualized), which is a sharp decline by 59 percentage points on indexed scale.

	2013-14		2014-15
Particulars	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1 (Calculated on basis of April 2014 data)
Export Quantity DI (MT)	19445	14699	7959
Trend	100	76	41

33. Inventory:

There is no inventory during the period Dec'13 to Apr'14. It also appears that the inventory was capitalized in Q2 of 2013-14, after which there is no inventory.

34. Determination of Serious injury and threat thereto:

34.1) On the basis of above analysis, it is noticed that the increased imports of Fatty Alcohols have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic producers of Fatty Alcohols as almost all the factors show a significant overall impairment. This significant overall impairment is clearly discernible in the period taken for analysis for examining existence of critical circumstances for considering imposition of immediate provisional duty, i.e. from Dec'13 to Apr'14 (monthly basis) and Q3 of 2013-14 to Q1 of 2014-15 (annualized) for (quarterly basis). There is a sharp decline in production and sale, with steep decline in productivity. The DI has also accumulated losses in Q4 of 2013-14 which has witnessed very steep surge in imports, both in absolute and relative terms. In fact, the poor performance of the DI in almost all economic parameters on one hand and steep rise in imports on the other, immediately after the period of Notice of Initiation, clearly shows the urgent need for a measure which can arrest this surge in imports, failing which, irreparable damage will be caused to the DI which would be difficult to repair.

34.2) It is also seen that due to lowering of tariff barrier from ASEAN countries (AIFTA), sharp surge in imports have taken place which has already caused serious injury to the DI. However, as per the trends noticed above, this condition is likely to continue and pose grave threat of serious injury for the DI in the times to come as well.

35. Causal Link:

35.1) Rule 5(3)(c) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1977 states the requirement of a causal link between increased imports and alleged injury or threat of serious injury.

35.2) For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated.

35.3) From the analysis above, it is found that both in the monthly as well as quarterly analysis of import and domestic data, imports have surged both in absolute as well as in relation to production. The market share of imports have increased substantially in April'14 from Dec'13 and from Q3 of 2013-14 to Q1 of 2014-15 Annualised whereas the market share of the DI has sharply declined during the same period. This clearly established the causal link between the surge in imports and the serious injury caused to the DI in this case.

35.4) Moreover, during the same period, it is noticed that there is a rise in demand for the PUC which should have had resulted into rise in sales for the DI. But the DI has witnessed loss in domestic sales, whereas the imports have surged, a situation which has further aggravated the already precarious economic condition of the DI. The losses have also increased sharply during the same period, i.e. Q4 of 2013-14, which reflects the critical economic condition of the DI. I therefore, find that if this situation is not addressed on immediate basis, it could lead to a situation which could be difficult to redress/rectify/resurrect.

36. Examination on views of Interested Parties:

While dealing with the request of the DI for provisional imposition of safeguard duty, I have also come across several post Initiation submissions of the Interested parties in which some of them have raised certain issues. Accordingly therefore, the issues raised by the interested parties in their post Initiation submissions in the instant safeguard investigation are also being dealt with in brief, as below:

36.1. No Locus Standi of Petitioner to file application & EOU obligations to be considered

36.1.1) It has been argued by some of the Interested Parties that the petitioner is ineligible to seek protection under the safeguard provisions, for the reason that it is a 100% EOU. In this context, reliance has been placed by them on the decision of the Designated Authority in the case of *Ceftriaxone Disodium Hemiheptahydrate-Sterile from China PR* (Final findings dated July 2, 2008). In terms of the definition of 'domestic industry', under the ADD provisions, producers who are importers or related to the importers or exporters, may be excluded from the scope of "domestic industry". However, in the said finding, the EOU had imported substantial quantities of the article under investigation, and since importers of the PUC are specifically barred under ADD law, therefore it was excluded in that case from the scope of domestic industry. Since no

such exclusion has been provided for, under the safeguard provisions, the contention of Interested parties is therefore, unfounded.

36.1.2.) It has been further contended by the interested parties, that there are restrictions on the quantum of domestic sales that can be made by an EOU. This has been examined. It appears that subject to achievement of positive NFE, there is no restriction on sale of the subject goods in India, by the EOU unit/petitioner. That is to say that there are no restrictions on the sale of domestically manufactured goods in India, as long as a positive NFE is maintained by the EOU unit. The Foreign Trade Policy provides for concessional rate of duty on domestic clearances (upto 50% of the FOB value of exports) of that product. In the present case therefore, entitlement earned on other products can be used for fatty alcohols upto 90% of total FOB value of exports. Beyond the aforesaid limits, sales can be made by the EOU/petitioner on payment of appropriate duties of excise. There is hence, no restriction on the sale of goods manufactured by an EOU in India as long as there is positive NFE. In this context, the DI has placed reliance on paragraph 34 of the findings of the Designated Authority (Anti Dumping) in the case of Vitamin A, in which Piramal Healthcare (100% EOU) was considered to be a domestic industry:

“With regard to domestic industry being 100% EOU and therefore it is ineligible to be domestic industry, it is noted that EOU facility in itself does not adversely affect the status of the Petitioner as “domestic industry”. In fact, it is noted that the clearances made by the Petitioner to the Domestic Tariff Area are not restricted or contingent on the exports of the Product under Consideration and are treated as excise-paid domestic sales and not as imports. Thus, based on the Information available on records of the Designated Authority, the Petitioner accounts for all the production of the subject goods in India and thus constitutes domestic industry within the meaning of the Rules”.

36.1.3) It has further been submitted that an export oriented unit is also a domestic unit and its clearances are not to be considered as imports. In the case of Vikram Ispat Vs Commissioner Of Central Excise reported in 2000 (120) ELT 800 Tri Del.(LB), the Hon'ble Tribunal held that domestic sales made by an EOU are not treated as imports and are liable to be treated as domestic goods. The relevant paragraph (para 16) is excerpted below:

“The Revenue wants to restrict the availment of Modvat credit to the components of additional duty of customs paid under Section 3 of the Customs Tariff Act by bringing the fiction that 100% E. O. U. is a place which is not in India and the sale therefrom within India is akin to import into India. We do not find any substance in this view of the Revenue. The clearance of the goods by 100% E.O.U. are not import in the terms in which it has been defined under Section 2 (23) of the Customs Act, according to which import, with its grammatical and cogent expression means bringing into India from a place outside India. This is also apparent from the fact that when the goods are cleared from 100% E.O.U. to any place in India, central excise duty under Section 3(1) of the Central Excise Act is levied and not the customs duty under the Customs Act. If it is to be regarded as import, then the duty has to be charged under Section 12 of the Customs Act, read with Section 3 of the Customs Tariff Act. The Revenue, it seems is confusing the measure of the tax with the nature of the tax. The nature of the duty levied on the goods from 100% E.O.U. is excise duty and nothing else, whereas for determining the quantum of duty the measure adopted is duty leviable under Customs Act as held by the Supreme Court in many cases referred to above. The method adopted by the law makers in recovering the tax cannot alter its character. Once it is held that the duty paid by the 100% E.O.U. in respect of goods cleared to any place in India is excise duty, the question of dissecting the said duty into different components of basic customs duty, auxiliary duty, additional duty of Customs or any other customs duty does not arise. The proforma of AR-1A on which the reliance was placed by the learned D.R., cannot change the legal position that the duty levied on 100% E.O.U. is a duty of excise and not customs duty”.

36.1.4) In the case of Cosco Blossoms Pvt. Ltd. Vs Commissioner Of Customs reported at 2004 (164) ELT 423 (Tri Del), the Hon'ble Tribunal reiterated that goods cleared by an EOU domestically are treated as domestic goods. The relevant paragraph is excerpted below:

“5. It is well settled 2000 (120) E.L.T. 800 that goods produced in an EOU cannot be treated as imported goods and subjected to customs duty. The duty payable in respect of such goods is the duty of excise under Section 3 of the Central Excise Act, 1944. Therefore, the duty demand made in the impugned order under Section 28 of the Customs Act is not sustainable. Accordingly, we set aside the impugned order and allow the present appeal. However, we make it clear that revenue authorities will be at liberty to demand duty on the imported inputs, if any, used in the production of the cut-flowers in question”.

36.1.5) In view of above therefore, I agree with the contention of the DI that an export oriented unit, is not a unit located outside India and hence forms part of domestic industry, and hence, the contention raised by the interested parties is, therefore, without merit.

37. No surge in imports for some product types:

Most of the interested parties have contended that there is no surge in imports in 2013-14 based on a disaggregated analysis of some product types of the PUC and that the increase in imports is showing a declining trend. It however appears that the claim of the interested parties of such selective analysis of some types of the PUC is of no relevance, and is not permissible under the law. The law provides for analysis of total imports from all sources without any discrimination and it has been

found that the imports of fatty alcohols are at a high level, and continue to increase. Both an end point to end point comparison and an analysis of intervening trends over the monthly and quarterly period, indicate that the imports are increasing in absolute terms and also relative to domestic production. The surge in imports is to be seen for the product under investigation, not grades / types thereof.

38. *No injury to other Indian Producer:*

The argument of one of the Interested Parties that no injury is caused to the other producer, i.e, M/s Godrej Industries, is totally false. The other producer is also facing losses for this product. Most of the observations referred to from the annual report, relate to oleochemical division, and its position in export markets. They have failed to appreciate the condition of this other Industry for the PUC. The position of the other producer in the domestic market for fatty alcohol has worsened during the injury period, falling from 18% to 11%.

39. Critical Circumstances:

39.1 On the basis of analysis of the submissions made by the domestic industry and the injury parameters it is observed that the domestic industry has prayed for immediate imposition of interim safeguard measures. In view of the critical circumstances, they have sought imposition of provisional safeguard measures.

39.2 Rule 9 of Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 notified vide Notification No. 35/97-NT-Customs dated 29.07.1997 prescribes that the Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he/she may record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury. The principles governing investigations have been provided in the Rule 6 of the Customs Tariff. (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules'97, which is independent to Rule 9. The Rule 15 of the Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules'97 provide for refund of differential Safeguard duty in case safeguard duty imposed after conclusions of the investigations is lower than the provisional duty already imposed and collected. The harmonious reading of Rules 6, 9 and 15 of the said Rules leads to a conclusion that the Rules provide for expeditious recommendation of provisional Safeguard duty based on preliminary findings and refund of the differential duty in case it is ascertained that the duty imposed after conclusion of investigation following natural justice as enshrined in the Rule 6 is lower than the provisional Safeguard Duty. However, in critical circumstances any delay in imposition of Provisional Safeguard duty may cause damage which would be difficult to repair.

39.3 Accordingly, it was considered prudent to analyze circumstances to assess whether the same falls in the category of critical circumstances. The sudden surge in imports from January'14 till April'14, as compared to December'13 and the corresponding performance of the domestic industry have been considered in order to determine the existence of critical circumstances, both on monthly (from Dec'13 till Apr'14) as well as quarterly (Q3, of 2013-14 till Q1, of 2014-15 based on Apr'14 annualised) basis.

39.4 The imports have increased till 2013-2014 both from the base year as well as previous year. The same trend of increased imports is noticed in the monthly as well as quarterly analysis done above. The market share, profitability, return on investment, domestic production of domestic industry declined significantly during this period. The condition of the petitioner has worsened considerably during the period Jan'14 to Apr'14, when the imports were at high levels.

39.5 The duties on imports of fatty alcohols from certain sources have been removed with effect from 01.01.2014. Anticipating this reduction, imports declined in the third Quarter. The petitioner was able to retain its customers during this period. In Q4, 2013-2014, after removal of duties of customs, the imports have increased drastically and the condition of domestic industry has further worsened.

39.6 It may be seen that the performance of domestic industry has significantly worsened in the last quarter as compared to the earlier period. The effect of any marginal improvements in Q3 has been totally wiped out in Q4. As a consequence, the domestic industry is facing severe price undercutting, price underselling and price suppression from the imports. Profits of domestic industry have also declined drastically in the last quarter. This clearly indicates that serious injury has been caused and threat of further injury is imminent. The causal link between the imports and injury is also established.

39.7 It is further noticed that with the sharp rise in imports with a corresponding decline in the market share of the DI, coupled with steep decline in productivity and profitability in this case, I am of the view that this situation would lead to irreparable damage to the DI. Therefore, surge in imports and resultant decline in performance of the domestic industry in almost all the parameters, confirm existence of critical circumstances which necessitates imposition of immediate provisional safeguard duty to arrest any further decline. As the situation has gone from bad to worse, it appears that any delay in imposing provisional safeguard duty on the PUC would be detrimental to the health of the DI, because in the trends that have been noticed, the situation may aggravate further, thereby accentuating the crisis.

40. Unforeseen Circumstances:

40.1 It is noted that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement either in Indian Rules on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments or the WTO Agreement on Safeguards which also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments.

40.2 The Appellate Body in Argentina-Footwear (EC case) held that the phrase “Unforeseen Developments” means the developments which were unexpected. ‘Unforeseen developments’ requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been ‘unexpected’. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

40.3 The Appellate Body, in Argentina-Footwear (EC), then held that the requirement of “unforeseen developments” did not establish a separate “condition” for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of “circumstances”

40.4 I find that the applicant has in this context, urged as under that there has been an unprecedented increase in the import of subject goods to India, causing serious and irreparable injury to the domestic industry. It has been argued by some of the Interested Parties that this situation was clearly foreseen as the provisions of the FTA had in-built guidelines for a time bound lowering and eventually elimination of import tariff barrier. I agree with this contention of the interested parties to the extent that the provision of FTA had already envisaged lowering of tariff as well as the reasonable expectation that due to this, imports may increase. However, the extraordinary pace and un-anticipated accelerated surge in imports in the most recent period till Apr’14 due to this lowering/elimination of import tariff has surpassed all legitimate reasoning for increased imports. This unprecedented surge of the PUC during Dec’13 to Apr’14 and from Q3, of 2013-14 to Q1, of 2014-15 by around 46-49 percentage points far outstripped the demand of the PUC in the country (around 33 percentage points), which is clearly an unforeseeable circumstances. Such phenomenal surge in imports, which in any case showed an increasing trend throughout the POI, therefore, appears an unforeseen circumstances

41. Public Interest:

It has been submitted by the DI that the purpose of the safeguard duties is to eliminate injury caused by the surge in imports. As there has been a steep surge in cheap imports into India whereby the rising demand has not led to rising sales by the domestic industry, the domestic industry has suffered. Moreover, steep rise in imports has also led to sharp decline in profitability of the DI to a critical level, so much so that, the losses have almost increased by around 40% in Q4, 2013-14 over Q3, 2013-14. Therefore, there appears to be reasonable and justifiable grounds for taking immediate steps in checking the unabated imports of the PUC in the country, in order to prevent irreparable damage to the DI. As any safeguard duty will not affect the availability of the product to the consumers and will also prevent the decline of the Domestic industry further and help maintain availability of a wider choice to the consumers of the subject goods, I find that imposition of provisional safeguard duty thereby, will be in Public Interest.

42. Adjustment Plan:

The DI has given their adjustment plan in their original application which focuses on positive adjustments to be made in view of an annual growth of around 6% in the demand of the product under consideration. As envisaged therein, in order to counter the cost advantage in procurement of the raw material, i.e. split palm kernel oil, the DI has started the process of setting up of a new green field project for producing oleo-chemicals in Medan, Indonesia, which will become the supply source for intermediate products for Indian operations. As stated, this will support to feed its fatty alcohol plant in Taloja, India, by providing SPKO, which will insulate insulate Indian operation from any frequent changes in export tax on Palm and Palm kernel oil, by one of the exporting countries. I find that the adjustment plan envisaged by the DI for cost saving in the raw material segment to produce the PUC, appears to be a viable adjustment plan.

43. Imports of PUC from other developing countries in year FY 2013-14 (De-Minimis):

From the import data it is seen that the total import of PUC into India from developing nations except Malaysia, Thailand and Indonesia do not exceed 3% individually and 9% collectively. Therefore, the import of product under consideration originating from developing nations except Malaysia, Thailand and Indonesia would not attract safeguards duty in terms of the proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

44. Conclusion:

I find in the present case that critical circumstances are in existence and therefore interim measures are imperative in view of the steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of sudden and steep increase imports of the product under consideration. Therefore, if there is any delay in imposition of provisional safeguard duty, it would cause

irreparable damage to the domestic Industry. Accordingly, immediate imposition of provisional safeguard duty, pending final determination of serious injury and threat of serious injury is warranted in this case.

45. Recommendation:

45.1 In view of the findings above, it is concluded that increased imports of "Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8,C10,C12,C14,C16, and C18 including single, blends and unblended (Not including branched isomers) which includes blends a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18,C-16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14)", i.e., "PUC" into India have caused grave injuries and are threatening to cause serious injuries to the domestic producers of "PUC" and it will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of "PUC" into India in terms of Rule 10 of the Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules'97 read with Article 6 of Agreement on Safeguards. Considering the average cost of production of "PUC" by the domestic producer, after allowing a reasonable return on capital employed, provisional safeguard duty at the rate of 20% (twenty percent) ad-valorem which is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry, is hereby recommended for 200 days to be imposed on " Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C8,C10,C12,C14,C16, and C18 including single, blends and unblended (Not including branched isomers) which includes blends a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18,C-16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14)" being imported falling under sub-heading 38237010, 38237020, 38237040, 38237090 and 29051700 (only indicative in nature) of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975.

45.2 As the imports from developing nations except Malaysia, Thailand and Indonesia do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except Malaysia, Thailand and Indonesia, will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

46. Further Process:

- I. The information provided by various parties may be subjected to verification where necessary, for which they will be informed separately.
- II. A public hearing will be held in due course before making a final determination, for which the date will be informed separately.

[F.No. D-22011/ 26/2013]

R. K.SINGLA, Director General